



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 6, 2009/आश्विन 14, 1931

No. 573]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2009/ASVINA 14, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2009

विषय : चीन जन. गण. से भारत में हुए सोडा-ऐश के आयातों से संबंधित रक्षोपाय शुल्क संबंधी जाँच—अंतिम जाँच परिणाम ।

सा.का.नि. 725(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

1. चीन जन.गण. से संबंधित आयातों के कारण हुई बाजार विकृति या बाजार विकृति के उत्पन्न हुए खतरे से सोडा-ऐश के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के लिए चीन से भारत में हुए सोडा ऐश के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), तीसरा तल, पंकज चैम्बर्स, प्रीत बिहार कर्मशियल कॉम्प्लैक्स, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा सीमा-शुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है, सीमा-शुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के नियम 6 के अंतर्गत चीन जन.गण. से भारत में हुए सोडा ऐश के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरू करने की सूचना दिनांक 16 जनवरी, 2009 को जारी की गई थी और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

2. सूचना की एक प्रति नई दिल्ली स्थित दूतावास के जरिए चीन जन.गण. की सरकार को भेजी गई थी। सूचना की एक प्रति नीचे सूचीबद्ध समस्त ज्ञात हितवद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी :—

घरेलू उत्पादक

1. टाटा कैमिकल्स लि.,
लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पू.)
मुम्बई-400059
2. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.,
बिरला सागर, पोरबन्दर-360576,
गुजरात

3. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि.
बी-38, इंस्टीट्यूशनल एरिया
सेक्टर-1, नोएडा-201301
4. डीसीडब्ल्यू लि.
“ निर्मल ”, तीसरा तल
नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
5. निरमा लि.
एनसीसी कार्यालय
कृष्णानगर
वाघवाड़ी रोड
भावनगर-364002, गुजरात

अन्य भारतीय उत्पादक

1. तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.
ईस्ट कोस्ट सेंटर
534, अन्नासलाई
टेनामपेट, चेन्नई-600018

आयातक

1. गुजरात गार्जियन लि.
ग्राम-कोंढ
वालिया रोड
प्लांट राज्य राजमार्ग सं. 13
अंकलेश्वर, भरुच-393001
2. फ्लोट ग्लास इंडिया लि.
टी-7, एमआईडीसी
इंडस्ट्रियल एरिया
तलोजा, महाराष्ट्र
3. अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि.
अलेम्बिक रोड
बड़ौदा (वड़ोदरा)
गुजरात
4. दीपक नाइट्राइट लि.
नांदेसारी,
4/12 कैमिकल कॉम्प्लेक्स
जीआईडीसी, नांदेसारी,
बड़ौदा (वड़ोदरा)
गुजरात

5. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लि.
रिशरा, पश्चिम बंगाल
6. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि.
दक्षिणा बिल्डिंग
8वाँ तल, प्लॉट सं. 2
सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर
नवी मुंबई
7. प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजिन एंड हेल्थ केयर
मंडी दीप प्लांट एल एंड सी-विनिर्माण
प्लॉट सं. 182, मंडी दीप
मध्य प्रदेश
8. अलब्राइट मोरारजी एंड पण्डित लि.
अम्बरनाथ, जिला- थाणे
महाराष्ट्र
9. एड्वाटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि., धनाली
ग्राम धनाली
कड़ी जिला, मेहसाना
गुजरात
10. सेंट गोबेन ग्लास लि.
श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु

निर्यातक

1. शेन्डॉंग हाहुआ ग्रुप
शेन्डॉंग हाहुआ ग्रुप कं. लि.
डेवलप जोन ऑफ हाहुआ
वेईफांग सिटी, शेन्डॉंग-262737
चीन
2. हेबेई टेंगशन सैन्यो अल्कली इंडस्ट्री कं.
नान्यु डेवलपमेंट एरिया
टेंगशन, हेबेई
चीन
पोस्ट कोड- 063305
3. किंघाई अल्कली प्लांट (जेजियांग ग्लास)
चीन का किंघाई दिल्ली म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल पार्क
जिप-817000

4. तियान्जिन सोडा ऐश पार्क
संख्या 87, जिन्हुआ रोड
टंग्गु, जिला तियान्जिन
चीन
5. जिन्शान कैमिकल कं.
हेनान प्रोविंस में चीन की जेंगजोउ सिटी
जेंगजोउ सिटी, फुशोशान स्ट्रीट 87, चीन
3. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों एवं आयातकों तथा निर्यातकों को उसी दिन प्रश्नावलियाँ भी भेजी गयी थीं और उनसे 30 दिनों के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।
4. अनेक पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि उन पर हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विचार किया जाए और समस्त अनुरोध स्वीकार कर लिए गए थे । इसके अलावा, अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार का अनुरोध भी किया गया था और निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी करने की समय-सीमाओं को ध्यान में रखने के बाद सभी मामलों में समय-विस्तार के अनुरोधों की अनुमति दी गई थी और तदनुसार उन्हें सूचित किया गया था । समस्त हितबद्ध पक्षकारों के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

 - i. चीन जन. गण. का दूतावास, 50 डी, शांति पथ, नई दिल्ली
 - ii. अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), तीसरा तल, पंकज चैम्बर्स, प्रीत विहार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विकास मार्ग, दिल्ली-92
 - iii. टीपीएम सॉलिसिटर्स एंड कन्सल्टेंट्स, के-3/ए, साकेत, नई दिल्ली
 - iv. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि., बी-38, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-1, नोएडा-201301
 - v. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि., बिरला सागर, पोरबन्दर-360576, गुजरात
 - vi. टाटा कैमिकल्स लि., लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पू.), मुंबई-400059
 - vii. डीसीडब्ल्यू लि., “ निर्मल ”, तीसरा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
 - viii. निरमा लि., एनसीसी कार्यालय, कृष्णानगर, वाघवाडी रोड, भावनगर-364002, गुजरात
 - ix. तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., ईस्ट कोस्ट सेंटर, 534, अन्नासलाई, टेनामपेट, चेन्नई-600018
 - x. शेन्डॉंग हाहुआ ग्रुप, शेन्डॉंग हाहुआ ग्रुप कं. लि., डेवलप जोन ऑफ हाहुआ, वेईफांग सिटी, शेन्डॉंग-262737, चीन
 - xi. हेबेई टेंगशन सैन्यो अल्कली इंडस्ट्री कं., न्यु डेवलपमेंट एरिया, टेंगशन, हेबेई, चीन, पोस्ट कोड- 063305
 - xii. किंघाई अल्कली प्लांट (जेजियांग ग्लास), चीन का किंघाई दिल्ली म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल पार्क, जिप-817000
 - xiii. तियान्जिन सोडा ऐश पार्क, संख्या 87, जिन्हुआ रोड, टंग्गु, जिला तियान्जिन, चीन
 - xiv. जिन्शान कैमिकल कं., हेनान प्रोविंस में चीन की जेंगजोउ सिटी, जेंगजोउ सिटी, फुशोशान स्ट्रीट 87, चीन

- xv. गुजरात गार्जियन लि., ग्राम-कोंढ, वालिया रोड, प्लांट राज्य राजमार्ग सं. 13, अंकलेश्वर, भरुच-393001
- xvi. फ्लोट ग्लास इंडिया लि., टी-7, एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, तलोजा, महाराष्ट्र
- xvii. अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., अलेम्बिक रोड, बड़ौदा (वडोदरा), गुजरात
- xviii. दीपक नाइट्राइट लि., नांदेसारी, 4/12 कैमिकल कॉम्प्लेक्स, जीआईडीसी, नांदेसारी, बड़ौदा (वडोदरा), गुजरात
- xix. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लि., रिशरा, पश्चिम बंगाल
- xx. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि., दक्षिण बिल्डिंग, 8वाँ तल, प्लॉट सं. 2, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई
- xxi. प्रॉक्टर एंड मैम्बल हाइजिन एंड हेल्थ केयर, मंडी दीप प्लांट एल एंड सी-विनिर्माण, प्लॉट सं. 182, मंडी दीप, मध्य प्रदेश
- xxii. अलब्राइट मोरारजी एंड पण्डित लि., अम्बरनाथ, जिला- थाणे, महाराष्ट्र
- xxiii. एडवाटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि., घनाली, ग्राम घनाली, कडी जिला, मेहसाना, गुजरात
- xxiv. सेंट गोबेन ग्लास लि., श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु
- xxv. यूपी ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स सिंडिकेट, 14 मोनापुरम, निकट गणेश नगर, फिरोजाबाद-283203, उ. प्र.
- xxvi. असाही इंडिया ग्लास लि., 5वाँ तल, टॉक्स-बी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, मेहरीली-गुडगाँव रोड, गुडगाँव-122002 (भारत)
- xxvii. फेना (प्रा.) लि., ए-237, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
- xxviii. डिटर्जेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र), 148, न्यू ओखला इंड. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110020
- xxix. सेंट गोबेन, प्लॉट सं. ए-1, शिपकॉट इंड. पार्क, श्रीपेरुम्बदूर-602105, काँचिपुरम जिला, तमिलनाडु
- xxx. सासी-कैम, 59 व 60, डीएसआईडीसी इंड. कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज-1, नई दिल्ली-110020
- xxxi. श्री यूनिकोन ऑर्गेनिक्स प्रा. लि., बीएस-3, एपीजे, 130, बम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-400023
- xxxii. कैपेक्सिल, वाणिज्य भवन, इंटरनेशनल ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर, 1/1, वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता-700016
- xxxiii. पोल्ताची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंड., आर. पी. कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, 14, बाल गोपालपुरम स्ट्रीट, पोल्ताची-642001
- xxxiv. वसुंधरा रसायन लि., सी-104, एमआईडीसी इंड. एरिया, महेद, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र
- xxxv. स्मोल स्केल डिटर्जेंट एंड सोप मैन्यू. एसोसिएशन, 43, यूरोपियन एस्तेयलम लेन, कोलकाता-700016
- xxxvi. पावर सोप लि., 62-बी, नॉर्थ बोआग रोड, टीनगर, चेन्नई-600017, भारत
- xxxvii. शांतिनाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि., पी-15, कालाकर स्ट्रीट, कोलकाता-700007
- xxxviii. एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लि., एडवांस सर्फैक्टेंट्स इंडिया लि., 511/2/1, गाँव-रजोकरी, नई दिल्ली-110038
- xxxix. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिटर्जेंट मैन्यू. एसोसिएशन, 511/2/1, गाँव-रजोकरी, नई दिल्ली-110038
- xl. एस. कुमार डिटर्जेंट प्रा. लि., प्लॉट नं. 34, सेक्टर-2, इंड. एरिया, पीतमपुर-454775, जिला-धार, मध्यप्रदेश

- xli. एडवांस सर्फेक्ट्स इंडिया लि., 511/2/1, गाँव-रजोकरी, नई दिल्ली-110038
- xlii. ए. आर. सल्फोनेट्स, 9, हेमंत बसु सरणी (20, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट), दूसरा तल, कुक एंड केल्वे बिल्डिंग, कोलकाता-700001
- xliii. साई सल्फोनेट्स, 21, प्रिंसेप स्ट्रीट, दूसरा तल, कोलकाता-700072
- xliv. ए आर स्टेन कैम. प्रा. लि., 9, हेमंत बसु सरणी (20, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट), दूसरा तल, कुक एंड केल्वे बिल्डिंग, कोलकाता-700001
- xliv. हिन्द सिल्केट्स प्रा. लि., 3ए, ऑकलैण्ड प्लेस, पाँचवाँ तल, कोलकाता-700017
- xlvi. टॉरस कैमिकल्स (प्रा.) लि., 318, स्वप्नलोक, 92/93, एस डी रोड, सिकन्द्राबाद-500003, आंध्र प्रदेश, भारत
- xlvi. पी एंड जे क्रेटेकेम (प्रा.) लि. 318, स्वप्नलोक, 92/93, एस डी रोड, सिकन्द्राबाद-500003, आंध्र प्रदेश, भारत
- xlvi. किशोर सन्स डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा. लि., 15-9-469, महबूबगंज रोड, हैदराबाद-500012
- xlix. गोपाल एजेंसिज, गोण्डल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट-360004
- 1. जे. जे. पटेल इंड., गोण्डल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट-360004
- li. श्री राम भरत कैमिकल्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स (प्रा.) लि., 1/56, संजय गाँधी नगर, नोचीपलायम रोड, 46, पोधुर गाँव, इरोड-638002
- lii. इंडियन कैमिकल मर्चेन्ट्स एंड मैनु. एसोसिएशन, 4, इंडिया एकसचेंज प्लेस, कोलकाता-700001
- liii. अध्यक्ष, बल्क ड्रग मैनु. एसोसिएशन (इंडिया), सी-25, इंड. एस्टेट, सनतनगर, हैदराबाद-500018
- liv. भारतीय लघु उद्योग परिषद्, 19/2, वनमाली नस्कर रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700060
- lv. ऑल इंडिया ग्लास मैनु. फेडरेशन, 812, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- lvi. क्रिसेंट सिलिकेट, ए-45, गाने खडपोली एमाआईडीसी चिपलुन, जिला-रत्नागिरी-415604
- lvii. गाँधी कैमिकल्स वर्क्स, एफ-41, विछवाल इंड. एरिया, बीकानेर-334006
- lviii. चीन जन. गण. का वाणिज्य मंत्रालय, 2, डॉगचेंग ए स्ट्रीट, बीजिंग, चीन-100731
- lix. मॉडर्न ग्लास इंड., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)
- lx. आदर्श काँच उद्योग (प्रा.) लि., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)
- lxi. एडवांस लैम्प. कम्पोनेंट एंड टेबल वेयर्स प्रा. लि., ई-24, दूसरा तल, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092
- lxii. प्रगति ग्लास प्रा. लि., 111, धामजीशामजी इंड. कॉम्प्लेक्स, 9, एलबीएस कुर्ला (प.), मुम्बई-400070
- lxiii. गोरामल हरिशम लि., 39, नजफगढ़ रोड इंड. एरिया, नई दिल्ली-110015
- lxiv. रोहित सर्फेक्ट्स (प्रा.) लि., 117/एच-2/202, पांडु नगर, कानपुर-05
- lxv. एस्ट्रल ग्लास प्रा. लि., आदिनाथ टॉवर्स “ ए ”, दूसरा तल, नैन्सी कालोनी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सामने, बोरीवली (पू.), मुम्बई-400066
- lxvi. बीडीजे ग्लास इंड प्रा. लि., 1, किड स्ट्रीट, प्लेस कोर्ट, पहला तल, सूट-14ए, कोलकाता-700016

- lxvii. इंडियन ग्लास मैनु, एसोसिएशन, बी-6, शिवालिक, नई दिल्ली-110017
- lxviii. द डाइज एंड कैमिकल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 4 मंदिर स्ट्रीट, कोलकाता-700073
- lxix. हिप्पोलिन लि., “ मधुवन ”, चतुर्थ तल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006
- lxx. द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डाइज एंड कैमिकल्स मर्चेन्ट्स एसो., 16, महाराणाप्रताप सरणी, दूसरा तल, कमरा सं. 5, कोलकाता-700001
- lxxi. अथेना लौह एसो., 808, एल एंड टी, सेक्टर-18-बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075
- lxxii. लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन, बी-6/10, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
- lxxiii. श्री हरि इंड., 47, श्री वीरुमाई मा निवास, शास्त्री नगर स्क्वेयर, नागपुर-440008
- lxxiv. महाराष्ट्र स्मॉल स्केल सोप, डिटर्जेंट एंड कास्मेटिक मैनु एसो., 47, श्री वीरुमाई मा निवास, शास्त्री नगर स्क्वेयर, नागपुर-440008
- lxxv. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंड. लि., 2, रेडक्रॉस प्लेस, कोलकाता-700001
- lxxvi. जगतजीत इंड. लि., प्लॉट सं. 78, सेक्टर-18, इस्टी. एरिया, गुडगाँव-122001
- lxxvii. भारतीय लघु उद्योग परिषद्, 19/2, वनमाली नस्कर रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700060
- lxxviii. पीताम्बर ग्लास वर्क्स, चमेलीबाग, आगरा रोड, फिरोजाबाद-283203
- lxxix. अशोक एनामेल एंड ग्लास वर्क्स प्रा. लि., 34-ए, मेटकॉफ स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता-700013
- lxxx. एडवांस लैम्प कम्पोनेंट एंड टेबल वेयर्स प्रा. लि., ई-24, दूसरा तल, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092
- lxxxi. हैल्डिन ग्लास गुजरात लि., 9, गायत्री कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मित्तल इंड. एस्टेट नं. 5 के पीछे, अँधेरी कुर्ला रोड, मरोल नाका, अँधेरी (पू.), मुम्बई-400059
- lxxxii. एजीआई ग्लासपैक, 2, रेडक्रॉस, कोलकाता-700001
- lxxxiii. पेरामल ग्लास, पेरामल टॉवर, पेनिन्सिला कॉर्पोरेट पार्क गणपतराय कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013
- lxxxiv. गणेश बीड्स इंड., धौलपुरा, इंड. एरिया के निकट, आगरा रोड, फिरोजाबाद-283203
- lxxxv. श्री जगदम्बा इंड., बी-13, इंड. एरिया, फिरोजाबाद-283203
- lxxxvi. एम्पायर इंड. लि., एम्पायर हाउस, 414, सेनापति बापत, लोअर परेल, मुम्बई-400013
- lxxxvii. आदर्श काँच उद्योग (प्रा.) लि., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)
- lxxxviii. मॉडर्न ग्लास इंड., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)
- lxxxix. भारत ग्लास ट्यूब लि., 501, पाँचवाँ तल, एस्ट्रोन टॉवर, सैटेलाइट, अहमदाबाद-380015

5. जाँच की कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी करने के बाद प्रारंभिक जाँच परिणाम 30 जनवरी, 2009 को जारी किए गए थे। चीन जन. गण. से भारत में आयातित और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 283620 के अंतर्गत आने वाले सोडा-ऐश के आयात पर दिनांक 20.04.2009 की अधिसूचना सं. 37/2009-सी.शु. के तहत मूल्यानुसार 20% की दर से दिनांक 20.04.2009 को अनंतिम शुल्क लागू किया गया था। इस अधिसूचना के तहत लगाया गया रक्षोपाय शुल्क जब तक उसे समाप्त, स्थगित या उसमें पूर्व में संशोधन न किया जाए तब तक 5 नवम्बर, 2009 तक लागू किया गया है और उसमें यह दिन भी शामिल है।

6. 23 मार्च, 2009 को एक 'सार्वजनिक सुनवाई' आयोजित की गई थी जिसकी सूचना 25 फरवरी, 2009 को भेजी गई थी। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त सुनवाई में भाग लिया था उन सभी से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित निवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों पर उत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया था। केन्द्र सरकार ने जाँच अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2009 कर दी थी।

7. दूसरी सार्वजनिक सुनवाई 7 अगस्त, 2009 को आयोजित की गई थी जिसकी सूचना 17 जुलाई, 2009 को भेजी गई थी। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त सुनवाई में भाग लिया था उन सभी से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित निवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों पर उत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

8. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोधों में या उत्तरों में व्यक्त किए गए समस्त विचारों की जाँच की गई थी और उन पर उचित निर्धारण करने में ध्यान दिया गया है। चूँकि ऐसे कई हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्होंने अपने उत्तर दायर किए हैं इसलिए उनके तर्कों और उनसे उत्पन्न मुद्दों पर संक्षिप्तता की वजह से हितबद्ध पक्षकार के नाम का विशिष्ट उल्लेख किए बिना कार्रवाई की गई है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों और मौके पर जाकर किया गया था। इसके अलावा, लागत संबंधी आंकड़ों का सत्यापन और लागत लेखाकार द्वारा उसका प्रमाणन भी किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

भारत में घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उत्पादकों ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :

11. यह आवेदन मै. टाटा कैमिकल्स लि., अंधेरी (पू.), मुंबई; मै. गुजरात हेवी कैमिकल्स लि., नोएडा; मै. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि., बिरला सागर, पोरबंदर, गुजरात; मै. डीसीडब्ल्यू लि., नरीमन प्वाइंट, मुंबई और मै. निरमा लि., भावनगर, गुजरात की ओर से भारतीय अल्कली विनिर्माता एसोसिएशन (एएमएआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों द्वारा उठाए गए प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

12. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि भारत में ग्लू से डाई सोडियम कार्बोनेट जिसका लोकप्रिय नाम 'सोडा ऐश' है, के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग के लिए बाजार विकृति हुई है या उसका खतरा उत्पन्न हो गया है। उत्पाद का रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है। सोडा ऐश एक सफेद, दानेदार और जल में घुलनशील सामग्री है। सोडा ऐश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :-

उत्पाद का नाम	एचएसएन अध्याय शीर्ष	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	आईटीसी शीर्ष
सोडा ऐश	2836.20	28362010 28362020 28362090	28362010 28362020 28362090

13. उन्होंने आरोप लगाया है कि कम कीमतों पर आयातों में वृद्धि हो रही है जिससे उन्हें बाजार हिस्सा गँवाना पड़ रहा है।

14. कम कीमत पर ये बढ़े हुए आयात चीन में कुछेक नई परिस्थितियों के कारण हैं जो निम्नानुसार हैं :-

i. अगस्त, 2008 के दौरान जीडीपी में वृद्धि 10.5% रही। अनुमान है कि 2009 के दौरान जीडीपी में वृद्धि घटकर 5-6% रहेगी। इससे चीन में अत्यधिक मात्रा में बेशी क्षमता हो जाएगी।

ii. ओलम्पिक खेलों और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद चीन में औद्योगिक कार्यकलाप में अत्यधिक गिरावट आई है जिससे सोडा ऐश की माँग में भी गिरावट आई है।

iii. सोडा ऐश हेतु माँग का अनुमान जो पहले 10%+/वर्ष लगाया गया था, अब घटकर 5%-6%/वर्ष रह गया है। इससे चीन में माँग में 2 मिलियन मीट्रिक टन/वर्ष की गिरावट आएगी।

iv. सभी निर्यात विशेष रूप से रसायनों/प्लास्टिक/टेक्स्टाइल/खिलौनों आदि के निर्यात जो काफी हद तक अमेरिका और यूरोप पर निर्भर थे, प्रतिकूलतः प्रभावित हुए हैं। परिणामस्वरूप इन बाजारों को सोडा ऐश के निर्यातों में भी कमी आई है जिससे चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक बेशी मात्रा है।

v. सरकार ने ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के उद्धार हेतु सहायता उपायों की घोषणा की थी। इससे कुछेक संयंत्र बंद होने से बच गए जो कि अन्यथा इन उपायों की अनुपस्थिति में बंद हो गए होते।

vi. लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की ही तरह सम्पदा क्षेत्र विशेष रूप से गृह निर्माण क्षेत्र प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है। भू-सम्पदा की कीमतों में गिरावट आ रही है और ग्राहकों की संख्या भी बहुत कम है। इससे सोडा-ऐश हेतु माँग सहित कई उत्पादों की माँग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

vii. गृह निर्माण क्षेत्र में मंदी से सीमेंट, इस्पात और ग्लास जैसे अवसरचना उद्योग प्रभावित हुए हैं।

viii. पिछले दो महीनों में लघु एवं मझोले आकार की 35 फ्लोट ग्लास लाइनें कथित रूप से बंद हो गयीं और अन्य कम उत्पादन दरों पर प्रचालन कर रही हैं। फ्लोट ग्लास के सोडा ऐश का प्रमुख उपभोक्ता होने के कारण इसका परिणाम बड़ी मात्रा में बेशी क्षमता के रूप में हुआ है।

ix. वर्ष 2007-08 में सोडा ऐश उद्योग में क्षमता में वृद्धि अनुमानों के अनुसार है।

x. मध्य 2008 में सात बड़े विनिर्माताओं और लगभग 44 लघु विनिर्माताओं के साथ चीन की क्षमता कथित रूप से 22 मि. मी. टन थी। पिछले 18 महीनों में इसमें 3.5 मि. मी. टन की वृद्धि हो चुकी है (18.5 मि. मी. टन के आगे)। लगभग 5 मि. मी. टन क्षमता उपलब्ध होने की घोषणा है (माँग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर यह साकार या अन्यथा हो सकता है)। वर्ष 2009 और 2010 में चीन की सोडा-ऐश उत्पादन क्षमता के क्रमशः 26 और 28 मि. मी. टन तक पहुँचने की आशा है।

xi. सितम्बर, 2008 में शेन्डॉंग- हाइतेई की क्षमता में 1 मि. मी. टन की वृद्धि हुई है और उसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। एक बार वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू करने के बाद यह कम्पनी बाजार में एक मि. मी. टन सोडा-ऐश भेजेगी।

xii. ओलम्पिक के बाद खेलों के दौरान संभार तंत्र में कमी के कारण अधिक वस्तुसूची के प्रतिकूल प्रभाव के साथ खपत में अत्यधिक गिरावट देखी गयी।

xiii. पूर्वानुमानों के विपरीत खेलों के दौरान कोई सोडा-ऐश संयंत्र बंद नहीं हुआ था। इसके कारण सोडा-ऐश उत्पादकों के पास अधिक मात्रा में वस्तुसूची थी और अब उनके पास स्टॉक की भरमार है। अधिक वस्तुसूची और सतत रिकॉर्ड उत्पादन के कारण वस्तुसूची में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

xiv. चीन में ग्लास उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य संगत हैं।

xv. फ्लोट ग्लास को अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

xvi. सितम्बर-अक्टूबर में इस क्षेत्र में वित्त की भारी कमी के कारण ओलम्पिक खेलों के दौरान बड़ी हुई वस्तुसूची का निपटान नहीं किया जा सका।

xvii. भू-सम्पदा क्षेत्र में 25-30% की गिरावट की प्रवृत्ति है। “कोई ग्राहक” उपलब्ध नहीं है।

xviii. कथित रूप से उच्च वस्तु सूची के कारण 30 फ्लोट ग्लास इकाइयाँ बंद हो गईं और कोई घरेलू माँग नहीं है।

xix. सोडा-ऐश की अत्यधिक माँग जो अब तक बहुत अधिक थी, भी अब कम हो गई है।

xx. मंदी के परिणामस्वरूप डिटर्जेंट की माँग में भी कमी आई है। वर्ष 2008 के दौरान डिटर्जेंट उद्योग में, जिसमें वर्ष 2007 तक + 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही थी, आंशिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

xxi. अल्यूमीनियम सेक्टर में सोडा ऐश की खपत में कमी आने के कारण अल्यूमीनियम उद्योग में सोडा ऐश की माँग में भी कमी आई है।

15. कमतर उत्पादन के बावजूद उनकी वस्तु सूची में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

16. संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण तथा बिक्री से संबंधित लागत का एक बड़ा हिस्सा परिवहन लागत होती है। जहाँ एक ओर सोडा ऐश के भारतीय उत्पादक गुजरात राज्य में अवस्थित हैं (कच्चे माल की उपलब्धता के कारण) वहीं दूसरी ओर बिक्री समग्र भारत में की जानी अपेक्षित होती है जिससे समस्या और विकट हो जाती है। इसके अतिरिक्त संबद्ध वस्तु तुलनात्मक रूप से निम्नतर कीमत उत्पाद है। अतः उत्पाद की बिक्री कीमत की तुलना में प्रति मी. टन उत्पाद की परिवहन लागत के बहुत अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है।
17. उनकी लाभप्रदता में अत्यधिक कमी आई है और उद्योग के समाप्त होने का खतरा आसन्नवर्ती है।
18. भारत सोडा ऐश में आत्मनिर्भर है। माँग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और इस वजह से इस हेतु आयातों की जरूरत नहीं होती है।
19. चीन के निर्यातों से पूर्व में भी भारतीय उत्पादकों को क्षति होती रही है। पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क पर भरोसा किया गया है।
20. चीन के निर्यातकों या आयातकों ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दायर किया है।
21. हितबद्ध पक्षकारों ने समय पर अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया है जो नियमानुसार अनिवार्य है।
22. याचिकाकर्ता ने आंकड़ों के तीन स्रोत-डीजीसीआई एंड एस, आईबीआईएस एवं चीन का सीमाशुल्क उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, मूल्यांकन निदेशालय के आंकड़े भी महानिदेशक के लिए उपलब्ध हैं। महानिदेशक तीनों स्रोतों द्वारा सूचित आयातों पर विचार करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा कर सकते हैं।
23. यद्यपि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत को चीन से हुए निर्यात की कीमत वैश्विक कीमत से कम थी तथापि अप्रैल, 07-सितम्बर, 08 की अवधि के दौरान भारत के लिए कीमतें वैश्विक कीमतों से अधिक रही थीं तथापि यह प्रवृत्ति न केवल अक्टूबर, 08 से पुनः बदली है अपितु नवम्बर एवं दिसम्बर, 08 में कीमत में भी काफी अंतर रहा है। परिणामतः जहाँ अन्य वैश्विक बाजारों को होने वाले निर्यातों में अगस्त, 08 से तेजी से गिरावट आई है वहीं भारत को हुए निर्यातों में भारी वृद्धि हुई है।
24. यद्यपि सितम्बर, 08 तक चीन से हुए आयात की कीमत अन्य देशों से हुए आयात की कीमत से अधिक रही थी तथापि, अक्टू., 08 के दौरान यह प्रवृत्ति बदल गयी और चीन से आयात की कीमत अब अन्य देशों से आयात की कीमत से काफी कम है। परिणामतः जहाँ वर्ष 1999-2000 और 2007-08 के बीच तीसरे देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हो रही थी वहीं उसके बाद चीन के आयातों में तेजी से वृद्धि होने और तीसरे देश से आयातों में अत्यधिक गिरावट आने के कारण यह प्रवृत्ति बदल गयी है।
25. अखिल भारतीय उत्पादक वर्तमान जाँच में भाग ले रहे हैं और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

26. उत्पाद के वर्तमान क्षेत्र में लाइट एवं डेन्स सोडा ऐश दोनों को शामिल किया गया है। दोनों का चीन से आयात किया जा रहा है और घरेलू उद्योग और दोनों की आपूर्ति की जा रही है।

27. सोडा ऐश प्रमुख ब्रांडों के 3-5% तक के लोकप्रिय कम कीमत बैंडों हेतु डिटर्जेंट की बिक्री कीमत के लगभग 12-15% पर हर जगह उपलब्ध है। ग्लास की परिवर्ती लागत का लगभग 40% सोडा ऐश होता है।

28. आयातों में समग्र रूप में और कुल आयातों, घरेलू उत्पादन एवं घरेलू खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

29. वर्तमान वैश्विक मंदी शुरू होने के कारण चीन के उत्पादकों के समक्ष एक ओर संवर्धित क्षमताओं और दूसरी ओर चीन एवं वैश्विक माँग में कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है। चीन में सोडा ऐश की घरेलू माँग में कमी, चीन से वैश्विक निर्यातों में गिरावट, घरेलू एवं विदेश दोनों में कीमतों में अत्यधिक कमी, चीन में नई क्षमताओं की स्थापना, मौजूदा उत्पादकों द्वारा घरेलू माँग में आनुपातिक वृद्धि के बिना और मौजूदा बेशी क्षमताओं के बावजूद चीन में क्षमता संवर्धन स्पष्ट तौर पर ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से संवर्धित आयात हुए हैं।

30. भारत को मात्राओं में हुई बेतहाशा वृद्धि एकमात्र वजह है जिसके कारण चीन के आपूर्तिकर्ताओं पर माँग के भारी दबाव के कारण उनके द्वारा समान रूप से घातक और विशिष्ट रूप से लक्षित कीमत में कमी (भारतीय बाजार में) की गई है।

31. अगस्त, 2008-दिसम्बर, 08 की अवधि के दौरान “शेष विश्व” को चीन की निर्यात कीमत में 16% तक की गिरावट आई है जबकि भारत के मामले में यह गिरावट अत्यधिक 37% की है।

32. घरेलू सोडा ऐश तथा आयात कीमत में भारी कीमत अंतर से छोटे उपभोक्ता भी आयातित सोडा ऐश की ओर प्रेरित हो रहे हैं।

33. गंभीर क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

34. चीन के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है।

35. आयातों में मौजूदा वृद्धि से पूर्व घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हो रहा था। तथापि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, बिक्री कीमत, रोजगार, लाभप्रदता, बाजार हिस्से, निवेश पर आय, वृद्धि आदि के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

36. इसके अलावा, चीन से संवर्धित आयातों के कारण बाजार विकृति का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस बात की स्पष्ट तौर पर पुष्टि आयातों में वृद्धि दर, घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर, चीन के उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं जैसे मापदण्डों से होती है। इसके अलावा, अंतरिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी खतरा जारी है जिसकी वजह यह है कि चीन के उत्पादक पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमताओं का सामना कर रहे हैं।

37. जनवरी-जून, 09 की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में मामूली सुधार आया है। तथापि, 20% का रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद जुलाई-सितम्बर, 09 में निष्पादन में पुनः तेजी से गिरावट आई है।

38. सोडा ऐश उद्योग में कुछेक चक्रीय विशेषताएँ होती हैं क्योंकि उत्पादन और बिक्री में मानसून के बाद और मार्च तक वृद्धि होती है और तत्पश्चात् मानसून तक गिरावट आती है। इस प्रवृत्ति की आसानी से पुष्टि अप्रैल, 05 से हाल की अवधि तक के माह-वार आंकड़ों से की जा सकती है। तथापि, वर्ष 2008 के मानसून के बाद बिक्री मात्रा में हुई वृद्धि काफी कम रही थी और उसके बाद वर्ष 2009 के मानसून तक बिक्री मात्रा में गिरावट पूर्ववर्ती अवधि से काफी अधिक रही थी जिसका मुख्य कारण संवर्धित आयात हैं।

39. घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। संवर्धित आयातों से इतर अन्य कारकों अर्थात् अन्य देशों से हुए आयात, खपत की पद्धति में परिवर्तन, विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास, निर्यात निष्पादन आदि से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, चीन से हुए आयातों में अत्यधिक वृद्धि, चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि और परिणामतः घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, सितम्बर, 08 के बाद की अवधि में प्रचलित दरों की तुलना में कम दरों पर हुई बिक्री में वृद्धि तथा पूर्व में प्रचलित दरों से अधिक पर मार्च, 09 के बाद बिक्री में आई गिरावट से स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है।

40. रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में है।

41. रक्षोपाय शुल्क लागू किए जाने के बाद भी आयातों में वृद्धि या उनकी उच्च मात्रा से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि रक्षोपाय शुल्क की वर्तमान राशि अत्यधिक अपर्याप्त है।

चीन की सरकार और निर्यातकों के विचार

42. चीन की सरकार, चाइना सोडा इंड. एसो. (सीआईएसए), चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड कैमिकल्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स (सीसीसीएमसी) ने अपने परामर्शदाता तथा अन्यो के जरिए निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

43. कोई जाँच शुरू करने से पूर्व सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के अनुसार परामर्श किए जाने चाहिए थे। उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि यह जाँच डब्ल्यूटीओ में चीन के शामिल होने संबंधी प्रोटोकॉल (सीएपी) के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत निर्धारित परिबर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय (टीपीएसएसएम) लागू करने के लिए है इसलिए सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के तहत पूर्व परामर्श अपेक्षित है। अनुच्छेद 16.1 निम्नानुसार है :

16. परिबर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र

1. ऐसे मामलों में जिनमें चीन के मूल के उत्पादों का डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य के भू-भाग में आयात ऐसी संवर्धित मात्रा में या ऐसी स्थितियों में किया जा रहा है जिससे समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार विकृति उत्पन्न हो गयी है या उसका खतरा उत्पन्न हो गया है, इस प्रकार से प्रभावित डब्ल्यूटीओ सदस्य पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान प्राप्त करने की दृष्टि से चीन के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है जिसमें यह भी

शामिल है कि क्या प्रभावित डब्ल्यूटीओ सदस्य को रक्षोपाय करार के अंतर्गत उपाय लागू करने की पहल करनी चाहिए। इस प्रकार के किसी अनुरोध को रक्षोपाय समिति को तुरंत अधिसूचित किया जाएगा।”

44. तथापि, चीन की सरकार को यह नोट करते हुए खेद है कि जाँचकर्ता प्राधिकारी जाँच की शुरुआत से पूर्व परामर्श का ऐसा अवसर प्रदान करने में विफल रहे हैं। जाँच की शुरुआत से पूर्व से लेकर आज की तारीख तक (प्रारंभिक जाँच परिणामों के अनुमोदन के बाद भी) चीन की सरकार को उचित माध्यम से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। चीन की सरकार की राय में यह न केवल डब्ल्यूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, अपितु जाँचकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किए जाने वाले दायित्वों के भी प्रतिकूल है। परिणामतः इससे चीन की सरकार अपने अधिकारों से सर्वथा वंचित हुई है।

45. सीएपी के अनुच्छेद 16.1 में उल्लिखित “पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान प्राप्त करने की दृष्टि से जिसमें यह भी शामिल है कि क्या प्रभावित डब्ल्यूटीओ सदस्य को रक्षोपाय करार के अंतर्गत उपाय लागू करने की पहल करनी चाहिए” शब्दों का स्पष्ट तात्पर्य यह निकलता है कि पूर्व परामर्श के बिना कोई जाँच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी।

46. इस विशेष मामले में भारत ने सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत चीन के साथ परामर्श की माँग नहीं की थी। डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य के रूप में डब्ल्यूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना होता है और कोई जाँच करते समय लिए जाने वाले दायित्वों की किसी भी रूप में अनदेखी नहीं की जाएगी या उनमें कमी नहीं की जाएगी। चूँकि चीन की सरकार को सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत परामर्श का कोई अवसर नहीं दिया गया है इसलिए टीपीएसएसएम जाँच तुरंत समाप्त कर दी जानी चाहिए।

47. उन्होंने ने यह भी दलील दी है कि संवर्धित आयातों का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे बाजार विकृति आई हो या बाजार विकृति का खतरा उत्पन्न हो गया हो।

48. नए आंकड़ों को शामिल कर जाँच अवधि को बदला गया है जो सही नहीं है।

49. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा आयातों में हुई तेजी से वृद्धि का आरोप लगाए जाने का संबंध है, जिन आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता यह आरोप लगा रहा है वे आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने पण्य वस्तु के संबंधित आयात के आंकड़ों के लिए अनेक स्रोतों अर्थात् आईबीआईएस, डीजीसीआईएस, चीन के सीमाशुल्क तथा उद्योग अनुमानों का उल्लेख किया है। तथापि, इनमें से किसी स्रोत द्वारा चीन से हुए आयातों के बारे में संगत आंकड़ा उपलब्ध नहीं किया गया है।

50. आधार वर्ष और वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में हाल के महीनों में औसत साप्ताहिक उत्पादन औसत मासिक उत्पादन से अधिक रहा है। यह तथ्य कि हाल की अवधि (अर्थात् 1-7 जनवरी, 2009) के लिए सूचीबद्ध उत्पादन में गिरावट आई है, से उद्योग के उत्पादन में समग्र गिरावट का पता नहीं चलता है। वर्ष 2007-08 के लिए घरेलू बिक्री 1,765,322 मी. टन हुई थी। अगले छः माह के लिए आनुपातिक आधार पर इसे 882,661 मी. टन होना चाहिए तथापि, अगले छः माह अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान वास्तविक घरेलू बिक्री काफी अधिक 892,577 मी. टन रही थी। अतः याचिका के अनुसार घरेलू बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्ष 2007-08 के दौरान चीन से 45,771 मी. टन के आयात हुए थे। आनुपातिक आधार पर इसे

अगले छः माह के दौरान 22,886 मी. टन होना चाहिए था। तथापि, अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान आयात 22,907 मी. टन के हुए थे अर्थात् केवल लगभग 21 मी. टन की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, याचिका के अनुबंध 8 में निहित आंकड़ों से यह पता चलता है कि उसमें सूचीबद्ध प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी की प्रति इकाई बिक्री कीमत वर्ष 2007-08 में रही प्रति इकाई कीमत की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 08 की अवधि में बढ़ी है। इसके अलावा, इन कंपनियों में से तीन कंपनियों (अर्थात् निरमा, जीएचसीएल तथा टीसीएल) के लिए कुल बिक्री मात्रा वर्ष 2007-08 की 6 माह की अवधि की तुलना में बढ़ी है। जहाँ तक लाभ का संबंध है, अनुबंध 8 से यह पता चलता है कि पाँच याचिकाकर्ता कंपनियों में से तीन कंपनियों (अर्थात् डीसीडब्ल्यू, जीएचसीएल तथा टीसीएल) को वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2008 में घाटे की स्थिति से उबरने का अवसर मिला। इन तीनों कंपनियों का कुल मिलाकर हिस्सा याचिकाकर्ता कंपनियों की कुल बिक्री मात्रा का लगभग 70% बनता है। यह पता लगा पाना कठिन है कि याचिकाकर्ता किस प्रकार सद्भावना में लाभों में गिरावट आने के ऐसे दावे कर सकता है जबकि अधिकांश घरेलू उद्योग के लाभों में वृद्धि हो रही है।

51. याचिका में हमारे द्वारा किए गए अन्य दावों अर्थात् अमरीका तथा ईयू को हुए निर्यातों में गिरावट; ओलम्पिक खेलों के बाद सोडा ऐश की चीन की माँग में गिरावट; पीआरसी सरकार की कार्रवाई जिसकी वजह से चीन में सोडा ऐश के संयंत्र बंद होने से बच गए हैं का समर्थन किसी साक्ष्य द्वारा नहीं किया गया है।

52. यह याचिका पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है और इस प्रकार जांच की शुरुआत में नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। यदि नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो महानिदेशक के पास जांच शुरू करने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। इस प्रकार, यह याचिका क्षेत्राधिकार रहित है और ऐसी किसी शुरुआत पर कोई उपाय लागू नहीं किया जा सकता।

53. महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम 13 फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक में स्थायी रक्षोपाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। स्थायी बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया था कि प्रारंभिक जांच परिणाम में शुल्क लगाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है और यह कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को अन्य अनेक मुद्दों की जांच करनी चाहिए। यह जानकारी में आया है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में मुद्दों की आगे जांच की और स्थायी बोर्ड को बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। परवर्ती रिपोर्ट के आधार पर स्थायी बोर्ड ने 20% की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुमोदन प्रदान किया। चूँकि संशोधित प्रारंभिक जांच परिणामों की कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी इसलिए कोई अनंतिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

54. इनके अलावा, प्रारंभिक जांच परिणामों में सूचीबद्ध आयात आंकड़े और उत्पादन आंकड़े याचिका में उल्लिखित आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

55. कोई बाजार विकृति नहीं आई है क्योंकि बिक्री में गिरावट मामूली है।

56. अन्य देशों से भारी मात्रा में आयात हुए हैं जहाँ आवेदक उद्योगों के पास विनिर्माण सुविधाएँ हैं। इस प्रकार, वे टीपीएसएसएम का उपयोग एक ऐसे उपाय के रूप में कर रहे हैं जिससे भारतीय प्रचालनों की रक्षा न हो परंतु केन्या या रोमानिया से निर्यात हेतु मुक्त बाजार सुनिश्चित हो सकें। टीपीएसएसएम का उद्देश्य ऐसे प्रयोजनों की सिद्धि करना नहीं है।

57. बाजार विकृति का अनुमान लगाते हुए यह बाजार विकृति आयातों के कारण नहीं आई है ।
58. उद्योगों द्वारा सोडा ऐश का उपयोग विभिन्न तैयार उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है । कोई रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से अंतिम प्रयोक्ताओं और अनेक उत्पादों के उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।
59. यह स्पष्ट नहीं है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में दिए गए 31% के आंकड़े का आधार क्या है । उदाहरणार्थ यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस मार्जिन की गणना कारखाना स्तर पर किसी तुलना पर आधारित है अथवा क्या इसकी गणना चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों पर आधारित पहुँच मूल्य का उपयोग कर की गई थी । चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों में सामान्यतः चीन में एफओबी कीमत दी जाती है ।
60. जहाँ तक महानिदेशक द्वारा बीओएस को भेजे गए पत्र का संबंध है, यूरोपीय आयोग के निर्णय पर भरोसा करना सही नहीं है क्योंकि इससे उनके दावे का कोई समर्थन नहीं होता है । प्रथमतः इस निर्णय को व्यापार कानूनविदों में अच्छा नहीं माना जाता है । यह सच है कि यूरोपीय आयोग का निर्णय राजनीतिक कारणों से लिया गया था और यह इस्पात के आयातों पर अमरीका की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के विरुद्ध बदला लेने के लिए लिया गया था ।

आयातकों/प्रयोक्ता उद्योगों के विचार

61. डिटर्जेंट मैन्यू. एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र) पंजी./ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिटर्जेंट मैन्यू. (एआईएफडीएम) ने अपने काउंसिल के जरिए निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
62. प्रारंभिक आपत्ति : घरेलू उद्योग 7 अगस्त, 2009 को हुई सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पूर्णतः नए आंकड़ों के साथ आया था । इसका पूर्णतः विरोध किया गया था क्योंकि हितबद्ध पक्षकार यह समझने में असमर्थ हैं कि घरेलू उद्योग का दावा क्या है । किसी रक्षोपाय जांच को सतत जांच नहीं कहा जा सकता । महानिदेशक को क्षति अवधि निर्धारित करनी चाहिए ताकि समस्त हितबद्ध पक्षकार उस पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकें । अनुरोध है कि जांच की शुरुआत के बाद की अवधि से संबंधित किसी आंकड़े पर अंतिम जांच परिणाम निकालने में महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए । इस संबंध में, कार्बन ब्लैक से संबंधित रक्षोपाय जांच में महानिदेशक (रक्षोपाय) के पूर्ववर्ती निर्णय-अंतिम जांच परिणाम, 1 जुलाई, 1998 का भी हवाला दिया जाता है जिसमें महानिदेशक ने जांच अवधि का विस्तार नहीं किया था ।
63. याचिका में कमियाँ : जहाँ तक आयातों में तेजी से वृद्धि होने के बारे में याचिकाकर्ता के आरोप का संबंध है, याचिकाकर्ता द्वारा आंकड़ों के जिस स्रोत के आधार पर यह आरोप लगाया गया है वह स्पष्ट नहीं है । याचिकाकर्ता ने पण्य वस्तु के संबंधित आयात के आंकड़ों के लिए अनेक स्रोतों अर्थात् आईबीआईएस, लीजीसीआईएस, चीन के सीमाशुल्क तथा उद्योग अनुमानों का उल्लेख किया है । तथापि, इनमें से किसी स्रोत द्वारा चीन से हुए आयातों के बारे में संगत आंकड़ा उपलब्ध नहीं किया गया है । तदनुसार, सादर निवेदन है कि महानिदेशक को अपने अंतिम निर्धारण पर पहुँचने में संबद्ध पण्य वस्तु आयात के आंकड़ों के एक संगत स्रोत पर भरोसा करना चाहिए । इसके अलावा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग(1) में “ भारत में संवर्धित आयात ” का उल्लेख है न कि “ चीन से निर्यात ” का । जब धारा में “ भारत में आयात ” का उल्लेख है, तो कोई भी व्यक्ति निर्धारण करने के लिए चीन से हुए निर्यातों को आधार नहीं मान सकता । इस

प्रकार, चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों जो चीन से हुए निर्यातों और भारत में हुए आयातों के सिवाय और कुछ नहीं है, पर महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।

64. याचिका में बाजार विकृति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है : आधार वर्ष और वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में हाल के महीनों में औसत साप्ताहिक उत्पादन औसत मासिक उत्पादन से अधिक रहा है। यह तथ्य कि हाल की अवधि (अर्थात् 1-7 जनवरी, 2009) के लिए सूचीबद्ध उत्पादन में गिरावट आई है, से उद्योग के उत्पादन में समग्र गिरावट का पता नहीं चलता है। वर्ष 2007-08 के लिए घरेलू बिक्री 1,765,322 मी. टन हुई थी। अगले छः माह के लिए आनुपातिक आधार पर इसे 882,661 मी. टन होना चाहिए तथापि, अगले छः माह अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान वास्तविक घरेलू बिक्री काफी अधिक 892,577 मी. टन रही थी। अतः याचिका के अनुसार घरेलू बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्ष 2007-08 के दौरान चीन से 45,771 मी. टन के आयात हुए थे। आनुपातिक आधार पर इसे अगले छः माह के दौरान 22,886 मी. टन होना चाहिए था। तथापि, अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान आयात 22,907 मी. टन के हुए थे अर्थात् केवल लगभग 21 मी. टन की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, याचिका के अनुबंध 8 में निहित आंकड़ों से यह पता चलता है कि उसमें सूचीबद्ध प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी की प्रति इकाई बिक्री कीमत वर्ष 2007-08 में रही प्रति इकाई कीमत की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 08 की अवधि में बढ़ी है। इसके अलावा, इन कंपनियों में से तीन कंपनियों (अर्थात् निरमा, जीएचसीएल तथा टीसीएल) के लिए कुल बिक्री मात्रा वर्ष 2007-08 की 6 माह की अवधि की तुलना में बढ़ी है। जहाँ तक लाभ का संबंध है, अनुबंध 8 से यह पता चलता है कि पाँच याचिकाकर्ता कंपनियों में से तीन कंपनियों (अर्थात् डीसीडब्ल्यू, जीएचसीएल तथा टीसीएल) को वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2008 में घाटे की स्थिति से उबरने का अवसर मिला। इन तीनों कंपनियों का कुल मिलाकर हिस्सा याचिकाकर्ता कंपनियों की कुल बिक्री मात्रा का लगभग 70% बनता है। यह पता लगा पाना कठिन है कि याचिकाकर्ता किस प्रकार सद्भावना में लाभों में गिरावट आने के ऐसे दावे कर सकता है जबकि अधिकांश घरेलू उद्योग के लाभों में वृद्धि हो रही है।

65. याचिका में उल्लिखित अन्य दावे भी किसी साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं : याचिकाकर्ता ने आगे ये आरोप लगाए हैं - चीन के उत्पादकों में सोडा ऐश की मालसूची में वृद्धि जिसकी परिणति चीन में आर्थिक मंदी और अमरीका तथा ईयू को होने वाली निर्यातों में गिरावट के रूप में आई है; ओलम्पिक खेलों के बाद सोडा ऐश की चीन की माँग में गिरावट; पीआरसी सरकार की कार्रवाई जिससे चीन में सोडा ऐश के संयंत्र बंद होने से बच गए हैं; वर्ष 2007-08 में चीन में सोडा ऐश की क्षमता में “वृद्धि” हुई है और वर्ष 2008 के मध्य में चीन की क्षमता “कथित रूप से” 22 मि. मी. टन है; मंदी एवं इसके परिणामस्वरूप, चीन के फ्लोट ग्लास, डिटर्जेंट तथा अल्यूमीनियम उद्योगों आदि सोडा ऐश की माँग में गिरावट। इन सबके संबंध में इन कोरे दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

66. याचिका नितांत त्रुटिपूर्ण है और इस प्रकार, जाँच की शुरुआत में नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है : उपर्युक्तानुसार याचिका में अनेक त्रुटियों के मद्देनजर याचिका नितांत त्रुटिपूर्ण है और इसमें नियम 5(2) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। तदनुसार, महानिदेशक, रक्षोपाय ने जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को कभी संतुष्ट नहीं किया होगा। अतः जाँच की शुरुआत में ही नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। यदि नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो महानिदेशक के पास जाँच की शुरुआत करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रहता है। इस प्रकार, जाँच

की शुरुआत क्षेत्राधिकार रहित है और ऐसी किसी जांच के अनुसरण में कोई उपाय नहीं लगाया जा सकता ।

67. जांच की शुरुआत में प्रक्रियागत चूकें : शामिल होने से संबंधित प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 16.1 में स्पष्ट प्रावधान और परामर्श की जरूरत के बारे में सदस्य देशों के बीच साझा समझ होने के बावजूद चीन की सरकार को सरकारी चैनलों के जरिए वर्तमान टीपीएसएस जांच के बारे में सूचित नहीं किया गया है ।

68. इसके अलावा, महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम 13 फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक में स्थायी रक्षोपाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे । स्थायी बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया था कि प्रारंभिक जांच परिणाम में शुल्क लगाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है और यह कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को अन्य अनेक मुद्दों की जांच करनी चाहिए । यह जानकारी में आया है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में मुद्दों की आगे जांच की और स्थायी बोर्ड को बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । परवर्ती रिपोर्ट के आधार पर स्थायी बोर्ड ने 20% की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुमोदन प्रदान किया । चूंकि संशोधित प्रारंभिक जांच परिणामों की कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी इसलिए कोई अनंतिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता ।

69. इनके अलावा, प्रारंभिक जांच परिणामों में सूचीबद्ध आयात आंकड़े और उत्पादन आंकड़े याचिका में उल्लिखित आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं ।

70. कोई बाजार विकृति नहीं आई है क्योंकि बिक्री में गिरावट मामूली है ।

71. घरेलू उत्पादकों में से दो उत्पादकों के पास विदेशों में विनिर्माण सुविधाएँ हैं । टाटा कैमिकल्स ने दिसम्बर, 2005 में केन्या में मगाडी सोडा को अपने अधिकार में ले लिया था । केन्या में केवल एक उत्पादक है । केन्या से हुए आयात चीन से हुए आयातों से काफी अधिक हैं । इसी प्रकार, जीएचसीएल ने वर्ष 2005 में रोमानिया में एससी बेगा उपसम एस-ए को अपने अधिकार में लिया था । रोमानिया से हुए आयात वर्ष 2007-08 तक सबसे अधिक रहे थे । वर्ष 2008-09 के दौरान भी रोमानिया से भारी मात्रा में आयात हुए हैं । ये दोनों घरेलू उत्पादक (अर्थात् टाटा कैमिकल्स एवं जीएचसीएल) भारत को केन्या/रोमानिया से निर्यात करने की अपनी क्षमता सुरक्षित रखना चाहते हैं । यदि इन देशों पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाएगा तो केन्या/रोमानिया उनके आयातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, उन्होंने चीन से हुए आयातों को ही लक्ष्य बनाते हुए टीपीएसएसएम उपाय का चुनाव किया है । चीन के आयातों के एक बार बंद हो जाने पर केन्या/रोमानिया स्थित उनकी संबद्ध कंपनियों से आयात करने में कोई समस्या नहीं होगी । इस प्रकार, उनके द्वारा टीपीएसएसएम का उपयोग अपने भारतीय प्रचालनों की रक्षा करने के उपाय के रूप में नहीं किया जा रहा है अपितु केन्या या रोमानिया से निर्यात हेतु मुक्त बाजार सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है । टीपीएसएसएम का उद्देश्य ऐसे प्रयोजनों की सिद्धि करना नहीं है ।

72. बाजार विकृति का अनुमान लगाते हुए यह बाजार विकृति आयातों के कारण नहीं आई है ।

73. सार्वजनिक हित : सोडा ऐश का उपयोग विभिन्न तैयार उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनेक उद्योगों द्वारा किया जाता है । इनकी व्यापक सूची नीचे दी गई है ।

- i. घरेलू डिटर्जेंट
- ii. साबुन
- iii. सफाई यौगिक
- iv. फ्लोट ग्लास
- v. कंटेनर तथा विशिष्टता काँच
- vi. अनेक प्रकार के भारी एवं औद्योगिक रसायन
- vii. निम्नलिखित में व्यापक उपयोग
- viii. वस्त्र उद्योग
- ix. कागज उद्योग
- x. धात्विक उद्योग
- xi. डिसेलिनेशन संयंत्र
- xii. जलशोधन
- xiii. रबड़ उद्योग
- xiv. चर्म उद्योग
- xv. अल्यूमीनियम उद्योग
- xvi. सोडा ऐश निम्नलिखित के विनिर्माण में भी एक प्रमुख संघटक है
- xvii. बल्क ड्रग
- xviii. सैक्रीन
- xix. सफोलिन

74. सोडा ऐश के विभिन्न उपयोग होने के कारण यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से अंतिम प्रयोक्ताओं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसकी आगे परिणति निरमा जैसे समेकित उत्पादकों के लिए अनुचित लाभ के रूप में होगी। चीन से हुए आयातों पर एक बार रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग केन्या और रोमानिया स्थित अपनी संबद्ध कंपनियों से आस्तानी से आयात करेगा और अंतिम प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हित भी ~~लक्षित~~ ~~पर~~ ~~की~~ ~~मूल्यों~~ में वृद्धि करेगा।

75. घरेलू उद्योग की कार्टेल जैसी प्रकृति उसके कीमत व्यवहार से स्पष्ट हो जाती है (याचिकाकर्ता कंपनियाँ एकीकृत कीमत प्रभारित करती हैं)। इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमत पद्धति पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण निकालने या बाजार विकृति या उसके खतरे का निष्कर्ष निकालने में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

76. रक्षोपाय शुल्क की गणना : यह स्पष्ट नहीं है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में दिए गए 31% के आंकड़े का आधार क्या है। उदाहरणार्थ यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस मार्जिन की गणना कारखाना स्तर पर किसी तुलना पर आधारित है अथवा क्या इसकी गणना चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों पर आधारित पहुँच मूल्य का उपयोग कर की गई थी। चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों में सामान्यतः चीन में एफओबी कीमत दी जाती है।

77. जहाँ तक महानिदेशक द्वारा बीओएस को भेजे गए पत्र का संबंध है, यूरोपीय आयोग के निर्णय पर भरोसा करना सही नहीं है क्योंकि इससे उनके दावे का कोई समर्थन नहीं होता है। प्रथमतः इस निर्णय को व्यापार कानूनविदों में अच्छा नहीं माना जाता है। यह सच है कि यूरोपीय

आयोग का निर्णय राजनीतिक कारणों से लिया गया था और यह इस्पात के आयातों पर अमरीका की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के विरुद्ध बदला लेने के लिए लिया गया था।

मै. हिन्दुस्तान लिबरर्स के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

78. कोई रक्षोपाय “दोषरहित सिद्धांत” पर आधारित होता है और इसका उपयोग उन आयातों पर किया जाता है जो निष्पक्ष भाव से किए जाते हैं न कि घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाने की मंशा से। इस प्रकार, बाजार विकृति को सिद्ध करने या रक्षोपाय लागू करने पर विचार करना भी अन्य व्यापार उपचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अर्थ निरूपण यथासंभव यथोचित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि मुक्त व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

79. आवेदक ने अपनी सुविधानुसार आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों पर भरोसा किया है और वह एक स्रोत के आंकड़ों से दूसरे स्रोत डीजीसीआई एंड एस तथा आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से लेकर चीन की सीमाशुल्क तथा “घरेलू अनुमान” द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर इस बदलाव के सुसंगत कारण उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

80. याचिका और प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रयुक्त आंकड़ों के विविध स्रोत हैं।

81. याचिका में दिए गए आंकड़ों में कई विसंगतियाँ हैं। याचिका में प्रदत्त सूचना और प्रारंभिक जांच परिणामों में उल्लिखित सूचना कई स्थानों पर मेल नहीं खाती है।

82. गोपनीयता : याचिका गोपनीयता की आड़ में सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल रही है और याचिका के विभिन्न भाग भी गोपनीय रखते हुए कोई वैध कारण बताए बिना कोरे छोड़ दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, याचिका में यह उल्लेख है कि याचिका के अनुबंध 2 में चीन सहित सोडा ऐश के देश-वार आयात दिए गए हैं। यह आंकड़ा डीजीसीआई एंड एस तथा आईबीआईएस से आवेदकों ने लिया है। अतः यह मानना कठिन है कि उक्त आंकड़ों को गोपनीय क्यों होना चाहिए। इसके अलावा, यह याचिका गोपनीयता की माँग करने का कोई कारण देने में विफल रही है।

83. स्पष्ट “जांच अवधि” उपलब्ध कराने में विफलता : डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार तथा नियमावली में “जांच अवधि” की कोई परिभाषा नहीं है। वस्तुतः जाँच अवधि पद रक्षोपाय करार और नियमावली दोनों में कहीं नहीं पाया जाता है। तथापि, महानिदेशक ने विगत में जाँच अवधि के मुद्दे पर कार्यवाही की है। कार्बन ब्लैक के मामले में जाँच की शुरुआत 5 फरवरी, 1998 को की गई थी और आवेदकों ने सितम्बर, 1998 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, जब आवेदकों ने हाल की घटनाओं के नए साक्ष्य लाने का प्रयास किया तो महानिदेशक ने इस आधार पर आंकड़े स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इस संदर्भ अवधि को बदलना उचित नहीं होगा क्योंकि विभिन्न हितबद्ध पक्षकार इस अवधि के दौरान उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में उत्तर देते हैं। वर्तमान मामले में आवेदकों ने संदर्भ कीमत से बाद अर्थात् वर्ष 2005-06 से सितम्बर, 2008 के नए आंकड़े याचिका, जाँच की शुरुआत, प्रारंभिक जांच परिणाम और हाल में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान शामिल करने की माँग की है। अतः हम महानिदेशक की सुसंगत पद्धति को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक से “जांच अवधि” अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2008 तक सीमित रखने का अनुरोध करते हैं।

84. जाँच की शुरुआत और प्रारंभिक जाँच परिणामों में समस्याएँ : चीन से सोडा ऐश के आयातों की जाँच हेतु जाँच शुरुआत की सूचना 16 जनवरी, 2009 को जारी की गई थी। उक्त सूचना में संबंधित पक्षकारों को 16 फरवरी, 2009 तक अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। तथापि, महानिदेशक ने 30 जनवरी, 2009 को अपने प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए। प्रारंभिक जाँच परिणाम प्रशासनिक कानून के मूलभूत सिद्धांत अर्थात् किसी की भी सुनवाई किए बिना भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए, का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था। इस सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम रामकिशन एवं अन्य (एआईआर 1988 एससी 1301) के मामले में बार-बार स्वीकार किया है। इसके अलावा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन ही नहीं है अपितु नियमों का भी उल्लंघन है। नियम 6 में जाँच को शासित करने वाले सिद्धांत निहित हैं। नियम 6 उपनियम 5 में यह उपबंध है कि महानिदेशक औद्योगिक प्रयोक्ताओं को सुनने का अवसर उपलब्ध करएँगे।

85. आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई : आवेदक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि आयातों में कोई नाटकीय वृद्धि हुई है। याचिका में प्रदत्त आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि आयातों में स्पष्टतः कोई वृद्धि नहीं हुई है। याचिका के पृष्ठ 6 पर दी गई तालिका पर गौर करने से यह पता चलता है कि अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2008 तक आयातों में कोई नाटकीय वृद्धि नहीं हुई है।

86. आवेदकों की बिक्री या बाजार हिस्से में कोई खास गिरावट नहीं : कोई रक्षोपाय तभी लागू किया जा सकता है जब बिक्री या उत्पादन के स्तर में परिवर्तन हुआ हो। याचिका या प्रारंभिक जाँच परिणामों में प्रस्तुत आंकड़ों से अन्यथा पता चलता है कि याचिका के अनुबंध 10 में भारतीय बाजार में माँग और “ माँग में बाजार हिस्से ” का पता चलता है। इस तालिका में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2006-07- अप्रैल-सितम्बर, 2008 तक आवेदकों की बिक्री में स्पष्ट तौर पर लगभग 3% की वृद्धि हुई है। संदर्भ अवधि के दौरान माँग में गिरावट के कारण घरेलू बिक्री में वृद्धि स्पष्ट तौर पर बाजार विकृति का कारक नहीं हो सकती। प्रारंभिक जाँच परिणाम में उल्लिखित बिक्री के आंकड़ों से उसी अवधि के दौरान बिक्री में मामूली गिरावट प्रदर्शित होती है।

87. कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी आने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन आवेदकों की कीमतों में गिरावट नहीं आई है।

88. डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार तथा नियमावली में “ कीमत ” शब्द का भी उल्लेख नहीं है। अतः केवल घरेलू बाजार पर कम कीमतों के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। रक्षोपाय शुल्क उस स्थिति में ही आयातों पर लगाया जाता है जब आयातों में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर कुछेक नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। रक्षोपाय के संबंध में, कीमत कटौती या कम कीमत पर बिक्री का कोई जिक्र नहीं है। अतः विदेशी एवं घरेलू कीमतों के संबंध में सूचना की अनदेखी की जानी चाहिए क्योंकि रक्षोपाय शुल्क लगाने के निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तथापि, पिछले कुछ महीनों में सोडा ऐश की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। कीमतों में यह गिरावट मुख्यतः उन निविष्टियों की कीमतों में गिरावट के कारण आई है जिनका उपयोग सोडा ऐश बनाने में किया जाता है। इस प्रकार, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट आई है तथापि घरेलू उद्योग अपनी कीमत कम करने में विफल रहा है। ऐसा संभवतः इस वजह से हुआ है कि आवेदकों ने तत्स्थानी बाजार में समान निविष्टियों की कीमतों की तुलना में उच्चतम कीमत पर निविष्टियों के लिए दीर्घावधिक संविदाएँ की हैं।

89. क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं : आवेदकों ने दावा किया है कि क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं आई है तथापि, याचिका के अनुबंध 5 के अवलोकन से यह पता चलता है कि अप्रैल, 2006-सितम्बर, 2008 तक क्षमता उपयोग में कोई खास गिरावट नहीं आई है। इसके अलावा वर्ष 2005-06 से 2006-07 तक क्षमता उपयोग में गिरावट को बिक्री या उत्पादन में खास गिरावट के बजाय उत्पादन में तदनुसूची विस्तार के बिना घरेलू उद्योग द्वारा कुल क्षमता में वृद्धि द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

90. रोजगार तथा लाभ एवं हानि : याचिका में आवेदकों को हुए रोजगार के नुकसान के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है परंतु महानिदेशक ने आश्चर्यजनक ढंग से अपने जांच परिणाम की तालिका 9 में इस पहलू पर जांच परिणाम निकाला है कि रोजगार में गिरावट आई है। जहाँ तक लाभप्रदता का संबंध है, याचिका में प्रदत्त कोष्ठक सूचना का हवाला दिए बिना हमारा अनुरोध यह है कि यह सच है कि सबसे बड़े उत्पादक टाटा कैमिकल्स के तीसरी तिमाही के लाभ में 106% की वृद्धि हुई है जो बढ़कर 3495 करोड़ रु. हो गया है। इसी प्रकार, जीएचसीएल की तिमाही के परिणामों से यह पता चलता है कि 9 माह के राजस्व में 20% की वृद्धि हुई जबकि 9 माह के लाभ में 36% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि आयातों और बाजार विकृति के दावे के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

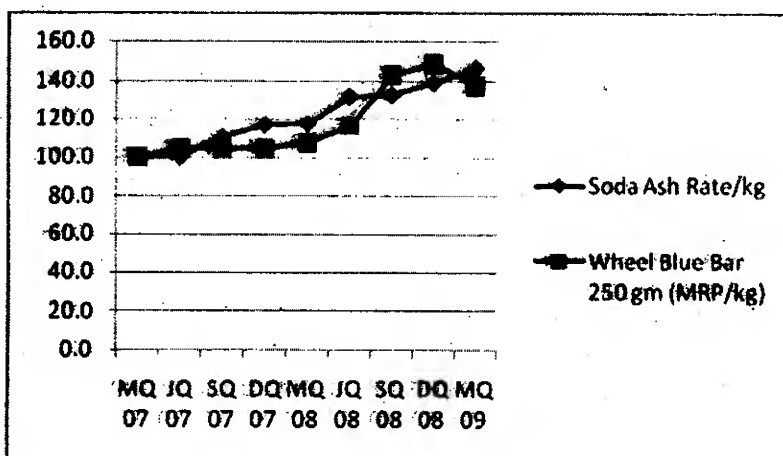
91. कोई कारणात्मक संबंध नहीं : आवेदक यह भी नहीं बता सके हैं कि संवर्धित आयातों और बाजार विकृति के बीच स्पष्ट तौर पर कोई कारणात्मक संबंध है जिसकी वजह यह है कि उपर्युक्तानुसार आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और रिकॉर्ड में यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि आवेदकों के प्रचालन में कोई बाजार विकृति आई है। यदि संदर्भ अवधि के दौरान बाजार विकृति का कोई संकेत था तो अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए सीमा से बाहर कोई निवेश नहीं किया गया होता।

92. जैसाकि ऊपर देखा गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने की कोई शर्त पूरी नहीं होती है आपात परिस्थितियों जिनके तहत उक्त शुल्क लगाया जा सकता है, को न्यायोचित ठहराने के लिए खतरे का दावा वास्तविक और आसन्नवर्ती होना चाहिए। अतः बाजार विकृति या बाजार विकृति के खतरे का कोई मामला नहीं बन सकता।

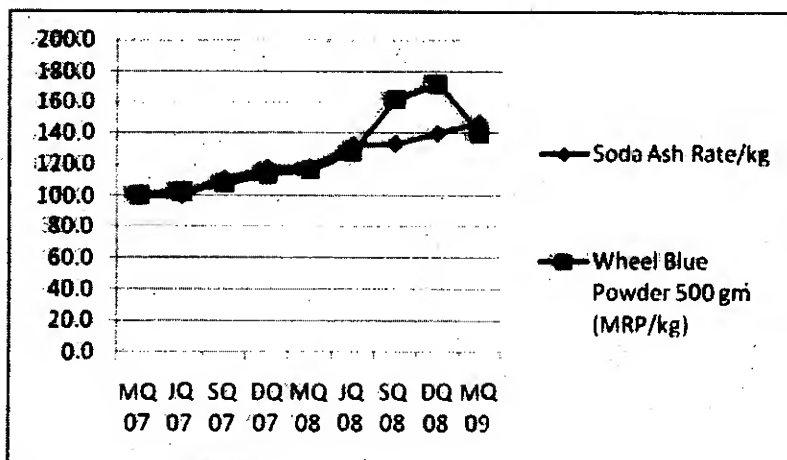
93. शुल्क की गणना : आवेदकों ने चीन से सोडा ऐश के आयातों पर 55% रक्षोपाय शुल्क लगाने की माँग की है जो डब्ल्यूटीओ में भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार 40% की वचनबद्धता दर से स्पष्टतः अधिक है। तथापि, आवेदक इस शुल्क की संस्तुति हेतु कोई कारण या गणना या अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति उपलब्ध कराने में विफल रहा है। इसी प्रकार, महानिदेशक भी चीन से सोडा ऐश के आयातों पर 31% शुल्क का कारण देने में विफल रहे हैं।

94. सार्वजनिक हित : सोडा ऐश पर कोई रक्षोपाय शुल्क सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगा। एक औद्योगिक प्रयोक्ता के रूप में हम सोडा ऐश का व्यापक उपयोग डिटर्जेंट, टिक्की तथा सैकरीन के विनिर्माण में करते हैं। सोडा ऐश फ्लोट ग्लास उद्योग, बल्क ड्रग तथा विभिन्न औद्योगिक रसायनों में भी महत्वपूर्ण है। सोडा ऐश पर किसी शुल्क के परिणामस्वरूप अनेक मूलभूत वस्तुओं तथा दवाइयों की कीमतों में वृद्धि होगी। इस प्रकार, ये प्रभाव उद्योगों की सीमित संख्या के बजाय भारतीय नागरिकों पर अधिक पड़ेंगे।

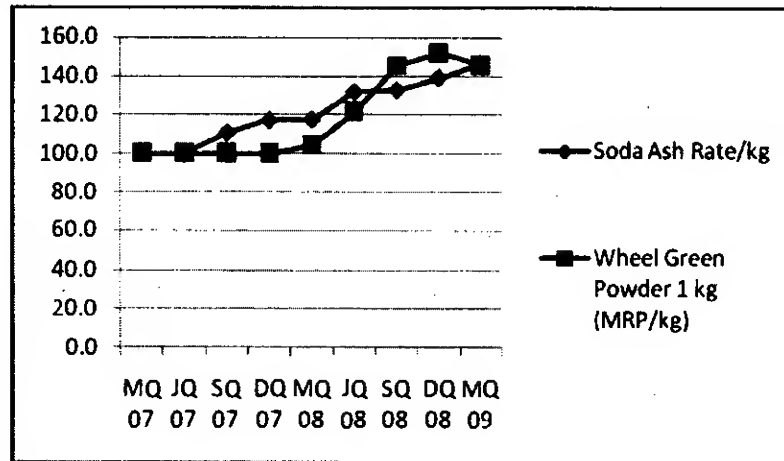
95. जहाँ तक अनंतिम स्लोपाय शुल्क के प्रभाव का संबंध है, सोडा ऐश पर अनंतिम शुल्क 20 अप्रैल, 2009 को ही लागू किया गया था; जबकि शुल्क के भार का प्रभाव अंतिम उत्पाद अर्थात् डिटर्जेंटों पर पड़ेगा परंतु इस स्तर पर समय की कमी को ध्यान में रखते हुए उद्योग सोडा ऐश की कीमत में वृद्धि करने के सम्पूर्ण प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ है। चूँकि परिणामों का पता आयातक जैसे किसी सूचबद्ध कम्पनी के लिए केवल तिमाही आधार पर ही चलता है इसलिए संशोधित कीमत के प्रभाव का अभी पता लगाया जाना है। अतः आयातक डिटर्जेंट की कीमतों पर अनंतिम शुल्क लगाए जाने के बाद सोडा ऐश की कीमत का प्रभाव दर्शाते हुए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ है। चूँकि अनंतिम शुल्क के बाद सोडा ऐश की उच्चतर कीमत का प्रभाव अभी महसूस किया जाएगा इसलिए घरेलू उद्योग हमारे लाभ मार्जिनों पर उच्चतर कीमतों के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ है। इसके अलावा, महानिदेशक का ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि वर्ष 2009 की दूसरी छमाही के लिए समस्त घरेलू सोडा ऐश के प्रतिस्पर्धियों के साथ कीमत संबंधी वार्ताओं के दौरान सोडा ऐश के घरेलू प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रदत्त आरंभिक प्रभाव आईपीपी (आयात समतुल्यता कीमत) बेंचमार्क कीमत के समान था जिसमें स्लोपाय शुल्क का प्रभाव शामिल था। इसे सामान्यतः उस तथ्य से जोड़ा जा सकता है कि घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने अब लागू अनंतिम शुल्क के कारण अपनी कीमतों में कृत्रिम रूप से वृद्धि की है। तथापि, पिछले आंकड़ों में व्हील डिटर्जेंट के अधिकतम खुदरा मूल्य/कि.ग्रा. के बीच मजबूत सह-संबंध प्रदर्शित होता है और सोडा ऐश की लागत निम्नानुसार है :



96.



97.



98. निष्कर्ष : उपर्युक्त के मद्देनजर आयातक ने अनुरोध किया है कि जांच अवधि “ अप्रैल-दिसम्बर, 2008 ” के रूप में परिभाषित की जानी चाहिए । आंकड़े पारदर्शी और भरोसेमंद होने चाहिए जो किसी विश्लेषण का आधार बन सकें । जांच अवधि के दौरान आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । याचिकाकर्ताओं को बाजार विकृति आयातों में आरोपित वृद्धि के कारण नहीं हुई है और रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगा । उपर्युक्त कारणों से रक्षोपाय शुल्क लगाने की याचिका की अनदेखी की जानी चाहिए और यह कार्यवाही आगे समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

ऑल इंडिया ग्लास मैन्यू. एसो. (एआईजीएमएफ) तथा यूपी ग्लास मैन्यू. सिंडिकेट (यूपीजीएमएस) ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

99. पक्षकारों के बीच रक्षोपाय जांच का कोई विवाद नहीं है । कानूनन रक्षोपाय जांच अत्यंत पारदर्शिता के साथ करनी होती है क्योंकि आम जनता जांच के परिणामों से प्रभावित होती है । यह कार्यवाही पक्षकारों के बीच किसी विवाद की प्रकृति की बजाय सूचना मांगने के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक हित में जांच के रूप में अधिक होती है । निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत लिखित सूचना को ध्यान में रखने के बाद भी शामिल किया गया था क्योंकि कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं होती है ।

100. आयात में वृद्धि अनुचित नहीं है । आयात में प्रत्येक वृद्धि अथवा भारत से बाहर कम कीमतों पर सामग्री की उपलब्धता खराब नहीं है और इसे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरिदास एक्सपोर्ट्स बनाम ऑल इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्यू. एसो. 2002 (145) ईएलटी 241 (एससी) के मामले में पाटनरोधी एवं प्रतिस्पर्धा कानून के सिलसिले में निम्नलिखित शब्दों में देश से बाहर कम कीमतों पर सामग्री की उपलब्धता के लाभों पर जोर दिया है । “ स्वदेशी रूप से उत्पादित वस्तु की कीमत से कम कीमत पर भारत से बाहर वस्तु की उपलब्धता से भारतीय उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी समाप्त नहीं होंगे जैसे कि प्रतिवादियों ने माँग की है । ”

101. डब्ल्यूटीओ में चीन के शामिल होने संबंधी प्रोटोकॉल/डब्ल्यूटीओ करार में निहित प्रावधानों और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग तथा सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 (जिसे आगे “ नियम ” कहा गया है) के उपबंधों के अंतर्गत कोई रक्षोपाय लागू करना एक अत्यंत असाधारण आपात उपाय/कार्यवाही होती है जिसका सहारा

असाधारण परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने संयुक्त राज्य-कोरिया से सर्कुलर वैल्वेड कार्बन क्वालिटी लाइन पाइप के आयातों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क, डब्ल्यूटी/डीएस202/एबी/आर, 8 मार्च, 2002 को पारित डीएसआर 2002 : IV, 1403 के पैरा 80 में यह माना है कि “यह स्मरण करना उपयोगी है कि रक्षोपाय आपात स्थितियों में ही उपयोग में लाया जाने वाला असाधारण निवारण है।”

102. सोडा ऐश की घरेलू कीमतें अनुचित रूप से अधिक हैं : घरेलू विनिर्माताओं की सोडा ऐश की कीमतें जो मार्च, 2007 में 9142 प्रति मी. टन से बढ़कर अगस्त, 2008 में 16000 हो गईं और आज भी ये कारखाना स्तर पर लगभग 14900 पर हैं। इनसे किसी बड़ी गिरावट दर्ज नहीं होती है। घरेलू बाजार में मूलभूत कच्ची सामग्री घूना और लवण प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है जैसा कि आवेदन के पैरा 3 में स्वीकार किया गया है। मूलभूत कच्ची सामग्री की कीमतों में खास परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी निविष्टि ऊर्जा है जो पेट्रोलियम कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप सस्ती हो गयी है। अतः यह कहना विरोधाभासी है कि घरेलू उद्योग चीन से हुए संविधित आयातों से मिली कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण खतरे में पड़ गया है। इसके विपरीत इससे सोडा ऐश के आयातों में आरोपित वृद्धि स्पष्ट हो जाती है क्योंकि उपभोक्ता अपनी माँग की पूर्ति हेतु सस्ती जगह तलाशने के लिए बाध्य होते हैं।

103. एक ओर चीन की कीमतें अन्य देशों की तुलना में वस्तुतः अधिक हैं, वहीं दूसरी ओर मात्रा के रूप में चीन के आयात घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार कम रहे हैं। इस प्रकार, चीन के आयात द्वारा कोई वास्तविक क्षति नहीं हो सकती जब यह अन्य देशों से हुए आयात के कारण भी नहीं हो सकती है।

104. निर्यात बिक्री के मामले में उत्पादन लागत घरेलू बिक्री की तुलना में डीईपीबी/वापसी लाभों की राशि तक कम है। वर्तमान डीईपीबी/वापसी लाभ अधिकतम 2% हैं। अतः कारोबारी परिदृश्य से निर्यात बिक्री एवं घरेलू बिक्री की मामले में कारखाना प्राप्ति में अंतर 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमत की जांच से यह पता चलेगा कि घरेलू उत्पादक 160-170 अम. डा. प्रति मी.टन एफओबी पर सोडा ऐश की बिक्री कर रहे हैं और इसलिए कारखाना द्वार पर उनकी प्राप्ति 150 अम. डा. (7500 रु./मी. टन) से कम है क्योंकि निर्यातों की स्थिति में वे ग्राहकों को घटी हुई निविष्टि लागत का लाभ प्रदान कर रहे हैं। उनके निर्यातों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता। उन्हें ऐसा व्यवहार दिया जाना चाहिए जो कम-से-कम विदेशी क्रेताओं को प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से बेहतर न होकर उनके बराबर जरूर हो।

105. कानून में सार्वजनिक सुनवाई के समय आंकड़े प्रस्तुत कर जांच की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं है और यह अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत कर प्रत्येक को चौकाने के लिए घरेलू उद्योग के भाग पर भी अनुचित है।

106. सार्वजनिक हित : सोडा ऐश प्याज के समान है जिसका उपयोग अनेक उपभोक्ता मर्दों की उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले अनेक उद्योगों द्वारा किया जाता है। वस्तुतः अगस्त, 2008 में सरकार ईटी, दिनांक 02.08.2008 में सूचित कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सोडा ऐश के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही थी।

107. सोडा ऐश अनेक उद्योगों के लिए निविष्टि है। यदि कच्ची सामग्री की लागत बढ़ेगी तो कीमत में भी वृद्धि होगी और उत्पाद आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि सोडा ऐश जैसे किसी मध्यवर्ती के बजाय ग्लास जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद का आयात किया जाएगा। यदि हम अपने उत्पादों की बिक्री करने में समर्थ नहीं हैं तो सोडा ऐश के विनिर्माता भारत में अपना बाजार गँवा देंगे। अतः सोडा ऐश पर पाटनरोधी शुल्क लगाना स्वयं अनुचित है और सार्वजनिक हित के खिलाफ है।

108. इससे काँच उद्योग बंद हो जाएगा और परिणामतः सोडा ऐश के उद्योग को क्षति पहुँचेगी। लोग बेरोजगार होंगे और उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ेगा।

109. इससे भारत सोडा ऐश जैसी कच्ची सामग्री का आयात करने के बजाय ग्लास जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का जरूरत के अनुसार आयातक बन जाएगा।

110. घरेलू उत्पादकों को आयातित सोडा ऐश की तुलना में कम-से-कम 7.5% का मूलभूत टैरिफ संरक्षण तथा 15% का अन्य समुद्री भाड़ा संरक्षण पहले से प्राप्त है। अतः किसी अतिरिक्त संरक्षण से घरेलू उत्पादकों को अनुचित लाभ मिलेगा।

111. यह उल्लेखनीय है कि निरमा लि., जो प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में से एक है और सोडा ऐश के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, अपने डिटर्जेंट कारोबार हेतु सोडा ऐश की आबद्ध खपत करता है। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना से भी यह पता चलता है कि टाटा कैमिकल्स लि. भी डिटर्जेंट पाउडर कारोबार में संभावना तलाशने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से डिटर्जेंट पाउडर के अन्य उत्पादकों को नुकसान पहुँचाकर इन उत्पादकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है।

112. प्रारंभिक जांच परिणाम केवल अंतरिम एकतरफा जांच परिणाम हैं और अंतिम जांच परिणामों पर प्रारंभिक जांच परिणामों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं में अंतरिम आदेशों की अंतिम निष्कर्ष निकालते समय कोई भूमिका नहीं होती है। अंतरिम जांच परिणामों का अंतिम जांच परिणामों के लिए कोई महत्व नहीं है।

113. प्रारंभिक जांच परिणाम का बीओएस द्वारा अनुमोदन विधिक अनुबंधों के प्रतिकूल गोपनीय पत्र के आधार पर किया गया है और इस दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतरण के परिवर्ती प्रकटन से प्रक्रिया विधिसम्मत नहीं बन जाएगी। सिफारिशों को सार्वजनिक बनाने के पीछे विचार यह है कि हितबद्ध पक्षकार को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए और इस सिफारिश की स्वीकृति के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दे दिया जाए। प्रस्ताव के प्रकटन की स्वीकृति के बाद कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जा सकता।

114. दिनांक 23.03.2009 को सार्वजनिक सुनवाई करने के बाद 20.04.2009 की अधिसूचना द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया जाना भी कानून के उपबंधों के खिलाफ है। नियम 9 में आपात परिस्थितियों में शुल्क लगाने का प्रावधान है और वह भी तब जब जांच लंबित हो। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद कोई अनंतिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता। तथापि, वर्तमान मामले में जांच पूरी हो गई थी। सुनवाई हो गयी थी। समस्त पक्षकारों ने अपने अनुरोध कर दिए थे तब भी शुल्क एकतरफा प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर लगाया गया था।

115. उपर्युक्त अनुरोधों के मद्देनजर रक्षोपाय शुल्क लगाने के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन स्वीकार्य नहीं है। अतः माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) से अनुरोध है कि वे इस जांच परिणाम के साथ सोडा ऐश पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बारे में 16 जनवरी, 2009 की फा. सं. डी-22011/02/09 के तहत शुरू की गई जांच को समाप्त करने कि रक्षोपाय शुल्क लगाने का कोई मामला नहीं बनता है।

I-ग्लास (पूर्व में ऑल इंडिया फ्लैट ग्लास मैन्यू. एसो.- एआईएफजीएमए के नाम से ज्ञात), सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि. (एसजीजीआई) तथा असाही इंडिया ग्लास लि. (एआईजी) के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

116. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया गया है जैसाकि निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगा :

i. महानिदेशक (रक्षोपाय) ने समस्त हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचारों को जानने के लिए 16.02.2009 तक का समय प्रदान किया था। प्रारंभिक जांच परिणामों को उस तारीख की प्रतीक्षा किए बिना ही घोषित कर दिया गया है जो तारीख स्वयं महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ/पूरक सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गयी थी।

ii. आवेदन एवं सूचना की प्रतियाँ कई प्रयोक्ताओं को भी नहीं भेजी गई थीं यद्यपि शिकायतकर्ता घरेलू उद्योग को इस बात की पूरी जानकारी है कि पूर्ववर्ती कंपनियाँ परवर्ती कंपनियों के क्रेता हैं।

iii. अधिकाँश मामलों में सूचनाएँ भेजी गई थीं परंतु घरेलू उद्योग के आवेदन की प्रतियाँ संलग्न नहीं की गई थीं।

iv. प्रयोक्ता उद्योग अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ या पूरक सूचना प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

117. आवेदन और जांच शुरुआत संबंधी सूचना के सामान्य पाठन से यह पता चलेगा कि नियम 5 की पूर्व शर्तों का पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार जांच की शुरुआत कानूनन दोषपूर्ण है।

118. आवेदन एवं प्रारंभिक जांच परिणामों में यह उल्लेख किया गया है कि आयातों में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है कि इनसे भारत में घरेलू बाजार के लिए विकृति उत्पन्न हो गई है। सादर निवेदन है कि दो माह की अत्यल्प अवधि के लिए मामूली वृद्धि से इतनी अधिक मात्रा में हुए आयातों की कल्पना नहीं की जा सकती जिससे बाजार विकृति हुई हो।

119. यह सुविदित तथ्य है कि मई, 2007 से नवम्बर, 2008 के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सोडा ऐश की कीमतों में काफी अधिक 70-75% की वृद्धि की गई थी। बाद में प्रमुख निविष्टियों में पर्याप्त कमी आने के बावजूद घरेलू उद्योग ने सांकेतिक रूप से 400 रु./टन अर्थात् लगभग 2.4% की कीमत में कमी की। कीमत में मामूली 2.4% की कमी करना निविष्टि की लागत में हुई कमी के अनुरूप नहीं था। स्पष्टतः अपनी कीमतों में सुधार करने और नई वास्तविकताओं को

समायोजित करने के लिए घरेलू उद्योग की अनिच्छा के कारण कुछेक आयातक अपने खुद के बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अनिवार्यतः आयात करने के लिए बाध्य हुए हैं।

120. यह बात स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का आवेदन और प्रारंभिक जांच परिणाम वस्तुतः गलत तथ्यों पर आधारित है और अतुलनीय अवधि की तुलना संख्याओं के हेरफेर द्वारा की गयी है।

121. क्या यह सच है कि कोई जांचकर्ता प्राधिकारी चाहे वो पाटनरोधी या रक्षोपाय से संबंधित हो, ऐसी न्यूनतम अवधि को ध्यान में रखना चाहेगा जिसके लिए जांच हेतु विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हों जिसका अर्थ यह नहीं है कि जांच अवधि में परिवर्तन स्वेच्छा से किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जांच शुरू करते समय प्राधिकारियों को उस अवधि के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिस अवधि के लिए आंकड़े या ब्यौरे उपलब्ध हों। इससे महानिदेशक को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो ऐसी अवधि को चुने जिससे कानूनी प्रक्रिया के कारण असंतोष तथा परिहास की स्थिति उत्पन्न हो जाए।

122. वस्तुतः घरेलू उद्योग के लिए सोडा ऐश का उत्पादन 40,879 मी. टन/सप्ताह के औसत साप्ताहिक उत्पादन से बढ़कर तुलनीय अवधि की तुलना में 55,971 मी. टन हो गया है। वस्तुतः यह 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार अब तक का सबसे अधिक औसत प्रतीत होता है।

123. औसत घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यह 39,101 मी. टन की नई ऊँचाई पर पहुँच गयी है जो उस अवधि के दौरान दर्ज सर्वोच्च औसत बिक्री से भी अधिक है जब बाजार विकृति उत्पन्न होने का दावा किया गया है।

124. औसत साप्ताहिक क्षमता उपयोग लगभग 100% पर पहुँच गया है जो 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार अब तक का सबसे अधिक है। यह 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार 73.84% से बढ़कर जांच अवधि में 99.99% हो गया है।

125. जहाँ तक लाभप्रदता में गिरावट आने के दावे का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि दावा की गई लाभप्रदता में गिरावट भी सितम्बर, 2008 को समाप्त अवधि के लिए जो आरोपित संबंधित आयातों तथा आरोपित बाजार विकृति से पहले की है। अतः लाभप्रदता संबंधी विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकलता है।

126. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त कारकों के संबंध में घरेलू उद्योग से कोई पूछताछ नहीं की गई है यदि 31.12.2008 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषण उचित और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तथा उसकी तुलना की जाए।

127. इस संदर्भ में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सोडा ऐश का आयात “डेन्स” तथा “लाइट” रूप में किया जाता है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि “डेन्स” तथा “लाइट” सोडा ऐश का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। तब भी घरेलू उद्योग ने महानिदेशक को भ्रमित करने के लिए दोनों उत्पादों को आपस में मिला दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि “डेन्स” तथा “लाइट” सोडा ऐश के बीच कीमत में भारी अंतर है जो आयात आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। अतः कीमत संबंधी मुद्दे के बारे में दिए गए समस्त तर्क “डेन्स” तथा “लाइट” सोडा ऐश दोनों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं जैसा कि घरेलू उद्योग ने किया है।

128. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया था कि भारत और अन्य देशों के लिए चीन की कीमतों में अंतर है, अन्य देशों के लिए कीमतें काफी अधिक हैं। इस संदर्भ में अनुरोध है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने की माँग करने के लिए कीमत को कानूनी आधार बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

129. इस बात का व्यापक तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग को इस तथ्य की वजह से भी घाटा हो रहा है कि संयंत्र कच्ची सामग्री की नजदीकी के कारण सौराष्ट्र क्षेत्र स्थित खपत केन्द्रों से काफी दूर स्थित हैं। इस संदर्भ में हमारा अनुरोध है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे का रक्षोपाय शुल्क से कोई लेना-देना नहीं है और ऐसे मुद्दों पर भाड़ा सब्सिडी की संभावना की दृष्टि से अलग से विचार किया जा सकता है। स्थान संबंधी कारकों के कारण अंतर्निहित नुकसान को रक्षोपाय शुल्क लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

130. बड़े जोर-शोर से यह भी तर्क दिया गया था कि चीन 9% तक निर्यात सब्सिडी प्रदान करता है। हमारा अनुरोध है कि उपर्युक्त कारणों से यह तर्क भी निराधार है। किसी निर्यात सब्सिडी का उत्तर सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार में निहित है न कि टीपीएसएसएम में।

131. प्रारंभिक जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के लिए रक्षोपाय शुल्क के रूप में 31% की सिफारिश की गई थी। तथापि, केन्द्र सरकार ने 20% तक शुल्क लगाने का निर्णय लिया जो भी इस तथ्य के मद्देनजर अधिक है कि घरेलू उद्योग भारी मुनाफा कमा रहा है और विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क का कोई वैध मामला नहीं बना है।

132. यह भी अनुरोध है कि ऐसे काल्पनिक आधार पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से समूचे काँच उद्योग को भारी धक्का लगेगा जो समग्र वैश्विक मंदी के कारण पहले से ही दबावग्रस्त है।

मे. गुजरात गार्जियन लि. (“जीजीएल”) ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

133. एएमएआई द्वारा दायर याचिका में गंभीर कमियाँ हैं जिससे इस जांच का आधार ही कम हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक भ्रामक, झूठे और असत्य विवरण अपनी याचिका में दिए हैं जो माननीय रक्षोपाय महानिदेशक को धोखा देने का प्रयास है और आयातों में आरोपित कुछ वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजार विकृति बाजार विकृति के खतरे तथा कारणात्मक संबंध की पुष्टि की है जबकि सच यह है कि याचिकाकर्ताओं ने क्षमता का पूर्ण उपयोग किया है और उनकी स्थिति में कोई मामूली परिवर्तन आयात की मात्रा से असंबद्ध कारणों से हुआ है।

134. सदस्यता संबंधी प्रोटोकॉल में एक स्कीम निर्धारित की गयी है जिसके तहत प्रभावित सदस्य चीन के साथ परामर्श करता है और वह बाजार विकृति, यदि कोई हो, के सुधार हेतु चीन को एक अवसर प्रदान करता है। ऐसा तभी होता है यदि परामर्श का यह परिणाम निकलता है कि प्रभावित सदस्य के पास उपाय लागू करने की अनुमति है तथापि इस मामले में यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रक्रिया का न केवल सदस्यता संबंधी प्रोटोकॉल के तहत चीन के प्रतिभाग के दायित्व उल्लंघन अपितु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन द्वारा पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है।

135. जांच की शुरुआत से पूर्व साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच नहीं की गई थी। यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना साक्ष्य के रूप में होनी चाहिए न कि किसी आंकड़े से समर्थित मात्र आरोपों के रूप में जैसा कि इस मामले में हुआ है। अनुरोध है कि

साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच करना जरूरी है। प्रदत्त आंकड़े इस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं कि (i) याचिका में कुछेक महत्वपूर्ण सूचना प्रदान नहीं की गई है जिसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए था और याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त आंकड़ों में गंभीर असंगतता होने के बावजूद जांच शुरू की गई है।

136. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़े गलत और भ्रामक हैं।

137. चीन तथा अन्य देशों से हुए आयातों की मात्रा गलत है।

138. उत्पादन के आंकड़ों में समानता नहीं है।

139. समूचे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और केवल चुनिंदा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

140. उत्पादन लागत के आंकड़े भ्रामक हैं।

141. आयात कीमत तथा घरेलू प्राप्ति की तुलना का आधार दोषपूर्ण और निराधार है। आंकड़ों की तुलना असंगत अवधियों के संदर्भ में की गई है।

142. यह देखा जा सकता है कि यद्यपि माननीय रक्षोपाय महानिदेशक ने रक्षोपाय जांच में उत्तर दायर करने के लिए 30 दिन की अवधि की अनुमति दी थी तथापि, प्रारंभिक जांच परिणामों से संबंधित अधिसूचना जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना शुरू होने की तारीख से 15 दिन के भीतर जारी कर दी गयी थी। अनुरोध है कि माननीय रक्षोपाय महानिदेशक का उक्त आचरण प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

143. बाजार विकृति तब हुई बताई जाती है जब रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य से निम्नलिखित सिद्ध हो जाए :

- i. आयातों में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- iii. आयातों में इस प्रकार की तीव्र वृद्धि वास्तविक क्षति का प्रमुख या पर्याप्त कारण है।
- iv. आयातों की मात्रा, कीमतों पर आयातों के प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव जैसे कारकों पर पूर्णरूप में विचार किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या बाजार विकृति हुई है।

144. गुजरात गार्जियन ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर क्षति मापदंडों के खतरे का विश्लेषण किया है। यह उस दावे के प्रति किसी भेदभाव से रहित है कि आंकड़े स्वयं भरोसेमंद नहीं हैं अथवा यह कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वार्षिक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए थे। पुनरावृत्ति का जोखिम लेते हुए आगे यह उल्लेख किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को यह सिद्ध करना चाहिए था कि वास्तविक क्षति का खतरा और इस प्रकार बाजार विकृति आसन्नवर्ती और पूर्वानुमानिक थी। यह इस तथ्य के मद्देनजर अधिक संगत हो जाता है कि याचिकाकर्ता “आपात परिस्थितियों” के आधार पर प्रारंभिक उपायों की मांग कर रहे थे। याचिकाकर्ता “खतरे” की पुष्टि करने या इस प्रकार की आरोपित “आपात परिस्थितियों” के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं जिनके तहत प्रारंभिक शुल्क अपेक्षित बन जाता है।

145. यह नोट किया जाना चाहिए कि जरूरत इस बात की नहीं है कि आयातों में “ वृद्धि ” दर्शाई जाए अपितु इस बात की है कि आयातों में “ तीव्र वृद्धि ” प्रदर्शित की जाए । इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को यह प्रदर्शित करना होता है कि न केवल वृद्धि हुई है अपितु ऐसी वृद्धि तेजी से और जल्दी-जल्दी हुई है । तथापि, इस स्पष्ट विधिक दायित्व के बावजूद याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि चीन से सोडा ऐश के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है ।

146. पूर्ववर्ती वर्ष के आयात आंकड़ों की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 08 के दौरान चीन से हुए कुल आयातों में मामूली अर्थात् 0.08% की वृद्धि हुई है । इसके अलावा, यदि हम चीन के सीमाशुल्क के आयात आंकड़ों पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान हुए आयातों की तुलना में केवल 0.03% की वृद्धि हुई है ।

147. तेजी से संवर्धित आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करते हुए “ बाजार विकृति ” की पुष्टि करनी होती है कि बाजार में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के हिस्से में आई ऐसी गिरावट केवल आयातों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण आई है । तथापि, याचिका में प्रदत्त आंकड़ों पर नजर डालने से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग के हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है अपितु घरेलू उद्योग के हिस्से में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और आयातों के हिस्से में वृद्धि मामूली हुई है ।

148. याचिकाकर्ताओं ने यह बेवजह का तर्क दिया है कि उत्पादन में उक्त गिरावट संवर्धित आयातों के कारण आई है । प्रारंभ में ही यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि उत्पादन में मामूली गिरावट आई है तथापि, जांच अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि हुई है । इस प्रकार, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्सा दोनों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है ।

149. किसी पूर्वाग्रह के बिना याचिका के अनुबंध 9 में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही मान लिए जाएँ तो इन आंकड़ों से स्पष्टतः यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने अपने संयंत्रों में क्षमता बढ़ाने के गंभीर प्रयास किए हैं । घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में किसी वृद्धि से स्पष्टतः यह पता चलता है कि यह प्रक्रिया केवल इसलिए की गयी है कि कंपनी को सोडा-ऐश की घरेलू बिक्री में तुरंत वृद्धि होने का अनुमान है ।

150. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने उद्योग की उत्पादकता का कोई हवाला नहीं दिया है ।

151. याचिका के अनुसार घरेलू उद्योग को आयातों में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है । तथापि, याचिकाकर्ताओं ने वह आधार प्रदर्शित नहीं किया है जिसपर उन्होंने लाभ/हानि की गणना की है । अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को उस आधार का खुलासा करना चाहिए जिस पर उन्होंने लाभ/हानि की गणना की है अर्थात् इसकी गणना क्या ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) के आधार पर की गई है या फिर ब्याज कर मूल्य ह्रास से पूर्व आय तथा ऋण स्थगन (ईबीआईटीडीए) के आधार पर ।

152. घरेलू उद्योग ने उत्पाद विशिष्ट स्लोपाय शुल्क लगाने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका में रोजगार के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं । हितबद्ध पक्षकारों को प्रमुख सूचना उपलब्ध न कराने से इन आंकड़ों की सत्यता का विरोध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों की क्षमता में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ है ।

153. यह भी अनुरोध है कि याचिका के अनुबंध 2 के अनुसार वर्ष 2007-08, जब बाजार विकृति के खतरे का दावा किया गया है, को छोड़कर चीन से हुए आयातों की सीआईएफ आयात कीमत अन्य देशों से हुए आयातों के सीआईएफ मूल्य से अधिक है।

154. घरेलू बिक्री के लिए उत्पादन लागत की गणना करते समय और क्षतिरहित कीमत निकालते समय घरेलू उद्योग ने 22% की दर से लगाई गई पूँजी पर आय आरओसीई निर्धारित करने का अनुमान लगाया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि चूँकि आरओसीई 22% नहीं थी जिससे घरेलू उद्योग के लिए बाजार विकृति का पता चलता है। तथापि, अनुरोध है कि आरओसीई पर 22% की निर्धारित आय कानूनसम्मत नहीं है जैसाकि रक्षोपाय नियमों में उल्लेख किया गया है। आरओसीईसी अलग-अलग उद्योगों तथा अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग होती है। अतः 22% की निर्धारित आरओसीई का अनुमान लगाना कानूनन गलत है और इसे बाजार विकृति का निष्कर्ष निकालने के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इंडियन स्पीनर्स एसो. बनाम डीए के मामले में यह भी निर्णय दिया गया है कि डीजीएडी को 22% की निर्धारित आरओसीई का अनुमान नहीं लगाना चाहिए और उद्योग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आरओसीई के सही आंकड़े निकालने चाहिए।

155. याचिकाकर्ता आयातों में “ तीव्र वृद्धि ” और उनके द्वारा आरोपित बाजार विकृति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में भी विफल रहे हैं। अनुरोध है कि आयातों एवं घरेलू समान उत्पादों के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है।

156. निष्कर्षतः गुजरात गार्जियन आंकड़ों में गंभीर कमी, बाजार विकृति या बाजार विकृति के खतरे तथा आरोपित आयात एवं आरोपित बाजार विकृति के बीच कारणात्मक संबंध के किसी साक्ष्य के अभाव के कारण यह जांच समाप्त करने के अपने अनुरोध को दोहराते हैं।

अन्य अनुरोध

157. विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी लिखित अनुरोधों के जरिए और दोनों सार्वजनिक सुनवाई के दौरान विस्तृत अनुरोध किए हैं। इनका सारांश निम्नानुसार है :

158. कुछेक पक्षकारों ने वही अनुरोध किए हैं जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है।

159. आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि आंकड़ों के अलग-अलग स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों का उपयोग करना उचित नहीं है।

160. आयात में वृद्धि, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमत कम करने की अक्षमता के कारण हुई है।

161. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। ये सभी कंपनियाँ काफी बड़ी हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं।

162. रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं है क्योंकि अनेक उपभोक्ताओं द्वारा खपत किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों के लिए ये उत्पाद निविष्टियाँ हैं। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से सोडा ऐश की कीमत बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप अंतिम उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी जिससे उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होंगे।

163. घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी व्यवहार अपना रहे हैं।

164. अतः कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

जाँच और जाँच परिणाम

165. धारा 8ग(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को किसी वस्तु पर उस स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है यदि चीन जन. गण. से भारत में उक्त वस्तु का आयात ऐसी संबंधित मात्राओं और ऐसी स्थितियों में किया जा रहा हो जिससे घरेलू उद्योग के लिए बाजार विकृति उत्पन्न हुई है या उसका खतरा उत्पन्न हो रहा है।

166. सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट) रक्षोपाय शुल्क नियम 2002 में जांच को शासित करने वाले तरीके और सिद्धांतों का प्रावधान है। तदनुसार, जांच उक्त नियमों के अनुसार की गई है और अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना के जरिए दर्ज किए गए हैं।

चीन से हुए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम 2002 के अंतर्गत जांच के कारण

167. चीन और चीन से भिन्न देशों के आयात के आंकड़ों (तालिका 2, तालिका 3 और तालिका 4) से यह पता चलता है कि अक्टूबर, 2008 के बाद चीन से सोडा ऐश के आयातों में वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों से हुए आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। अतः चीन से हुए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम 2002 के अंतर्गत रक्षोपाय जांच की गई है।

जांचाधीन उत्पाद क्या है ?

168. जाँचाधीन उत्पाद : जांचाधीन उत्पाद डाई सोडियम कार्बोनेट जिसका लोकप्रिय नाम सोडा ऐश है और जिसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है। सोडा ऐश एक सफेद, दानेदार और जल में घुलनशील पदार्थ है। इस आदेश में इसका उल्लेख “सोडा ऐश” के रूप में किया गया है। सोडा ऐश सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की उपशीर्ष 283620 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों- लाइट सोडा ऐश तथा डेन्स सोडा ऐश में किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा दोनों प्रकार के सोडा ऐश का उत्पादन किया जाता है और आयात भी दोनों प्रकारों के होते हैं। दोनों प्रकारों में अंतर बल्क घनत्व का है। रासायनिक रूप से सोडा ऐश के दोनों प्रकार समान हैं। चीन से आयातित डेन्स सोडा ऐश तथा घरेलू रूप से उत्पादित सोडा ऐश के बीच भौतिक या रासायनिक विशेषताओं के संबंध में कोई खास अंतर नहीं है। इसके अलावा, आयातित लाइट सोडा ऐश तथा घरेलू रूप से उत्पादित लाइट सोडा ऐश के बीच भौतिक या रासायनिक विशेषताओं के संबंध में कोई खास अंतर नहीं है। आयातित सोडा ऐश तथा घरेलू सोडा ऐश के समान या समनुरूप बिक्री माध्यम हैं। दोनों की बिक्री अंतिम प्रयोक्ताओं, वितरकों या खुदरा व्यापारियों को सीधी बिक्री के जरिए की जाती है। इन उत्पादों के समान उपयोगों और ये वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। कीमत संबंधी सूचना तत्काल उपलब्ध है तथा संबंधित उत्पाद एवं घरेलू उत्पादकों के उत्पाद मुख्यतः कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः आयातित सोडा ऐश घरेलू रूप से उत्पादित के “समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी” है।

ऐसे कौन घरेलू उत्पादक हैं जो रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ “घरेलू उद्योग” हैं ?

169. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग(7)(क) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

(ख) “घरेलू उद्योग” से ऐसे उत्पादक अभिप्रेत हैं-

- जो समग्र समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के उत्पादक हैं;
- जिनका समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

170. भारत में जो प्रमुख उत्पादक सोडा ऐश का विनिर्माण करते हैं वे निम्नानुसार हैं :

- टाटा कैमिकल्स लि.
- गुजरात हैवी कैमिकल्स लि.
- सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.
- डीसीडब्ल्यू लि.
- निरमा लि. और
- तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.

171. इन उत्पादकों के हिस्से का उल्लेख नीचे तालिका 1 में किया गया है। निम्नलिखित उत्पादकों ने “घरेलू उद्योग” के रूप में विचार करने का अनुरोध किया है :

- मै. टाटा कैमिकल्स लि., अंधेरी (पू.), मुंबई;
- मै. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि., नोएडा;
- मै. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि., बिरला सागर, पोखन्दर, गुजरात
- मै. डीसीडब्ल्यू लि., मुम्बई और
- मै. निरमा लि., भावनगर, गुजरात

तालिका-1

भारत के कुल उत्पादन में अलग-अलग उत्पादकों का हिस्सा					
	इकाई का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	डीसीडब्ल्यू लि.	3.81%	3.80%	3.90%	3.91%
2	जीएचसीएल लि.	23.35%	24.70%	28.37%	29.49%
3	निरमा लि.	22.95%	21.66%	17.21%	18.31%
4	सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.	10.64%	6.57%	13.26%	11.51%
5	टाटा कैमिकल्स लि.	35.37%	39.17%	37.27%	36.78%
6	तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%
	महायोग	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	भारतीय उत्पादकों, जिन्होंने याचिका का समर्थन किया, का हिस्सा	96.11%	95.91%	100.00%	100.00%
	अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%

172. यह पाया गया है कि वर्ष 2008-09 में सोडा ऐश का उनका उत्पादन कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 100% बनता है। चूंकि उपर्युक्त उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन भारत में सोडा ऐश के कुल उत्पादन का 100% बनता है और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस आशय का कोई तर्क नहीं दिया है कि ये उत्पादक घरेलू उद्योग नहीं हैं इसलिए उपर्युक्त घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8ग(7) के अंतर्गत परिभाषित “घरेलू उद्योग” के अर्थ के भीतर “घरेलू उद्योग” हैं।

जाँच अवधि क्या है ?

173. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम 2002, रक्षोपाय करार अथवा गैट के संगत अनुच्छेद XIX में इस आशय की विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि जाँच अवधि क्या होनी चाहिए। तथापि, अर्जेंटीना फुटवियर पर पैनल की रिपोर्ट में एवं अर्जेंटीना पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में जाँच अवधि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

“ अर्जेंटीना-फुटवियर के आयातों पर रक्षोपाय : पैनल की रिपोर्ट

8.216 जहाँ तक जाँच में घरेलू उद्योग की स्थिति में परिवर्तन के विश्लेषण में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की गई तुलनाओं पर लगभग पूर्ण भरोसा किए जाने का संबंध है, हमारी भी वही चिंता है जैसी कि “ संवर्धित आयातों ” के विश्लेषण के बारे में ऊपर नोट किया गया है। यहाँ हम इस बात को खासतौर पर नोट करते हैं कि यदि मध्यवर्ती रूझानों पर क्रमबद्ध ढंग से विचार नहीं किया जाता है और उनका विश्लेषण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी “ समस्त संगत कारकों ” का विश्लेषण करने के बारे में अनुच्छेद 4.2(क) की अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा घरेलू उद्योग की स्थिति का पूर्णरूप से आकलन नहीं होता है। उदाहरणार्थ, ऐसी किसी उद्योग की स्थिति, जिसका उत्पादन एक वर्ष में काफी कम हो जाता है परंतु उसके बाद उसमें लगातार सुधार होता है यद्यपि कुछ स्तर तक यह शुरूआती स्तर से कुछ कम रहता है तो यह स्थिति तर्कसम्मत ढंग से ऐसे किसी उद्योग की स्थिति से अलग होगी जिसके उत्पादन में विस्तारित अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है। एक छोर से दूसरे छोर तक का विश्लेषण दोनों मामलों में एक समान होना चाहिए जबकि वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों एवं रूझानों पर विचार करने से पूर्णतः विपरीत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

हमारा मानना है कि विभिन्न क्षतिकारकों में जाँच अवधि के दौरान परिवर्तनों पर विचार करना इस बात के निर्धारण हेतु अनिवार्य है कि क्या किसी उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का आसन्नवर्ती खतरा उत्पन्न हो गया है। मध्यवर्ती रूझानों पर विचार किए बिना एक छोर से दूसरे छोर तक की तुलना से अपेक्षानुसार समस्त संगत कारकों का पूर्ण मूल्यांकन प्रदान करने की संभावना नहीं है।

अपीलीय निकाय की रिपोर्ट

नोट 130.

पैनल ने पैनल रिपोर्ट के पैरा 8.166 की पाद टिप्पणी 530 में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान काल का उपयोग किया जा रहा है जिसमें यह उल्लेख है कि “ यह प्रतीत होगा कि जाँच अवधि का शुरूआती बिंदु कोई भी हो उसे हाल की निकटतम अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए ” (जोर दिया गया)। यहाँ हम पैनल से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि संगत जाँच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए अपितु उसे हाल की अवधि होनी चाहिए।

174. उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो रक्षोपाय करार और न ही डब्ल्यूटीओ के संगत प्रावधानों में जाँच अवधि की विशिष्ट परिभाषा या व्याख्या निहित नहीं है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह जाँच परिणाम दिया गया है कि संगत जाँच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए; जाँच अवधि हाल की अवधि होनी चाहिए। अतः आवेदन दायर करने के बाद की अवधि की रक्षोपाय जाँच में अनदेखी नहीं की जा सकती। तथापि, प्राकृतिक न्याय की जरूरत को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि जाँच की शुरूआत के बाद प्राप्त या संगृहीत सूचना हितबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध हो।

175. इस मामले में 16 जनवरी, 2009 को जांच शुरू की गई थी और प्रारंभिक जांच परिणाम 30 जनवरी, 2009 को जारी किए गए थे। अनंतिम रक्षोपाय शुल्क 20 अप्रैल, 2009 को लगाया गया था। आवेदकों ने यह कहा है कि पूर्व में अज्ञात मंदी के कारण आयात में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि दिसंबर, 2008 से हुई। आयात में वृद्धि 2008-09 की चौथी तिमाही में हुई। अतः 2008-09 की चौथी तिमाही बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे के निर्धारण के लिए माना गयी है। अप्रैल, 2006 से दिसंबर, 2008 तक की अवधि से संबंधित सूचना भी तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन के लिए मानी गई है। अतः मार्च, 2009 के बाद की अवधि पर भी विचार किया गया है।

सूचना की पद्धति एवं स्रोत

176. आयात के उद्देश्य से आंकड़ों की विश्वसनीयता डीजीसीआईएस आंकड़ों पर वित्तीय वर्ष 2007-08 तक और बाद की अवधि के लिए आईबीआईएस पर रखी गई है। सूचना के लेन-देन वार ब्योरे सार्वजनिक फाइल में रखे गए हैं। भारत के सभी विनिर्माताओं से संबंधित अन्य आर्थिक मानदंड अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) और अलग-अलग एककों से लिए गए हैं। यदि अन्य किसी सूचना का इस्तेमाल किया गया है, तो स्रोत का उल्लेख सूचना के साथ किया गया है।

177. चूंकि जांच की शुरुआत वर्ष के मध्य में की गई थी, अतः यह भी हो सकता है कि वार्षिक सूचना बहुत ही हाल की न हो। अतः विश्लेषण के उद्देश्य से विश्लेषण के लिए त्रैमासिक आंकड़े तथा मासिक आंकड़े प्रयोग किए गए हैं। मौसमी परिवर्तन के प्रभावों से बचने के उद्देश्य से, यदि कोई हों, पिछले वर्ष की इसी अवधि के साथ तुलना की गई है। प्रवृत्ति विश्लेषण करने के उद्देश्य से वास्तविक मासिक आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है ताकि नमूना आकार संगत रूप से बड़ा हो।

178. इसके अतिरिक्त, बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे के निर्धारण के लिए आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करते समय क्रम 2 और क्रम 3 के बहुपद का इस्तेमाल करते हुए प्रवृत्ति विश्लेषण किया गया है।

क्या आयात में कोई वृद्धि है ?

179. बढ़ा हुआ आयात : निम्नलिखित तालिका में सोडा ऐश से संबंधित तिमाही आयात आंकड़े दिए गए हैं। माहवार आयात अनुबंध-1 पर रखा है।

तालिका-2

	चीन से सोडा ऐश आयात (मात्रा मी.ट. में)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	17,836	2,256	10,046	1,10,329
ति2	19,112	6,362	10,716	-
ति3	7,929	21,268	20,261	-
ति4	16	7,804	67,624	-

तालिका 3

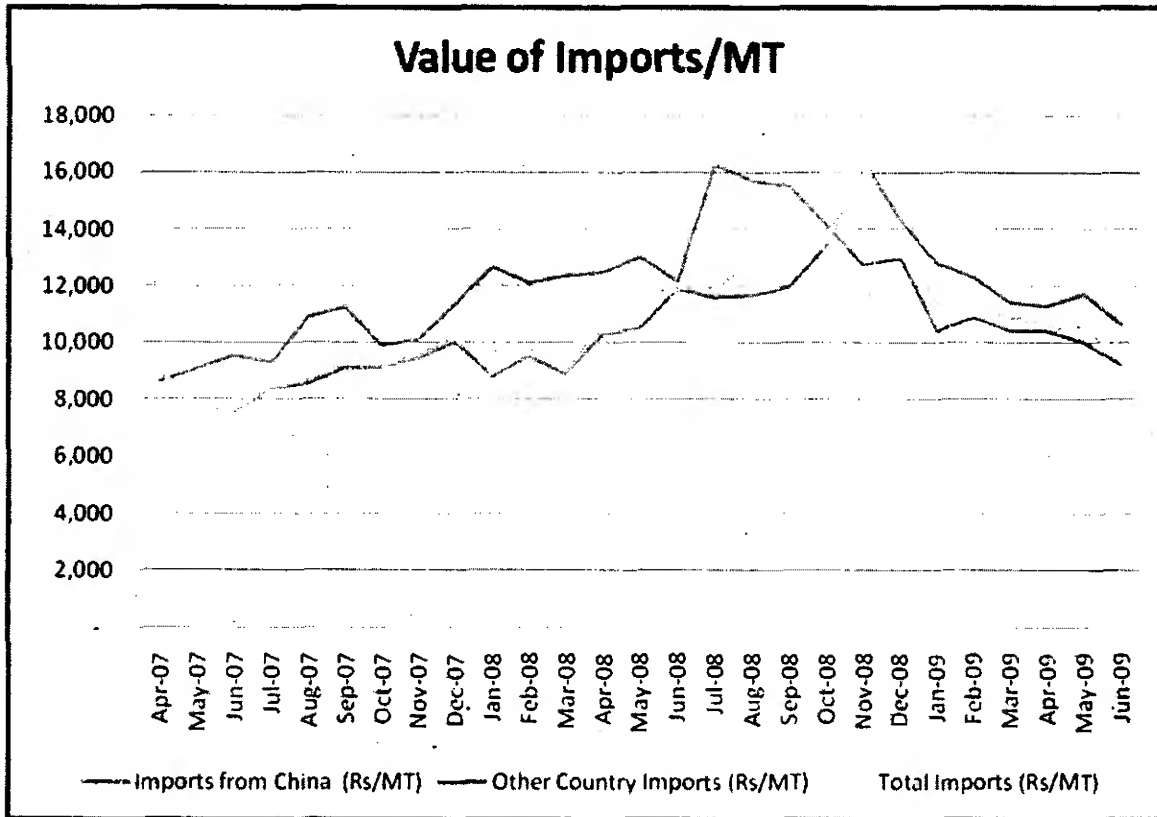
	चीन को छोड़कर अन्य से सोडा ऐश आयात (मात्रा मी.ट. में)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	58,923	49,666	50,333	41,195
ति2	62,139	63,236	55,566	-
ति3	56,241	1,13,356	42,825	-
ति4	35,326	90,233	33,778	-

तालिका 4

	भारत में कुल सोडा ऐश आयात (मात्रा मी.ट. में)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	30,166	76,759	51,922	60,379	1,51,523
ति2	44,637	81,251	69,598	66,282	-
ति3	38,733	64,170	1,34,623	63,086	-
ति4	38,280	35,342	98,037	1,01,402	-

रेखा चित्र-1

आयातित मूल्य/मी.ट.



180. चीन से आयात में वृद्धि माह दिसंबर, 2008 में हुई। दिसंबर, 2008 में आयात दिसंबर, 2007 में 4004 मी.ट. के आयात की तुलना में चीन से 15946 मी.ट. था। उपर्युक्त रेखा चित्र में चीन से माह-वार आयात दर्शाया गया है।

181. चीन से 2008-09 की चौथी तिमाही में आयात 2007-08 की चौथी तिमाही में 7804 मी.ट. के आयात की तुलना में 67624 मी.ट. था। चीन से 2009-10 की पहली तिमाही में आयात 2008-09 की पहली तिमाही में 10046 मी.ट. की तुलना में 110329 मी.ट. था। भारत में कुल आयात 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में पिछले वर्षों की संबंधित तिमाहियों में 98037 मी.ट. तथा 60379 मी.ट. की तुलना में 101402 मी.ट. तथा 1515123 मी.ट. था। यह 2008-09 की चौथी तिमाही में चीन से आयात में 8.66 गुना वृद्धि तथा 2009-10 की पहली तिमाही में 10.98 गुना वृद्धि दर्शाता है। चीन से आयात में इस वृद्धि से भारत में आयात में समग्र वृद्धि हुई है। यद्यपि, दूसरे देशों से आयात में उसी अवधि में गिरावट आई। 2008-09 की चौथी तिमाही में और 2009-10 की पहली तिमाही में आयात में कुल वृद्धि क्रमशः 3.4% तथा 151% थी। इसका अभिप्राय यह है कि चीन से आयात में दिसंबर, 2008 से तेजी से वृद्धि हुई है। दिनांक 20.04.2009 से 20% की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद भी आयातों में सतत वृद्धि हुई है।

182. आयात में सापेक्ष वृद्धि: भारत के कुल बाजार आकार में आयात का हिस्सा निम्नलिखितानुसार रहा है :-

तालिका 5

वर्ष		बाजार हिस्सा(%)		
		चीन	घरेलू उत्पादक	अन्य
2005-06	ति 1	0.01	94.19	5.81
	ति 2	0.91	91.91	7.18
	ति 3	0	92.68	7.32
	ति 4	0.72	93.11	6.17
2006-07	ति 1	3.07	86.80	10.14
	ति 2	3.63	84.58	11.79
	ति 3	1.46	88.16	10.38
	ति 4	0.00	93.76	6.24
2007-08	ति 1	0.42	90.30	9.28
	ति 2	1.34	85.35	13.31
	ति 3	3.36	78.75	17.89
	ति 4	1.27	84.01	14.72
2008-09	ति 1	1.82	89.07	9.11
	ति 2	2.00	87.61	10.39
	ति 3	4.05	87.38	8.57
	ति 4	11.62	82.57	5.80
2009-10	ति 1	17.74	75.63	6.62

183. चीन का बाजार हिस्सा 2008-09 की चौथी तिमाही में और 2009-10 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की संबंधित तिमाहियों में 1.27% और 1.82% की तुलना में क्रमशः 11.62% और 17.74% था। अतः चीन से आयात सापेक्ष दृष्टि से भी बढ़े।

चीन से किन स्थितियों में आयात हो रहे हैं ?

184. अनुबंध-1 में औसत आयात मूल्य/माह दिया गया है और उपर्युक्त रेखाचित्र-1 में चीन और अन्य देशों से आयात मूल्य/मी.टन का रेखाचित्र प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तालिका में तिमाही औसत आयात मूल्य है।

तालिका 6

आयात कीमतें - चीन

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	37,817	8,503	9,184	12,559	10,008
ति 2	8,765	8,492	10,540	15,721	
ति 3	-	8,824	10,300	13,221	
ति 4	8,794	44,446	12,393	10,649	

185. वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में प्रति मी.ट. आयात मूल्य में संबंधित तिमाहियों में 12393 रुपए/मी.ट. तथा 12559 रु./मी.ट. से घटकर क्रमशः 10649 रु./मी.ट. तथा 10008 रु./मी.ट. हो गया। इसके अतिरिक्त 2008-09 की चौथी तिमाही में और 2009-10 की पहली तिमाही में आयात मूल्य/मी.ट. में गिरावट आई है जो 2008-09 की ठीक पिछली तिमाही अर्थात् तीसरी तिमाही की तुलना में है। अतः चीन से आयात में वृद्धि कम मूल्य पर है।

चीन से आयात वृद्धि के क्या कारण हैं ?

186. वर्ष 2008 के मध्य में शुरू हुई अभूतपूर्व तथा विषम मंदी के कारण कई राष्ट्रों में मंदी छा गई। मंदी का प्रभाव विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप में रहा। मंदी के कारण सामान्य गिरावट से चीन के घरेलू तथा निर्यात बाजार में दोनों जगह मांग में गिरावट आ गई जिससे चीन में अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता उपलब्ध रही। ऐसी स्थितियों से निपटने के उद्देश्य से चीन ने अपारंपरिक बाजार की तलाश की। भारत चीन का पारंपरिक बाजार नहीं रहा है जैसा कि चीन से भारत में होने वाले आयात की मात्रा से स्पष्ट है, जो कि सितंबर, 2008 तक बहुत कम थी। तथापि, जब मंदी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया तो भारतीय बाजार चीन के लिए महत्वपूर्ण हो गया जो कि चीन से कम मूल्य पर बड़े हुए आयात से स्पष्ट है। पारंपरिक रूप से चीन से भारत में आयात अन्य देशों से आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य पर होता रहा है, परंतु 2008-09 की तीसरी तिमाही में यह स्थिति विपरीत हो गई। जैसा कि रेखाचित्र-1 में देखा जा सकता है कि दूसरे देशों से आयात की कीमत की बढ़ती हुई प्रवृत्ति होने पर भी चीन के आयात की कीमतें अचानक नीचे आ गईं। कीमतों में आई अचानक इस गिरावट से सोडा ऐश के आयात की प्रवृत्ति विपरीत हो गई। चीन द्वारा कीमत में अचानक कमी कर दिए जाने के कारण चीन से आयात तेजी से बढ़ने लगा और चीन भारत के लिए सोडा ऐश का मुख्य आयातक बन गया। चीन से आयात अन्य देशों की तुलना में कम कीमत पर होता है।

187. चीन से अन्य विभिन्न देशों को निर्यात की प्रवृत्ति (रेखाचित्र-2) भी यह दर्शाती है कि भारत चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। चीन में सोडा ऐश के उत्पादकों पर ध्यान देते हुए इस परिवर्तन से आयात में वृद्धि हुई है। चीन से आयात बढ़ाने वाले ये पहलू अप्रत्याशित हैं।

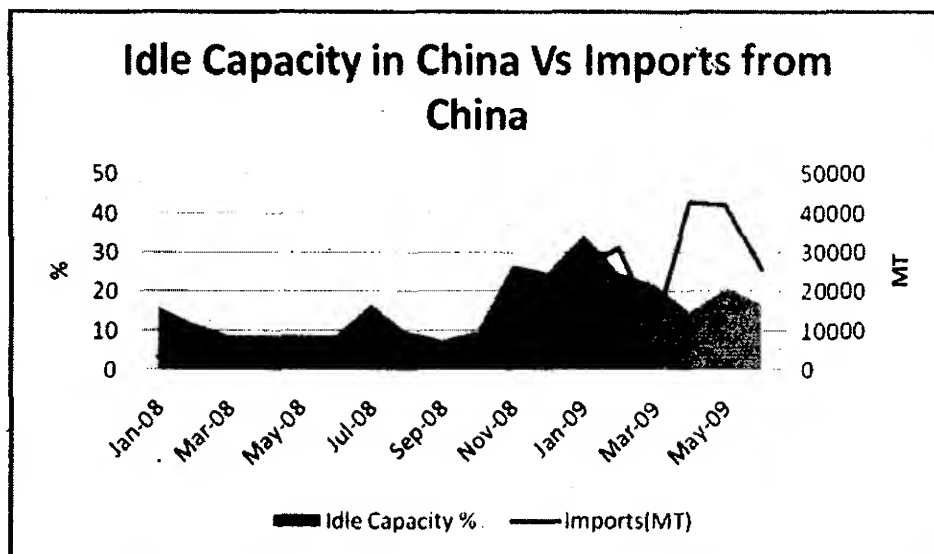
तालिका : 7
चीन में अतिरिक्त क्षमता

माह	बेकार क्षमता
जनवरी-08	16.00%
फरवरी-08	12.00%
मार्च-08	9.00%
अप्रैल-08	9.00%
मई -08	9.00%
जून-08	9.00%
जुलाई-08	17.00%
अगस्त-08	10.00%
सितंबर-08	8.00%
अक्टूबर-08	10.00%
नवंबर-08	27.00%
दिसंबर-08	25.00%
जनवरी-09	35.00%
फरवरी-09	25.00%
मार्च-09	22.00%
अप्रैल-09	15.00%
मई-09	21.00%
जून-09	17.00%
जुलाई-09	21.00%
अगस्त-09	20.90%

[स्रोत: हैरीमन कौसल्ट लिमिटेड. , सीएमएआई रिपोर्ट,
चीन का राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो]

रेखाचित्र- 2

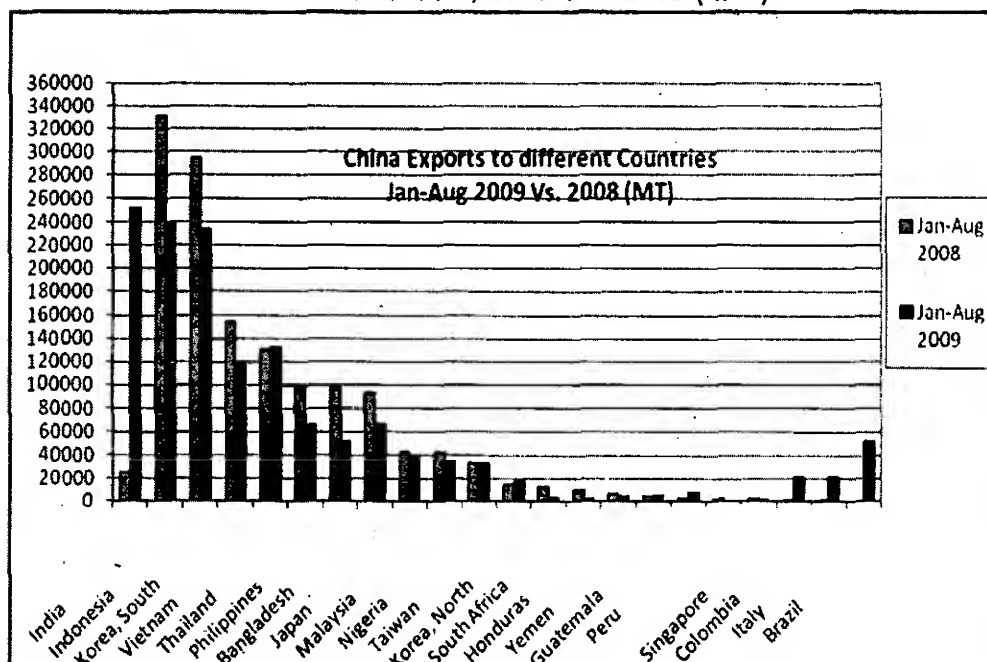
चीन की बेकार क्षमता बनाम चीन से आयात



रेखाचित्र- 3

चीन द्वारा भारत एवं अन्य देशों को निर्यात

विभिन्न देशों को चीन का निर्यात
जनवरी-अगस्त, 2009 बनाम 2008 (मी.ट.)



जैसाकि उपर्युक्त रेखाचित्र से देखा जाता है, जनवरी-अगस्त, 2009 के दौरान चीन द्वारा भारत को किए गए निर्यात में वर्ष 2008 की इसी अवधि की तुलना में 25,000 मी. टन से 252,000 मी. टन की वृद्धि हुई है। भारत को हुए निर्यात में हुई इस वृद्धि से इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा फिलिपींस जो चीन में सोडा ऐश के उत्पादकों के पारंपरिक बाजार रहे हैं, को निर्यात में होने वाली वृद्धि में कमी आई है।

बाजार अवरोध के खतरे से संबंधित प्रमाणों का मूल्यांकन:

सांविधिक ढांचा:

188. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग (7) (ख) में स्पष्ट है कि जब कभी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु या उस जैसी वस्तु का आयात तेजी से बढ़ता है, चाहे पूर्ण रूप से बढ़े अथवा सापेक्ष रूप से बढ़े जो वास्तविक क्षति का महत्वपूर्ण कारण हो, अथवा जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा हो, "बाजार अवरोध" उत्पन्न होगा। इसमें यह भी परिभाषित है कि "बाजार अवरोध के खतरे" का अभिप्राय बाजार अवरोध के स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।

189. तथापि, "वास्तविक क्षति" की परिभाषा न तो अधिनियम में पाई जाती है और न ही सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 में पाया जाता है। अतः निदेशालय द्वारा पिछली जांचों में अपनाई गई परिपाटी तथा अन्य देशों के कानूनों और परिपाटियों का अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि चीन के आयातों की तुलना में रक्षोपाय शुल्क से संबंधित यू एस ए के कानून में "वास्तविक क्षति" की परिभाषा दी गई है। "वास्तविक क्षति" शब्द यू एस ए के व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 406 में तथा यू एस ए के टैरिफ अधिनियम, 1930 के शीर्षक VII में दिखाई देती है। 1930 के टैरिफ अधिनियम के शीर्षक VII में "वास्तविक क्षति" को "वह क्षति जो अपरिणामी, अवास्तविक अथवा महत्वहीन न हो" के रूप में परिभाषित किया गया है।

190. यह भी नोट किया गया है कि बाजार अवरोध परीक्षण गंभीर क्षति परीक्षणों की अपेक्षा अधिक आसानी से पूरे किए जाने के इरादे से होते हैं। वास्तविक क्षति शब्द "गंभीर क्षति" शब्द की अपेक्षा कम मात्रा में क्षति दर्शाता है।

191. तदनुसार, बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे के लिए संगत नियमों में उल्लिखित सभी पहलुओं तथा अन्य कारकों, जैसा कि इसकी स्थिति है अथवा भविष्य का पूर्वानुमान लगाए जाने योग्य स्थिति में इसकी संभावना है, विशेषकर मूल अथवा निर्यातक देश में निर्यात क्षमता पर विचार करने के लिए, बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे का विश्लेषण करने में यह उपयुक्त पाया जाता है कि क्षमता का प्रयोग भारत को निर्यात करने के लिए किया जाएगा तथा भारत पर चीन द्वारा निर्यात के लिए कितना ध्यान दिया जा रहा है। एक भी कारक को निपटान योग्य नहीं माना गया है तथा संगत व्यापार चक्र के भीतर सभी संगत कारकों तथा प्रतिस्पर्धा की स्थितियों, जो प्रभावित उद्योग के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है। बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर बीच में आने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

संगत कारकों की पहचान

192. संगत कारकों की पहचान करने के उद्देश्य से रक्षोपाय जांच के लिए अनेक राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई परिपाटी तथा उन कारकों, जो सोडा ऐश उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डालते हैं, की जांच की गई। नियम 8 के अनुबंध में बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे के अस्तित्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया गया है :-

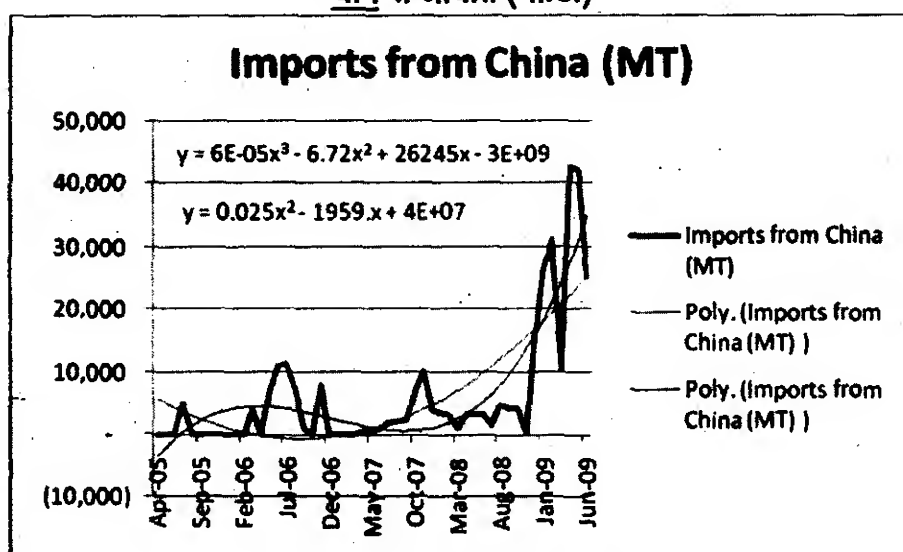
- i. आयात वृद्धि की दर
- ii. वर्धित आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार का हिस्सा
- iii. बिक्री स्तर में परिवर्तन
- iv. उत्पादन
- v. उत्पादकता
- vi. क्षमता उपयोग
- vii. लाभ एवं हानि
- viii. रोजगार

193. नियमों में उल्लिखित सभी पहलुओं को मूल्यांकन के लिए अपनाया गया है। इन कारकों के अतिरिक्त इस मामले के लिए कतिपय कारकों को भी संगत कारक माना गया है, ये हैं :-

- i. मूल अथवा निर्यातक देश में निर्यात क्षमता, जैसा कि इसकी स्थिति है अथवा भविष्य का पूर्वानुमान लगाए जाने योग्य स्थिति में इसकी संभावना है, की क्षमता का उपयोग भारत को निर्यात के लिए किया जाएगा।
- ii. चीन द्वारा निर्यात के लिए भारत को केन्द्र बनाना।
- iii. मालसूची

194. आयात वृद्धि की दर : आयात वृद्धि की दर का मूल्यांकन के उद्देश्य से अप्रैल, 2005 से आयात प्रवृत्ति का क्रम 2 और क्रम 3 के बहुपद प्रवृत्तियां लेकर अध्ययन किया गया है। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है। इस प्रवृत्ति की स्थितियां दर्शाती हैं कि आयात में वृद्धि की दर वास्तविक है। यह भी देखा गया है कि आयात में वृद्धि अक्टूबर, 2008 से एक बार हुई है। दूसरे शब्दों में आयात में वृद्धि की दर स्वतः बढ़ रही है।

रेखाचित्र - 4
चीन से आयात (मी.ट.)



195. चीन से वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार का हिस्सा: निम्नलिखित तालिका एवं रेखा चित्र से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के बारे में सूचना मिलती है।

तालिका 8

तिमाही	बाजार हिस्सा (%)		
	चीन	घरेलू उत्पादक	अन्य
05-06 ति1	0.01	94.19	5.81
05-06 ति2	0.91	91.91	7.18
05-06 ति 3	-	92.68	7.32
05-06 ति 4	0.72	93.11	6.17
06-07 ति 1	3.07	86.80	10.14
06-07 ति 2	3.63	84.58	11.79
06-07 ति 3	1.46	88.16	10.38
06-07 ति 4	0.00	93.76	6.24
07-08 ति 1	0.42	90.30	9.28
07-08 ति 2	1.34	85.35	13.31
07-08 ति 3	3.36	78.75	17.89
07-08 ति 4	1.27	84.01	14.72
08-09 ति 1	1.82	89.07	9.11
08-09 ति 2	2.00	87.61	10.39
08-09 ति 3	4.05	87.38	8.57
08-09 ति 4	11.62	82.57	5.80
09-10 ति 1	17.74	75.63	6.62

196. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2008-09 की तीसरी तिमाही से गिर रहा है। घरेलू उद्योगों का बाजार हिस्सा 2007-08 की चौथी तिमाही में 84.01% से गिरकर 2008-09 की चौथी तिमाही में 82.57% हो गया। बाजार हिस्से में यह गिरावट 2009-10 की पहली तिमाही में उस समय तक जारी रही जब यह पिछले वर्ष से उसी तिमाही में 89.07% से गिरकर 75.63% हो गई। वर्ष 2008-09 की तीसरी और चौथी तिमाही तथा 2009-10 की पहली तिमाही में यह गिरती प्रवृत्ति 2007-08 की तीसरी और चौथी तिमाही तथा

2008-09 की पहली तिमाही में वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है । 20 अप्रैल, 2009 से मूल्यानुसार 20% की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद भी 2009-10 की पहली तिमाही में बाजार हिस्सा 2005-06 से शुरू करके पूरी अवधि में कम से कम है । यह भी देखा गया है कि दूसरे देशों से आयात के हिस्से में भी गिरावट आई है और इस प्रकार घरेलू उद्योग का हिस्सा चीन से आयात द्वारा लिया गया है ।

197. बिक्री स्तर में परिवर्तन: निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा तिमाही-वार बिक्री दी गई है ।

तालिका 9

तिमाही	बिक्री (मी.ट.)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	4,88,794	5,04,532	4,83,558	4,92,142	4,70,319
ति2	5,07,359	4,45,663	4,05,514	4,68,751	
ति3	4,90,616	4,77,618	4,98,893	4,36,845	
ति4	5,17,577	5,31,127	5,14,964	4,80,476	

तालिका 9क

	बिक्री				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
जुलाई	1,72,221	1,49,000	1,54,029	1,66,172	1,50,528
अगस्त	1,60,070	1,46,524	1,22,933	1,60,381	1,31,586

198. वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में 2007-08 की चौथी तिमाही और 2008-09 की पहली तिमाही की तुलना में क्रमशः 6.7% तथा 4.43% की गिरावट आई । 2008-09 की चौथी तिमाही वह अवधि थी, जब अनंतिम शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी तथा 2008-09 की पहली तिमाही वह अवधि थी, जब अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया गया था । 2009-10 की पहली तिमाही में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद बिक्री में पिछले वर्ष की उसी तिमाही की तुलना में गिरावट आई । बिक्री की गिरावट की यह प्रवृत्ति जुलाई और अगस्त, 2009 तक जारी रही । वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में घरेलू उद्योग द्वारा सोडा ऐश की कम बिक्री, पिछले वर्ष की उसी तिमाही में तुलना करने पर, 2007-08 की दूसरी तिमाही और पहली तिमाही की तुलना में 2008-09 की दूसरी और पहली तिमाही में अधिक बिक्री के विपरीत है । मासिक बिक्री की प्रवृत्ति का विश्लेषण जनवरी, 2009 के बाद विपरीत प्रवृत्ति दर्शाता है ।

199. अतः यह नोट किया गया है कि 20 अप्रैल, 2009 से 20% की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद भी बिक्री में गिरावट आई है । बिक्री में यह गिरावट की पृष्ठभूमि में चीन से इतर देशों से घटते हुए आयात और उभरता हुआ बाजार आकार रहा है । बिक्री में गिरावट चीन से हुए आयात में वृद्धि के साथ-साथ आई है । इस प्रकार, बिक्री में यह गिरावट चीन से होने वाले आयातों में वृद्धि के कारण आई है ।

200. उत्पादन : निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन तथा निर्यातित उत्पादन द्वारा कम किए गए उत्पादन (निर्यात का शुद्ध उत्पादन) तिमाही वार दिया गया है ।

निर्यात के शुद्ध उत्पादन का विश्लेषण उत्पादन में निर्यात के प्रभाव तथा घरेलू खपत के लिए किए गए उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए किया गया है।

तालिका: 10

सकल उत्पादन (मी. टन)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5,65,853	5,15,924	5,32,360	5,12,342	5,34,576
ति2	5,68,648	4,87,595	4,25,305	5,11,118	
ति3	6,07,843	5,40,916	5,51,124	5,42,399	
ति4	5,49,985	5,79,708	5,76,499	5,28,162	

तालिका 11

निवल निर्यात उत्पादन (मी. टन)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5,08,720	4,88,405	4,94,992	4,83,482	4,79,999
ति2	5,19,054	4,57,960	4,08,555	4,78,414	
ति3	5,37,702	4,83,958	5,20,302	5,04,626	
ति4	4,80,705	5,24,963	5,23,591	4,68,523	

तालिका 10 क

सकल उत्पादन (मी. टन)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
जुलाई	1,89,678	1,60,644	1,59,520	1,76,042	1,52,989
अगस्त	1,90,952	1,61,811	1,26,703	1,74,905	1,62,539

तालिका 11 क

निवल निर्यात उत्पादन (सकल उत्पादन-निर्यात)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
जुलाई	1,75,212	1,55,571	1,56,742	1,68,272	1,29,131
अगस्त	1,70,147	1,49,967	1,18,056	1,65,386	1,49,329

201. वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में उत्पादन का यदि पिछले वर्ष की उसी तिमाही से तुलना की जाए तो वह 8.38% कम है। 2008-09 की चौथी तिमाही में उत्पादन 2005-06 से शुरू करके किसी भी वर्ष की चौथी तिमाही में सबसे कम है। 2009-10 की पहली तिमाही में उत्पादन 2008-09 की पहली तिमाही की अपेक्षा अधिक है परंतु माह जुलाई एवं अगस्त, 2009 में पिछले वर्ष इन्हीं माह की तुलना में उत्पादन में 13.09% तथा 7.07% की गिरावट आई। जनवरी-अगस्त, 2009 में उत्पादन की तुलना 61522 मी.ट. अर्थात् 4.3% तक की गिरावट दर्शाती है। यह भी नोट किया गया है कि 2009-10 की पहली तिमाही में रक्षोपाय शुल्क लगाया गया था। यह भी नोट किया गया है कि जब उत्पादन में गिरावट आती है, तो आयात में वृद्धि पायी जाती है।

202. निवल निर्यात उत्पादन यह दर्शाता है कि 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में घरेलू खपत के लिए बने उत्पादन में गिरावट 2009-10 की पहली तिमाही में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद क्रमशः 10.52% तथा 0.72% रही है। यह घटती प्रवृत्ति जुलाई एवं अगस्त, 2009 में जारी रही। जुलाई एवं अगस्त, 2009 में यह

गिरावट पिछले वर्षों के इन्हीं माहों की तुलना में क्रमशः 23.26% तथा 9.70% रही । निवल निर्यात उत्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में उत्पादन अपनी-अपनी तिमाहियों में कम रहा है ।

203. अतः यह नोट किया गया है कि घरेलू खपत के लिए बने उत्पादन में गिरावट आई है। जनवरी से अगस्त के दौरान कुल उत्पादन में भी गिरावट आई है । उत्पादन में यह गिरावट 20 अप्रैल, 2009 से 20% की दर से स्कोपाय शुल्क लगाने के बावजूद आई है । इस अवधि में जबकि उत्पादन घटा है तो आयात बढ़ा है । उत्पादन में यह गिरावट संवर्धित आयातों के कारण बिक्री में गिरावट के कारण आई है । इस प्रकार, बिक्री में गिरावट चीन से संबंधित आयातों के कारण आई है ।

204. क्षमता उपयोग : निम्नलिखित तालिका में क्षमता तथा घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना दी गई है :-

तालिका 12

संस्थापित क्षमता					
तिमाही	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	6,75,250	5,94,675	6,57,175	7,19,674	7,19,674
ति2	6,75,250	6,00,758	5,36,505	7,19,674	
ति3	6,75,250	6,80,175	6,35,508	7,19,674	
ति4	6,18,292	6,81,133	7,19,674	7,19,674	

तालिका 13

क्षमता उपयोग					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	84	87	81	71	74
ति2	84	81	79	71	
ति3	90	80	87	75	
ति4	89	85	80	73	

तालिका 13 क

क्षमता उपयोग					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
जुलाई	84.27	81.04	83.09	73.38	63.77
अगस्त	84.84	81.63	77.23	72.91	67.76

205. उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि 2008-09 की चौथी तिमाही में 2005-06 से संबंधित तिमाहियों में सबसे कम क्षमता उपयोग हुआ है । वर्ष 2009-10 में क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है । क्षमता उपयोग में यह सुधार आंशिक रूप से अधिक निर्यातों और आंशिक रूप से मालसूची में वृद्धि के कारण हुआ है । इसके अतिरिक्त, 20 अप्रैल, 2009 को स्कोपाय शुल्क भी लगाया गया था । यह तारीख उसी तिमाही में आती है । तथापि, क्षमता उपयोग में यह सुधार अस्थायी स्वरूप का था । लेकिन जुलाई और अगस्त, 2009 में क्षमता उपयोग 70% से कम रहा जो समूची विचाराधीन अवधि में न्यूनतम है । परिणामतः जनवरी से अगस्त, 2009 के दौरान क्षमता उपयोग 2008 में उसी अवधि के दौरान 75% से घटकर 71.8% हुआ है । क्षमता उपयोग का मासिक प्रवृत्ति विश्लेषण दिसंबर, 2008 के बाद विपरीत प्रवृत्ति दर्शाता है, जब वर्धित आयात नोट किया गया था ।

206. अतः यह नोट किया गया है कि क्षमता उपयोग घटा है । क्षमता उपयोग में गिरावट संवर्धित आयातों के कारण आई है ।

207. मालसूची : निम्नलिखित तालिकाओं में घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध माल सूची के बारे में सूचना दी गई है ।

तालिका 14

मालसूची					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	37,282	26,465	35,822	33,667	81,115
ति2	42,936	39,955	32,061	37,874	
ति3	77,857	44,459	46,997	99,910	
ति4	40,530	28,576	48,891	75,741	

तालिका 15

मालसूची					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
जुलाई	36,961	37,743	36,473	33,263	58,093
अगस्त	45,264	39,930	29,318	37,201	76,809

208. उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में मालसूची अपनी-अपनी तिमाहियों में अधिकतम रही है । वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में मालसूची पिछले वर्षों की संबंधित तिमाहियों की तुलना में 51% तथा 141% तक बढ़ी । वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में बिक्री का प्रति दिन का स्टॉक भी संबंधित तिमाहियों में अधिक है । यही प्रवृत्ति जुलाई एवं अगस्त, 2009 में भी देखी गई ।

209. अतः यह नोट किया गया है कि दिसंबर, 2008 के बाद जब निर्यात बढ़ रहे थे, तो मालसूची अधिक थी । मालसूची में यह वृद्धि बिक्री में उस समय गिरावट के कारण हुई है जब उत्पादन करने की क्षमता मौजूद थी ।

210. लाभप्रदता : निम्नलिखित तालिका में प्रति माह लाभ एवं हानि दी गई है :-

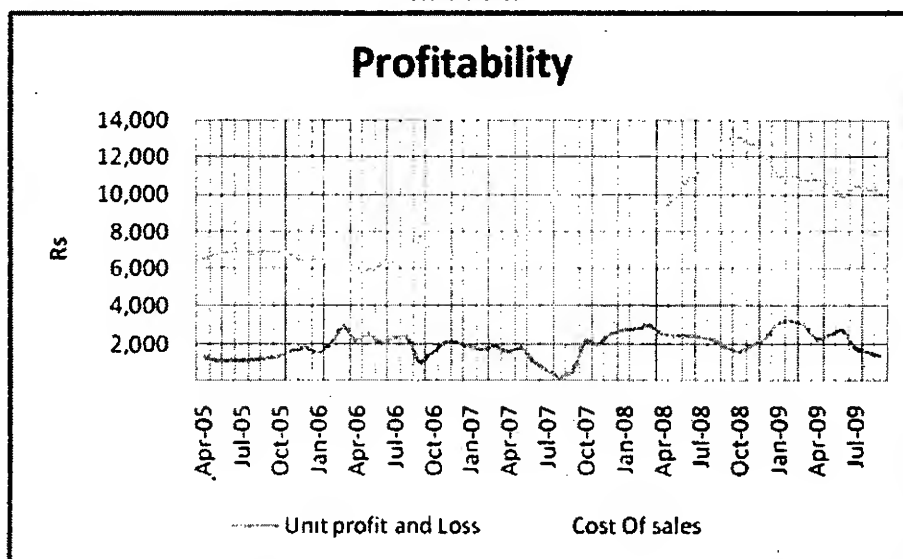
तालिका 16

लाभ एवं हानि (रु./मी.ट.) (सूचीबद्ध)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	100	190	127	209	211
ति2	97	163	34	180	
ति3	136	163	191	165	
ति4	178	152	244	264	

211. लाभ एवं हानि प्रति मी.ट. का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग में 2007-08 की तीसरी तिमाही से 2008-09 की दूसरी तिमाही तक लाभ/मी.ट. में वृद्धि हुई है परंतु, यह 2008-09 की तीसरी तिमाही में घट गया है। लाभ 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में क्रमशः 8.2% तथा 0.6% तक बढ़ गया (जब अनंतिम रक्षोपाय की सिफारिश की गई थी और उसे लागू किया गया था)। तथापि, जुलाई एवं अगस्त, 2009 में लाभप्रदता 26.7% तथा 28.8% तक गिर गई। यह भी नोट किया गया है कि इन तिमाहियों के दौरान अनंतिम रक्षोपाय शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

रेखाचित्र-5

लाभप्रदता



212. बिक्री लागत एवं यूनिट लाभ/हानि का उनके मासिक आंकड़ों, जो गिरता हुआ रेखाचित्र बना रहे हैं, के विश्लेषण से यह सामने आया है कि बिक्री लागत में वृद्धि से यूनिट लाभ में घाटा हुआ है और सामान्य रूप से जनवरी, 2009 तक लाभ होता रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि लागत में वृद्धि को उद्योग किसी हद तक खपा लेता है तथा लागत में पूरी गिरावट का असर उपभोक्ता तक नहीं जाता। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, जैसा कि अप्रैल, 2005 में विश्लेषण किया गया था। तथापि, नवीनतम प्रवृत्ति बाद की प्रवृत्ति से यह बात सामने आती है कि यूनिट लाभ एवं हानि में गिरावट है जबकि बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन लागत का लाभ अधिक अनुपात में दिया जा रहा है जो विगत में नहीं रहा है। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में माँग बढ़ रही है जिसका बिक्री प्राप्ति में सुधार एवं परिणामी बेहतर लाभप्रदता पर नैसर्गिक प्रभाव पड़ा है। लाभप्रदता या माँग में वृद्धि पर यह प्रभाव मुख्यतः भारत में संवर्धित आपूर्ति के कारण संवर्धित आयातों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। संवर्धित आयात माँग में वृद्धि से अधिक हुए हैं जिसके कारण कीमतों पर दबाव बना है जैसा कि निम्नलिखित रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

213. रोजगार: निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या दर्शायी गई है। निम्नलिखित रेखाचित्र में मासिक आधार पर कर्मचारियों की संख्या दी गई है:-

तालिका: 17

रोजगार					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	11,629	8,893	10,641	10,996	10,693
ति2	11,436	10,222	10,488	10,897	
ति3	11,721	10,981	10,944	10,979	
ति4	8,999	10,977	10,741	10,867	

214. कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही में 0.3% तक की वृद्धि, वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 1.1% तक की वृद्धि तथा वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में 2.7% तक की कमी हुई है। मासिक विश्लेषण कर्मचारियों की संख्या में रेंजवार आवागमन दर्शाता है। अतः यह नोट किया गया है कि उद्योग की स्थिति पर रोजगार कोई बाधा नहीं है, खासकर जबकि कर्मचारियों की छंटनी अल्पावधि में सामान्यतः संभव न हो।

215. उत्पादकता : प्रति कर्मचारी उत्पादन की दृष्टि से उत्पादकता निम्नलिखित है :-

तालिका 18

प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मी.ट./कर्मचारी)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	49	58	50	47	50
ति2	50	48	41	47	
ति3	52	49	50	49	
ति4	61	53	54	49	

216. कर्मचारी की उत्पादकता 2008-09 की चौथी तिमाही घटी है तथा 2009-10 की पहली तिमाही में बढ़ी है। तथापि, उत्पादकता रेंजबद्ध रही है और बाजार अवरोध के खतरे के निर्धारण पर उत्पादकता की कोई बाधा नहीं है।

217. चीन में निर्यात क्षमता, जैसी कि इसकी स्थिति है और अनुमान योग्य भविष्य में होने की संभावना है तथा ऐसी संभावना कि भारत को निर्यात करने के लिए क्षमता का उपयोग किया जाएगा: निम्नलिखित तालिका में चीन में बेकार क्षमता दर्शायी गई है।

तालिका 19

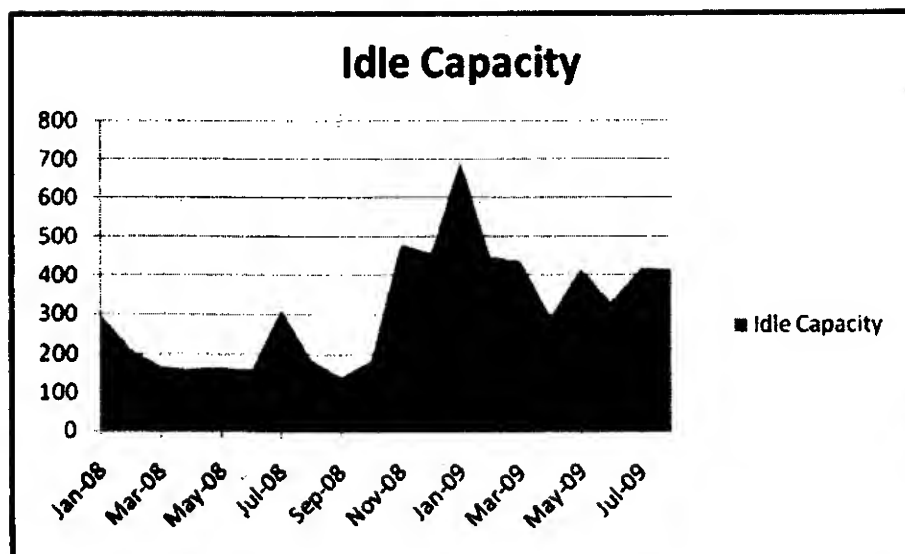
माह	बेकार क्षमता (000मी.ट.)
जनवरी-08	294.82
फरवरी-08	207.56
मार्च-08	166.26
अप्रैल-08	160.85
मई-08	165.93

जून-08	160.2
जुलाई-08	311.16
अगस्त-08	183.9
सितंबर-08	141.64
अक्टू.-08	183.87
नवंबर-08	482.97
दिसंबर-08	458.67
जनवरी-09	696.39
फरवरी-09	448.3
मार्च-09	437.91
अप्रैल-09	291.72
मई-09	418.33
जून-09	329.7
जुलाई-09	418.43
अगस्त-09	416.53

[स्रोत: हैरीमन कैमसल्ट]

रेखा चित्र- 6

बेकार क्षमता



218. अतिरिक्त क्षमता संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि चीन में अतिरिक्त क्षमता नवंबर, 2008 से बढ़ी। चीन में अतिरिक्त क्षमता नवंबर, 2009 से पूर्व 2 लाख मी.ट./माह थी, जो नवंबर, 2008 से अगस्त, 2009 तक बढ़कर औसतन 4.4 लाख मी.ट./माह हो गई। इससे चीन की इस बेकार क्षमता में 2.4 लाख मी.ट./माह तक की वृद्धि की निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि भारत का बाजार आकार लगभग

2 लाख मी.ट./माह है । इसके अतिरिक्त उनके पारंपरिक बाजार अर्थात् साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, बांग्लादेश और जापान को निर्यात कम हुआ है । जनवरी से अगस्त के दौरान इन देशों को चीन द्वारा निर्यात में औसतन मासिक गिरावट 36,000 मी.ट. प्रति माह रही है । पारंपरिक बाजार को निर्यात तथा चीन में सोडा ऐश की उपलब्ध बेकार क्षमता में कमी के कारण उसे पहले ही भारत को निर्यात के लिए इस्तेमाल किया गया है ।

219. चीन द्वारा निर्यात के लिए भारत को केन्द्र बनाना : निम्नलिखित तालिका और रेखाचित्र में चीन से भारत सहित विभिन्न देशों को निर्यात दर्शाया गया है :

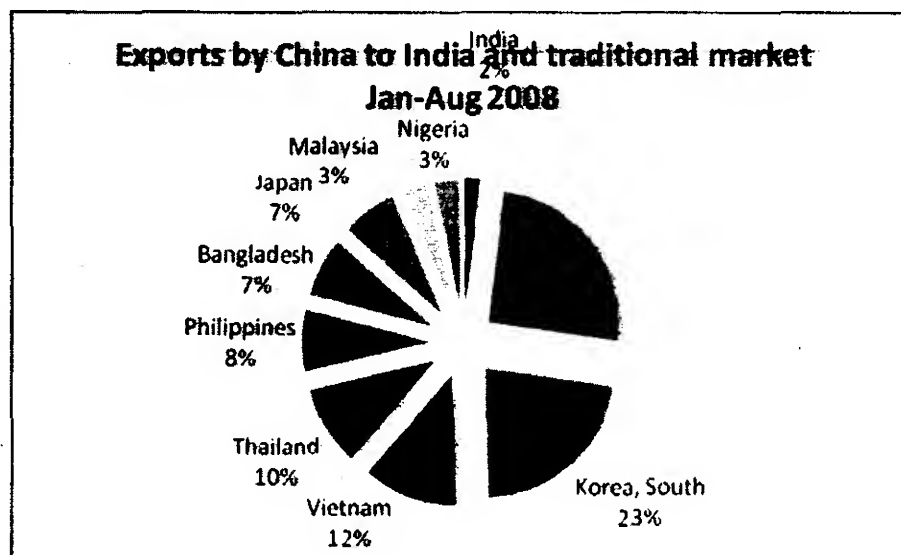
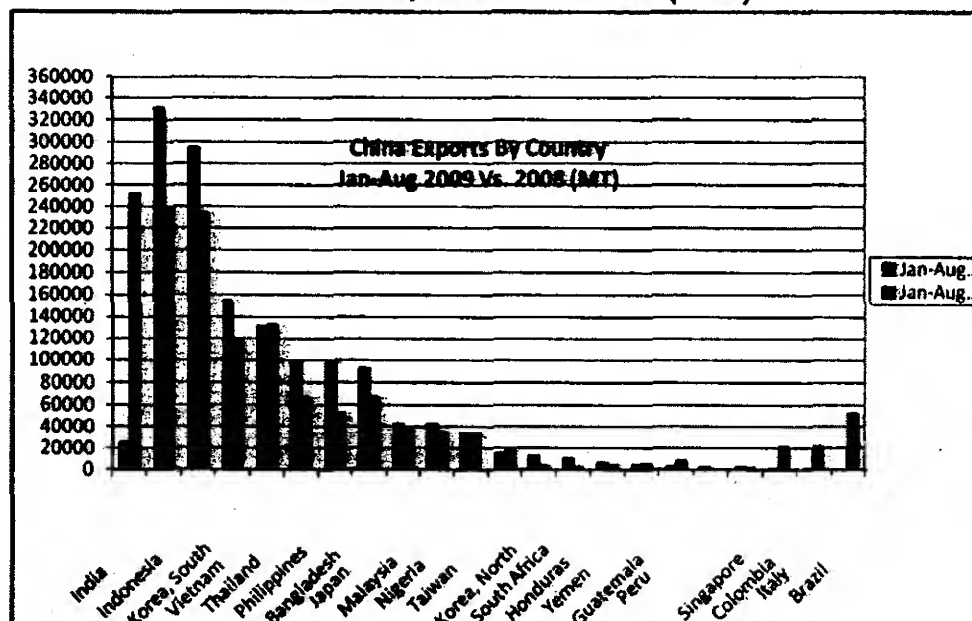
तालिका 20

चीन से विभिन्न देशों को निर्यात			
वर्ष	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा
2005-06	1,55,318	839	0.54%
2006-07	1,51,788	3,938	2.59%
2007-08	1,43,673	3,814	2.65%
जनवरी-08	1,47,389	5,282	3.58%
फरवरी-08	1,43,428	750	0.52%
मार्च-08	1,75,850	4,561	2.59%
अप्रैल-08	1,54,902	1,859	1.20%
मई-08	2,25,960	2,620	1.16%
जून-08	1,84,465	1,351	0.73%
जुलाई-08	2,10,262	3,011	1.43%
अगस्त-08	2,27,269	5,742	2.53%
सितंबर-08	1,83,157	7,809	4.26%
अक्टूबर-08	1,71,616	5,891	3.43%
नवंबर-08	1,32,478	1,920	1.45%
दिसंबर-08	1,72,103	41,207	23.94%
जनवरी-09	1,64,187	28,839	17.56%
फरवरी-09	2,11,493	31,129	14.72%
मार्च-09	2,79,692	47,535	17.00%
अप्रैल-09	2,39,698	45,320	18.91%
मई-09	1,70,377	30,402	17.84%
जून-09	2,15,828	22,889	10.60%
जुलाई-09	1,81,740	32,475	17.87%

[स्रोत: चीन सीमाशुल्क]

रेखा-चित्र 7

देशवार चीन निर्यात
जनवरी-अगस्त, 2009 बनाम 2008 (मी.ट.)





220. चीन के पारंपरिक बाजार, यथा इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम ने चीन से कम निर्यात दर्शाया है, लेकिन भारत को निर्यात जनवरी से अगस्त, 2009 के दौरान 10 गुना बढ़ा है। जनवरी से अगस्त, 2009 के दौरान भारत को निर्यात इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को हुए निर्यात से अधिक है जो कि उनके पारंपरिक बाजार रहे हैं। वर्ष 2008 में भारत का हिस्सा चीन से सोडा ऐश के कुल निर्यातों का 2-3% रहा था परंतु वर्ष 2009 में स्थिति बदल गयी और भारत का हिस्सा बढ़कर 16% हो गया। केन्द्र बनाने में इस परिवर्तन से भारत चीन के सोडा ऐश विनिर्माताओं के लिए एक संकेंद्रित बाजार बन गया है।

समग्र स्थिति का मूल्यांकन

221. ऊपर उल्लिखित मानदंडों के मूल्यांकन से यह बात सामने आती है कि आयात में बढ़ी हुई दर से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में हास हुआ है। चीन में बेकार क्षमता में भी वृद्धि हुई है और भारत को चीन ने निर्यात का एक संकेंद्रित लक्ष्य बनाया है। इसके अलावा, 20 अप्रैल, 2009 को 20% की दर से स्तोपाय शुल्क लगाने के बाद भी संबंधित आयातों, बाजार हिस्से में गिरावट, बिक्री, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में गिरावट जारी रही। अतः बाजार अवरोध का स्पष्ट एवं अस्वरूप खतरा है। प्रारंभिक निर्धारण से बाजार अवरोध का खतरा सामने आया है जिसके फलस्वरूप स्तोपाय शुल्क लगाना पड़ा है। यह भी नोट किया गया है कि बाजार अवरोध का खतरा बना हुआ है।

अन्य बाजार

222. निर्यात : निम्नलिखित तालिका में भारत द्वारा तिमाही निर्यात दिया गया है।

तालिका 21

	निर्यात बिक्री (मी. टन)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	57,133	27,520	37,368	28,860	54,577
ति2	49,594	29,636	16,750	32,704	
ति3	70,142	56,958	30,821	37,773	

ति4	69,280	54,745	52,908	59,639	
-----	--------	--------	--------	--------	--

223. निर्यात आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि भारत से निर्यात 2008-09 की तीसरी और चौथी तिमाही की अवधि तथा 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान बढ़ता रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन आंकड़ों के विश्लेषण, निर्यात विश्लेषण को छोड़कर, यह दर्शाता है कि उत्पादन में गिरावट आई है। अतः इस क्षति पर निर्यात कोई बाधा नहीं है।

224. भारत में सोडा ऐश की मांग: निम्नलिखित तालिका में भारत में बाजार आकार दिया गया है। मांग का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

तालिका 22

बाजार आकार [मांग] (मी.ट.)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5,18,960	5,81,291	5,35,480	5,52,521	6,21,842
ति2	5,51,996	5,26,914	4,75,112	5,35,033	
ति3	5,29,349	5,41,789	6,33,516	4,99,931	
ति4	5,55,857	5,66,469	6,13,001	5,81,878	

225. वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में मांग 2008-09 की पहली तिमाही की तुलना में बढ़कर 69321 तक हो गई परंतु घरेलू बिक्री घटकर 21823 मी.ट. तक रह गई। अन्य देशों से आयात भी घटकर 9138 मी.ट. तक आ गया। चीन से आयात में वृद्धि 100283 मी.ट. की थी। इसका अभिप्राय यह है कि चीन से आयात से न केवल बाजार आकार में वृद्धि हुई बल्कि उसने घरेलू उद्योग का 21823 मी.ट. का बाजार भी लिया।

226. कारणात्मक संबंध : चीन में बेकार क्षमता का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वहां नवंबर, 2008 में बेकार क्षमता तेजी से बढ़ी और आयात दिसंबर माह से बढ़ा। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा उसके पारंपरिक बाजार को निर्यात की मंदी की अवधि बढ़े हुए आयात की अवधि से सुसंगत है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा चीन से बढ़े हुए आयात के कारण काफी नीचे गया है क्योंकि उसी अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात में वृद्धि नहीं हुई है। जब चीन से आयात बढ़ गया तो उत्पादन घट गया और मालसूची बढ़ गई है। इसका अभिप्राय यह है कि चीन से आयात के कारण ही बिक्री में कमी हो रही है जिससे उत्पादन में गिरावट आ रही है और माल सूची बढ़ रही है। उत्पादन कम होने से क्षमता उपयोग भी कम हुआ है। अन्य कारकों का विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि बढ़े हुए आयात को छोड़कर अन्य कारकों का बाजार अवरोध के खतरे पर खास प्रभाव नहीं रहा। अतः बढ़ा हुआ आयात ही बाजार अवरोध के खतरे का महत्वपूर्ण कारण है।

227. जन हित : किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक व्यापारियों की परिवर्तनशील और कभी-कभी प्रतिस्पर्धी अभिरूचियां होती हैं। रक्षोपाय शुल्क लगाने से अलग-अलग व्यापारियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं और ये प्रभाव जब व्यापारियों के प्रतिस्पर्धी हित हों तो उन सभी के लिए हो सकता है कि यह सबसे उपयुक्त न हो। अतः विभिन्न आर्थिक व्यापारिक वर्ग के हितों का उपलब्ध सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

228. सोडा ऐश के उत्पादकों और सोडा ऐश के आयातकों/अंतः प्रयोक्ताओं ने रक्षोपाय जांच में भाग लिया। किसी भी उपभोक्ता संगठन अथवा समूह के प्रतिनिधि ने रक्षोपाय जांच में भाग नहीं लिया।

229. जनहित का विश्लेषण करने के उद्देश्य से आर्थिक व्यापारियों को तीन श्रेणियों, यथा- उत्पादक, आयातक/अंत प्रयोक्ता तथा अंतिम उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता में, विभाजित किया गया है ।

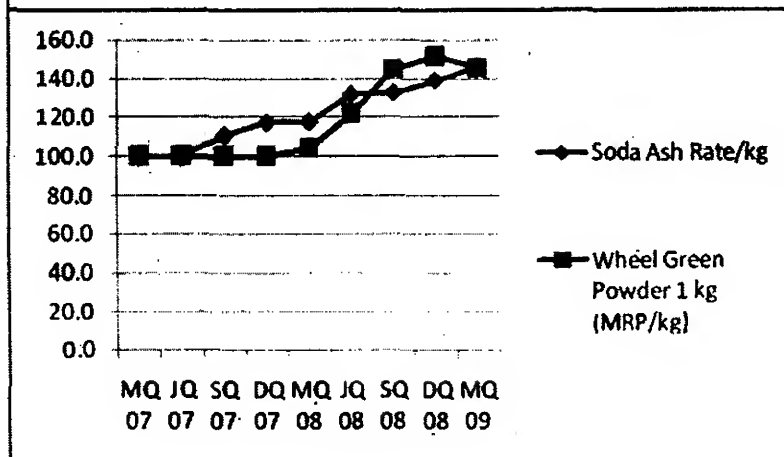
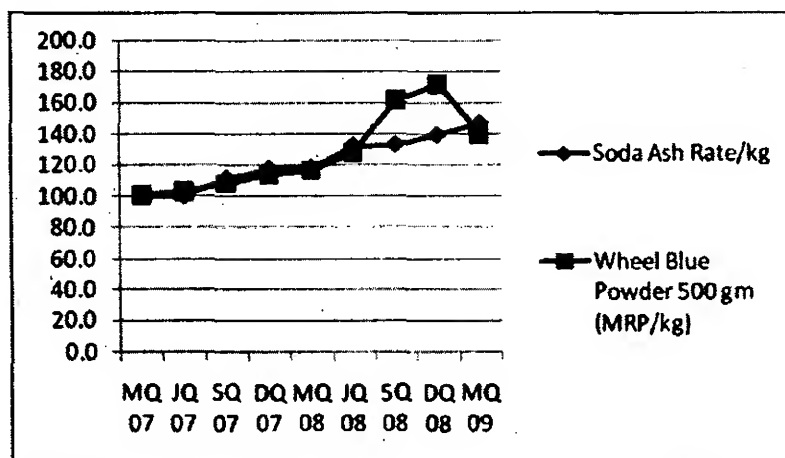
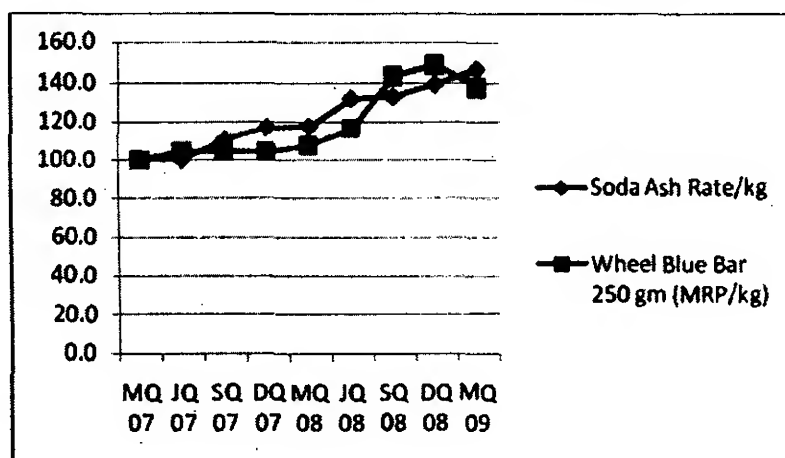
230. प्रभाव विश्लेषण करने के उद्देश्य से अंतिम उपभोक्ता तक जिस कीमत पर माल पहुंचता है, उससे संबंधित आंकड़े, वित्तीय प्रभाव से संबंधित सूचना और अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव पर सभी इच्छुक पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए हैं । परंतु, बहुत कम ने इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

231. प्रक्षालक उद्योग और शीशा उद्योग सोडा ऐश के मुख्य प्रयोक्ता हैं, जिन्होंने रक्षोपाय कार्रवाहियों में भाग लिया । इनके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, धातु उद्योग, डिसेलिनेशन प्लांट, जल आशोधन, रबड़ उद्योग, चर्म उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, भारी ड्रग्स आदि जैसे अधिसंख्य उद्योग हैं, परंतु रक्षोपाय जांच में इन उद्योगों ने कोई भागीदारी नहीं की है । सोडा ऐश उनके लिए महत्वपूर्ण लागत घटक नहीं बनाता ।

232. शीशा उद्योग : चालू शीशा उद्योग इंडोनेशिया और चीन जन. गण. से आयात हेतु 5 वर्ष की अवधि से (अर्थात् 5 जनवरी, 2014 तक) 6 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 4/2009-सी.शु. के तहत 133 अम. डा./मी. टन के पाटनरोधी संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं । चूंकि चालू शीशा उद्योग पहले ही शुल्क संरक्षण का लाभ ले रहा है, अतः रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव से उन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । इसके अतिरिक्त, सोडा ऐश संबंधी रक्षोपाय शुल्क का घातक प्रभाव पड़ने के संबंध में शीशा उद्योग ने कोई सूचना या पर्याप्त प्रमाण नहीं दिया है ।

233. प्रक्षालक उद्योग : भारत में प्रक्षालक के आयात की मात्रा 100 रु./कि.ग्रा. से अधिक के मूल्य पर लगभग चार हजार मी. टन है । आयातित प्रक्षालक का औसत सीआईएफ मूल्य 2007-08 में 54.10 रुपए/कि.ग्रा. से बढ़कर चीन से 71.18 प्रति कि.ग्रा. हो गया है और 2007-08 में 96.20 रुपए प्रति किग्रा. से बढ़कर 2008-09 में 104 रु. प्रति किग्रा. हो गया है जो कि घरेलू बाजार में कीमतों से काफी अधिक है । अधिकांश प्रक्षालक ब्राण्डों की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रु./कि.ग्रा. से कम है । इसका तात्पर्य यह है कि आयात मूल्य घरेलू बाजार में कीमतों से काफी अधिक है । आयातित प्रक्षालकों का घरेलू तौर पर उत्पादित प्रक्षालक की तुलना में कीमत लाभ नहीं है और इस प्रकार प्रक्षालकों के घरेलू उत्पादक आयातों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करते हैं ।

234. प्रक्षालक का उपभोक्ताओं पर प्रभाव : केवल मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने ही अपने उत्पादों पर एम आर पी दी है तथा सोडा ऐश की खरीद कीमतों के साथ उनके संबंध बताए हैं । यह सूचना केवल एक ब्रांड के संबंध में दी गई है क्योंकि वे उसे अपना प्रतिनिधि ब्रांड मानते हैं । इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि प्रक्षालकों के विभिन्न ब्रांडों पर अलग-अलग एम आर पी हैं और वे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वर्गों की पूर्ति करते हैं । सोडा ऐश की खरीद कीमत के साथ एम आर पी का संचलन निम्नलिखितानुसार है :-



235. उपर्युक्त रेखा चित्र यह दर्शाता है कि प्रक्षालक की एमआरपी सोडा ऐश की कीमत बढ़ जाने पर भी रेखाचित्र के आरंभिक चरण में स्थिर रही है। बाद के चरण में जब सोडा ऐश की कीमतें गिर गई तो एम आर पी बढ़ रही है। इससे यह स्पष्ट है कि सोडा ऐश की कीमत महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो प्रक्षालक की एम आर पी निर्धारित करे। अतः रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रक्षालक खण्ड के उपभोक्ताओं पर खास प्रभाव नहीं पड़ सकता।

236. जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक प्रचालन हैं। उनके हित अलग-अलग हैं और कई बार प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। इन आर्थिक प्रचालकों पर रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव भी उनके स्वरूप के कारण अलग-अलग होता है। कुछ के लिए सस्ते आयातित सोडा ऐश की उपलब्धता वित्तीय रूप से लाभकारी हो सकती है। दूसरी ओर, संवर्धित आयात से अन्य के

आर्थिक प्रचालनों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। रक्षोपाय शुल्क का निर्धारण करते समय विभिन्न आर्थिक प्रचालकों के हितों को ध्यान में रखा गया है। रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर उसके क्षतिकारी प्रभावों को कम करने हेतु आयातों को नियंत्रित करना है। 20% की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से आयात बंद नहीं होते हैं। इसके अलावा, हितबद्ध पार्टियों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चल सके कि रक्षोपाय शुल्क से उनका उद्योग अव्यवहार्य बन गया है अथवा उनकी वृद्धि में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हुआ है। अनंतिम रक्षोपाय शुल्क से अधिकतम रूप में संवर्धित आयातों के जरिए उनके द्वारा अर्जित लाभों का एक भाग निष्प्रभावी बन सकता है। तथापि, जनता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ सोडा ऐश उद्योग हो ताकि भारत में अनुषंगी प्रयोक्ता उद्योग की जरूरत को पूरा करने में सोडा ऐश का सतत एवं भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध रहे। अतः रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में है।

निष्कर्ष और सिफारिश

237. उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश की आयात वृद्धि से घरेलू उद्योग को बाजार अवरोध उत्पन्न होने का खतरा बना है। रक्षोपाय शुल्क की मात्रा निर्धारित करने में, जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा रोकने में पर्याप्त हो और सकारात्मक समायोजन सुकर बनाए, लगाई गई पूंजी पर उपर्युक्त आय पर भारित औसत बिक्री लागत तथा आयात की औसत पहुंच लागत को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार 20% के यथामूल्य की दर पर रक्षोपाय शुल्क, जो कि बाजार अवरोध से घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए न्यूनतम अपेक्षित माना गया है, सोडा ऐश के आयात पर लगाए जाने की सिफारिश की गई है जो चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात किए जाने के समय अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए उपर्युक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2838 20 के तहत आता है।

238. अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश करने वाले प्रारंभिक परिणामों, जिनके आधार पर 20 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. 37/2009-सीमाशुल्क द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया गया था, की पुष्टि की जाती है।

[फा. सं. डी-22011/02/09/5423]

प्रवीण महाजन, महानिदेशक (रक्षोपाय)

अनुबंध 1									
माह-वार आयात आंकड़े (मी. टन)									
माह	आयात मात्रा	(मी. टन)		आयात मूल्य			आयात कीमत		
	चीन से आयात	अन्य देशों से आयात	कुल आयात	चीन से आयात	अन्य देशों से आयात	कुल आयात	चीन से आयात (रु./मी. टन)	अन्य देशों से आयात (रु./मी. टन)	कुल आयात (रु./मी. टन)
अप्रैल-05	32	5,169	5,201	12	359	371	37,817	6,945	7,135
मई-05	-	12,380	12,380	-	855	855	-	6,907	6,907
जून-05	-	12,585	12,585	-	866	866	-	6,883	6,883
जुलाई-05	5,000	14,450	19,450	433	835	1,268	8,664	5,781	6,522
अगस्त-05	16	13,937	13,953	6	1,067	1,074	40,385	7,658	7,695
सित.-05	-	11,234	11,234	-	826	826	-	7,352	7,352
अक्तू.-05	-	9,433	9,433	-	718	718	-	7,611	7,611
नव.-05	-	17,430	17,430	-	1,422	1,422	-	8,158	8,158
दिस.-05	-	11,870	11,870	-	2,612	2,612	-	22,007	22,007
जन.-06	-	18,521	18,521	-	1,403	1,403	-	7,577	7,577
फर.-06	-	7,415	7,415	-	568	568	-	7,660	7,660
मार्च-06	4,000	8,345	12,345	352	664	1,016	8,794	7,956	8,228
अप्रैल-06	-	11,482	11,482	-	719	719	-	6,261	6,261
मई-06	8,907	20,541	27,448	587	1,595	2,182	8,495	7,766	7,949
जून-06	10,929	26,901	37,829	930	2,195	3,125	8,508	8,161	8,261
जुलाई-06	11,304	19,177	30,481	944	1,594	2,538	8,352	8,312	8,327
अगस्त-06	6,904	20,899	27,603	597	1,770	2,367	8,640	8,552	8,574
सित.-06	904	22,263	23,167	82	1,898	1,981	9,116	8,527	8,550
अक्तू.-06	-	25,260	25,260	-	2,171	2,171	-	8,594	8,594
नव.-06	7,929	20,232	28,161	700	1,702	2,402	8,824	8,412	8,528
दिस.-06	-	10,749	10,749	-	853	853	-	7,939	7,939
जन.-07	-	7,984	7,984	-	633	633	-	7,930	7,930
फर.-07	-	13,766	13,766	-	1,090	1,090	-	7,917	7,917
मार्च-07	16	13,576	13,592	7	1,079	1,086	44,446	7,947	7,990

अप्रैल-07	632	12,530	13,162	55	1,134	1,188	8,637	9,047	9,027
मई-07	600	20,544	21,144	55	1,580	1,635	9,115	7,891	7,731
जून-07	1,024	16,592	17,616	98	1,250	1,348	9,563	7,532	7,650
जुलाई-07	1,934	15,894	17,828	181	1,337	1,518	9,336	8,414	8,514
अगस्त-07	2,174	24,264	26,438	237	2,067	2,304	10,890	8,520	8,715
सित.-07	2,254	23,078	25,332	253	2,101	2,354	11,236	9,103	9,293
अक्तू.-07	7,233	39,286	46,518	717	3,589	4,306	9,915	9,136	9,257
नव.-07	10,032	46,301	56,332	1,017	4,387	5,404	10,139	9,474	9,593
दिस.-07	4,004	27,789	31,772	456	2,785	3,241	11,399	10,029	10,202
जन.-08	3,456	40,756	44,212	438	3,575	4,013	12,660	8,772	9,076
फर.-08	3,282	30,772	34,054	398	2,934	3,332	12,119	9,536	9,785
मार्च-08	1,066	18,705	19,771	132	1,664	1,796	12,368	8,896	9,083
अप्रैल-08	3,364	23,284	26,647	420	2,398	2,818	12,493	10,298	10,575
मई-08	3,373	11,711	15,084	439	1,229	1,669	13,026	10,496	11,062
जून-08	3,309	15,338	18,848	402	1,825	2,227	12,150	11,899	11,944
जुलाई-08	1,534	20,548	22,082	250	2,383	2,832	16,269	11,596	11,921
अगस्त-08	4,864	13,362	18,226	765	1,558	2,323	15,725	11,658	12,744
सित.-08	4,318	21,657	25,975	670	2,587	3,257	15,522	11,947	12,541
अक्तू.-08	4,191	18,126	20,317	595	2,157	2,752	14,196	13,379	13,547
नव.-08	125	6,950	7,075	16	1,144	1,160	12,765	16,459	16,393
दिस.-08	15,946	19,748	35,694	2,068	2,846	4,914	12,969	14,410	13,766
जन.-09	26,303	16,811	43,114	2,747	2,153	4,900	10,443	12,809	11,366
फर.-09	31,068	7,141	38,209	3,386	878	4,284	10,898	12,294	11,159
मार्च-09	10,253	9,825	20,078	1,069	1,123	2,192	10,424	11,428	10,916
अप्रैल-09	42,780	15,261	58,041	4,459	1,723	6,183	10,423	11,293	10,652
मई-09	42,173	10,857	53,030	4,236	1,270	5,506	10,045	11,694	10,382
जून-09	25,376	15,077	40,452	2,347	1,606	3,952	9,247	10,650	9,770

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS, CUSTOMS AND
CENTRAL EXCISE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2009

Subject : Safeguard Duty investigation against imports of Soda Ash in to India from People's Republic of China—Final Findings**G.S.R. 725(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 thereof :****A. PROCEDURE**

1. An application was filed before me Under Rules 5 of the Custom Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) , 3rd Floor, Pankaj Chambers, Preet Vihar Commercial complex , Vikas Marg, Delhi-110092, for imposition of Safeguard duty on imports of Soda Ash into India from China to protect the domestic producers of Soda Ash from market disruption or threat of market disruption caused by the increased imports from People's Republic of China. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Soda Ash into India from People's Republic of China was issued under Rule 6 of Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 on 16th January, 2009 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
2. A copy of the notice was sent to the government of People's Republic of China through their embassies in New Delhi. A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:

Domestic Producers:

1. Tata Chemicals Ltd.
Leela Business Park,
Andheri-Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai – 400 059.

2. Saurashtra Chemicals Limited,
Birlasagar,
Porbandar 360 576
Gujarat.
3. Gujarat Heavy Chemicals Limited
B-38, Institutional Area,
Sector – 1, Noida – 201 301.
4. DCW Limited,
“Nirmal” 3rd Floor,
Nariman Point,
Mumbai 400 021
5. Nirma Limited
NCC Office,
Krishna Nagar,
Wadhawadi Road,
Bhavnagar 364 002 Gujarat.
Other Indian producer :
 1. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited
East Coast Centre,
534, Anna Salai,
Teynampet,
Chennai 600 018
Importers

1. Gujarat Guardian Ltd.
Village - Kondh,
Valia Road,
Palnt Sate Highway No. - 13
Ankleshwar,
Bharuch - 393 001,
2. Float Glass India Ltd.
T - 7, Mide,
Industrial Area,
Taloja, Maharashtra,
3. Alembic Glass Industries Ltd.
Alembic Road,
Baroda (Vadodara),
Gujarat,
4. Deepak Nitrite Limited, Nandesari
4/12, Chemical Complex,
Gide,
Nanfesari,
Baroda (Vadodara)
Gujarat,
5. Hindusthan National Glass & Ind. Ltd.
Rishra,
West Bengal
6. Hindustan Uniliver Ltd.
Dakshina Building,
8th Floor, Plot No. - 2,
Sector No. - 11,

- Cbd Belapur,
Navi Mumbai,
7. Procter & Gamble Hygiene And Health Care
Mandideep Plant L & C - Mfg Plot No. - 182,
Mandideep,
Madhya Pradesh,
8. Albright Morarji & Pandit Ltd.
Ambernath,
Dist. - Thane
Maharashtra
9. Advatech Industries Pvt. Ltd., Dhanali
Village - Dhanali,
At - Kadi District,
Mahesana,
Gujarat,
10. Saint Gobain Glass Ltd.
Sriparumbathur,
Tamilnadu,

Exporters

1. Shandong Haihua Group
Shandong haihua Group Co., Ltd.
Delvelop Zone of Haihua
Weifang City,Shandong 262737,
China.
2. Hebei Tangshan Sanyou Alkali Industry Company
Nanpu Development Area,
TangShan,Hebei,

China

Postcode : 063305

3. Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass)
China's Qinghai Delhi Municipal Industrial Park

Zip:817000

4. Tianjin Soda Ash Plant
No.87 Xinhua Road

Tanggu District Tianjin

China

5. Jinshan Chemical co.
China's Zhengzhou City in Henan Province,

Zhengzhou City Fushoushan Street 87,

China

3. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.

4. Request to consider them as interested parties were received from a number of parties and all the requests were accepted. Further, requests for an extension of time to submit their replies were also made by a number of interested parties, and after taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time were allowed in all cases and the parties concerned were accordingly informed. The names and addresses of all interested parties are as follows:

- i. The Embassy of People's Republic of China 50, D Shantipath New Delhi
- ii. Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), 3rd Floor, Pankaj Chambers, Preet Vihar Commercial Complex, Vikas Marg, Delhi -92
- iii. T P M Solicitors & Consultants, K- 3/A, Saket, New Delhi.
- iv. Gujarat Heavy Chemicals Limited B-38, Institutional Area, Sector - 1, Noida - 201 301.
- v. Saurashtra Chemicals Limited, Birlasagar, Porbandar 360 576, Gujarat.
- vi. Tata Chemicals Ltd., Leela Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
- vii. DCW Limited, "Nirmal" 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021
- viii. Nirma Limited, NCC Office, Krishna Nagar, Wadhawadi Road, Bhavnagar 364 002 Gujarat.

- ix. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited, East Coast Centre, 534, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600 018
- x. Shandong Haihua Group, Shandong haihua Group Co., Ltd., Delvelop Zone of Haihua, Weifang City, Shandong 262737, China.
- xi. Hebei Tangshan Sanyou Alkali Industry Company, Nanpu Development Area, TangShan, Hebei, China: Postcode : 063305
- xii. Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass), China's Qinghai Delhi Municipal Industrial Park, Zip:817000
- xiii. Tianjin Soda Ash Plant, No.87 Xinhua Road, Tanggu District Tianjin
- xiv. China
- xv. Jinshan Chemical co., China's Zhengzhou City in Henan Province, Zhengzhou City Fushoushan Street 87, China
- xvi. Gujarat Guardian Ltd., Village – Kondh ; Valia Road, Palnt Sate Highway No. – 13, Ankleshwar, Bfaruch - 393 001,
- xvii. Float Glass India Ltd., T - 7, Midc, Industrial Area, Taloja, Maharashtra,
- xviii. Alembic Glass Industries Ltd., Alembic Road, Baroda (Vadodara), Gujarat
- xix. Deepak Nitrite Limited, Nandesari, 4/12, Chemical Complex, Gidc, Nanfesari, Baroda (Vadodara), Gujarat
- xx. Hindusthan National Glass & Ind. Ltd., Rishra, West Bengal
- xxi. Hindustan Uniliver Ltd., Dakshina Building, 8th Floor, Plot No. - 2, Sector No. - 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai,
- xxii. Procter & Gamble Hygiene And Health Care, Mandideep Plant L & C - Mfg Plot No. - 182, Mandideep, Madhya Pradesh,
- xxiii. Albright Morarji & Pandit Ltd., Ambernath, Dist. – Thane, Maharashtra
- xxiv. Advatech Industries Pvt. Ltd., Dhanali, Village - Dhanali, At - Kadi District, Mahesana, Gujarat,
- xxv. Saint Gobain Glass Ltd., Sriparumbathur, Tamilnadu.
- xxvi. U.P. GLASS MANUFACTURER SYNDICATE, 14-Monapuram, Near Ganesh Nagar, Firozabad-283203, U.P.
- xxvii. ASAHI INDIA GLASS LIMITED, 5th Floor, Tower – B, Global Business Park, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon-122002 (India).
- xxviii. FENA (P) LTD., A-237, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
- xxix. DETERGENT MANUFACTURERS ASSOCIATION (DELHI REGION) 148, New Okhla Industrial Complex-I, New Delhi-110020
- xxx. SAINT GOBAIN, Plot No. A-1, Sipcot Industrial Park, Sriperumbudur-602105, Kanchipuram District, Tamil Nadu.
- xxxi. SACI-CHEM, 59 & 60, DSIDC Industrial Complex, Okhla, Phase-I, a. New Delhi-110020.
- xxxii. SHREE UNICON ORGANICS P. LTD., BS-3, Apeejay, 130, Bombay Samachar Marg, Mumbai-400023.
- xxxiii. CAPEXIL, VANIJYA BHAVAN, INTERNATIONAL Trade Facilitation Centre, I/1, Wood Street, 3rd Floor, Kolkata-700016.
- xxxiv. POLLACHI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, R.P. Complex, II Nd Floor, 14, Balagopalapuram Street, Pollachi-642001.

- xxxv. VASUNDHARA RASAYAN LTD., C-104, MIDC Industrial Area, Mahed, Dist. Raigad, Maharashtra
- xxxvi. SMALL SCALE DETERGENTS & SOAP MFRS. ASSOCIATION
- xxxvii. 43, European Asylum Lane, Kolkata-700016
- xxxviii. POWER SOAP LTD., 62-B, North Boag Road, T. Nagar, Chennai- 600017, India
- xxxix. SHANTI NATH DETERGENTS(P) LTD,P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007.
- xl. ADVANCE HOME & PERSONAL CARE LTD., Advance Surfactants India Ltd.,511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-110038
- xli. ALL INDIA FEDERATION OF DETERGENT MFRS. ASSOCIATION, 511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-110038
- xl.ii. S. KUMAR DETERGENT P. LTD, Plot No. 34, sector-2, Industrial Area, Pithampur-454775 Dist. Dhar, M.P.
- xl.iii. Advance Surfactants India Ltd.,511/2/1, Village Rajokri,New Delhi-110038
- xl.iv. A.R. Sulphonates, 9, Hemanta basu Sarani, (20, Old Court House Street), 2nd Floor, Cooke and Kelvey Building, Kolkata-700001
- xl.v. Sai Sulphonates, 21, Princep street, 2 nd Floor,Kolkata-700072
- xl.vi. A.R. Stanchem Pvt. Ltd, 9, Hemanta basu Sarani, (20, Old Court House Street), 2nd Floor, Cooke and Kelvey Building, Kolkata-700001
- xl.vii. Hind Silicates Pvt. Ltd., 3A, Auckland Place, 5th Floor, Kolkata-700017
- xl.viii. Taurus Chemicals (P) Ltd., 318, Swapnalok, 92/93, S.D. Road, Secunderabad-500003, A.P., India
- xl.ix. P & J Cretechem (P) Ltd., 318, Swapnalok, 92/93, S.D. Road, Secunderabad-500003, A.P. India
- l. Kishoresons Detergents Pvt. Ltd., 15-9-469, Mahaboobgunj Rd, Hyderabad-500012
- li. Gopal Agencies, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004.
- lii. J.J. Patel Industries, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004.
- lii.iii. Shriram Bharath Chemicals & Detergents (P) Ltd., 1/56, Sanjay Gandhi Nagar, Nochipalayam Road,46, Podhur Village,ERODE-638002
- liv. Indian Chemical Merchants & Manufacturers Association, 4, India Exchange Place, Kolkata-700001
- lv. President, Bulk Drug Manufacturers Association (India), C-25, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500018
- lv.ii. Indian Council of Small Industries, 19/2, Banamali Naskar Road, 2nd Floor, Kolkata-700060
- lv.iii. The All India Glass Manufacturers' Federation, 812, New Delhi House, 27 Barakhambha Road, New Delhi-110001.
- lv.iii. Crescent Silicate, A-45, Gane Khadpoli M.I.D.C. Chiplun, Dist. Ratnagiri-415604
- lix. Gandhi Chemical Works, F-41, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006
- lx. Ministry of Commerce of The People's Republic of the China 2, Dong Chang' A Street, Beijing, China,100731
- lx.ii. Modern Glass Industires, Coal Siding Road, Firozabad-283203 (U.P)

- lxii. Adarsh Kanch Udyog (P) Ltd., Coal Siding Road, Firozabad-283203 (U.P)
- lxiii. Advance Lamp Component & Table Wares Pvt. Ltd., E-24, IInd Floor Jawahar Park, Laxmi Nagar, Vikas Marg, New Delhi-110092
- lxiv. Pragati Glass Pvt. Ltd., 111, Damji Shamji Industrial Complex, 9, LBS Kurla (W) Mumbai-400070
- lxv. Gora Mal Hari Ram Ltd., 39 Najafgarh Road Ind. Area, New Delhi-110015
- lxvi. Rohit Surfactants(P) Ltd., 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur-05
- lxvii. Astral Glass Pvt. Ltd., Adinath Towers 'A', 2nd Floor, Nancy Colony, Off .Western Express Highway Borivali (EAST), Mumbai-400066
- lxviii. BDJ Glass Industries Pvt. Ltd., 1 Kyd Street, Place Court, 1st Floor, Suite - 14 A, Kolkata- 700016
- lxix. Indian Glass Manufacturers' Association, B-6, Shivalik, New Delhi-110017
- lxx. The Dyes & Chemical Merchants Association, 4 Mandir Street, Kolkata-700073
- lxxi. Hipolin Limited, "Madhuban", 4th Floor, Ellisbridge, Ahmedabad-380006
- lxxii. The Federation of all India Dyes & Chemicals Merchants Association 16, Maharana Pratap Sarani, 2nd Floor, Room No. 5, Kolkata -700001
- lxxiii. Athena Law Association, 808, L & T Building, Sector - 18B, Dwarka, New Delhi-110075
- lxxiv. Lakshmi Kumarn & Sridharan, B-6/10, Safdarjang Enclave, New Delhi-110029
- lxxv. Shri Hari Industries, 47, Shree Veerbhai Maa Niwas, Shastri Nagar Square, Nagpur-440008
- lxxvi. Maharashtra Small Scale Soap, Detergent & Cosmetic Manufacturers Association, 47, Shree Veerbal Maa Niwas, Shastri Nagar Square, Nagpur-8
- lxxvii. Hindusthan National Glass & Industries Ltd., 2, Red Cross Place, Kolkata-700001
- lxxviii. Jagatjit Industries Limited, Plot No. 78, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon-122001
- lxxix. Indian Council of Small Industries, 19/2, Banamali Naskar Road, 2nd Floor, Kolkata-700060
- lxxx. Pitamber Glass Works, Chameli Bagh, Agra Road, Firozabad-283203
- lxxxi. Ashoke Enamel & Glass Works Private Limited, 34A, Metcalfe Street, 1st Floor, Kolkata-700013
- lxxxii. Advance Lamp Component & Table Wares Private Limited, E-24, IInd Floor, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi-110092
- lxxxiii. Haldyn Glass Gujarat Limited, 9, Gayatri Commercial Complex, Behind Mittal Industrial estate No. 5, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai-400059
- lxxxiv. AGI Glasspac, 2, Red Cross Place, Kolkata-700001
- lxxxv. Piramal Glass, Piramal Tower Peninsula Corporate Park Ganpatrao Kadam Marg, Lower parel, Mumbai-400013
- lxxxvi. Ganesh Beads Industries, Dholpura, Near Industrial Area, Agra Road, Firozabad-283203
- lxxxvii. Shri Jagdamba Industries, B-13, Industrial Area, Firozabad-283203
- lxxxviii. Empire Industries Limited, Empire House, 414, Senapati Bapat, Lower Parel, Mumbai-400013

- lxxxix. Adarsh Kanch Udyog (P) Ltd., Coal Siding Road, Firozabad-283203
xc. Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
xci. Bharat Glass Tube Ltd., 501, 5th Floor, Astron Tower, Satellite, Ahmedabad-380015

5. After expeditious conduct of investigation preliminary findings were issued on 30th January 2009. The provisional duties were levied on 20.04.2009 vide notification no.37/2009 - Customs, dated, 20.04.2009 at the rate of 20 per cent. *ad valorem* on import of Soda Ash, falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the said Act, when imported into India from the People's Republic of China. The safeguard duty imposed under this notification has been made effective up to and inclusive of the 5th November, 2009 unless revoked, superseded or amended earlier.
6. A public hearing was held on 23rd March 2009, notice for which was sent on 25th February, 2009. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties. The period of investigation was extended till 15th October, 2009 by the Central Government.
7. Another public hearing was held on 7th August 2009, notice for which was sent on 17th July, 2009. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties.
8. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination. As there are large number of interested parties who have filed their submissions, their contentions and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places without making specific name of the interested party for the sake of brevity.
9. The information presented by domestic producers was verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. Further, the cost data has also been verified and certified by cost accountant. The non confidential version of verification report is kept in the public file.

Views of domestic producers in India

10. The domestic producers have stated as follows:

11. The application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of M/s Tata Chemicals Ltd. Andheri (East), Mumbai, M/s Gujarat Heavy Chemicals Limited, Noida, M/s Saurashtra Chemicals Limited, Birla Sagar, Porbandar, Gujarat, M/s DCW Ltd, Nariman Point, Mumbai and M/s Nirma Ltd., Bhavnagar, Gujarat. The applicants have made following major points:-
12. The applicants have alleged that increased imports of Disodium Carbonate popularly known as Soda Ash from China into India have threatened to cause market disruption to domestic industry. The product has chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. Soda Ash is classified as below:

Name of the Products	HSN Chapter Heading	Customs Tariff Heading	ITC Heading
Soda ash	2836.20	28362010	28362010
		28362020	28362020
		28362090	28362090

13. They have alleged that surge in imports are taking place at lower prices making them lose their market share.
14. The increased imports at lower prices are on account of certain developments in China which are as mentioned below:
- GDP growth through August 2008 pegged at 10.5%. Indicators are that through 2009 GDP will taper down to around 5-6%. This would leave large volume of excess capacity in China.
 - Post the Olympic Games and the Global Financial Crisis, China has witnessed sharp downturn in industrial activity leading to decline in demand for soda ash as well.
 - Soda ash demand estimate revised downward to 5%-6% / year from the earlier projection of 10%+ / year. This will reduce Chinese demand by 2 million MT / year.
 - All exports specially those of Chemicals/Plastics/Textiles/ Toys etc which largely depended on US and Europe are hit drastically. Resultantly, exports of soda ash to these markets have also been hit, leaving significant surpluses with Chinese producers.
 - Government announced support measures for upliftment of Rural Agricultural Sectors. This prevented closure of some plants, which would have happened in the absence of these measures.

- vi. Like almost all economies, reality sector specially housing has been adversely affected. Real Estate prices are sliding and there are very few buyers. These have impacted demand for a number of products including demand for soda ash.
 - viii. Slow down in housing affecting infrastructure industries like Cement, Steel and Glass.
 - x. 35 Float Glass lines both small and medium sizes reportedly closed down in the last 2 months and others operating at reduced production rates. Float glass being one of the major consumer of soda ash, this has resulted in large surplus capacity.
 - xii. Capacity ramp up in 2007-08 in soda ash industry have been in line with projections.
 - xiii. China capacities in mid 2008 were reportedly at 22million MT constituting of 7 large manufacturers and about 44 small manufacturers. 3.5 million MT already added in last 18 months (up from 18.5 Million MT). Further announcements of about 5 million MT on hand (may or may not come on stream depending on demand supply situation). Chinese soda ash production capacity is expected to reach at 26 and 28 million MT in 2009 and 2010 respectively
 - xiv. Shandong-Haitai has added 1 million MT in September 2008 and commercial production has commenced. Once fully commercial, this would release 1 million MT soda ash in the market.
 - xvi. Post Olympics witnessed serious downturn in consumption along with ripple effect of added inventories due to logistics slow down during games.
 - xvii. No Soda Ash plant had to close during games as was earlier visualized. Because of this, the soda ash producers had built up high inventories and are now saddled with stocks. Added inventories and continuing record production have led to very high inventories.
 - xix. Glass industry in China is not doing good. Followings are relevant in this regard.
 - xxi. Float Glass going through severe pressure.
 - xxii. Inventories added up during Olympic Games could not be liquidated owing to serious financial crunch in the sector in September – October.
 - xxiii. Real Estate trend down by 25 – 30 % “No Buyers” available.
 - xxiv. 30 Float Glass units reportedly closed on account of high inventory and no domestic demand.
 - xxv. Dense Soda Ash demand which was hitherto tight has also become very weak.
 - xxvi. The demand for detergent is also falling subsequent to slow down. Detergent industry which was growing by +10% PA till 2007 has recorded marginally negative growth in 2008.
 - xxvii. Demand for soda ash in aluminium industry is also falling on account of falling consumption of Soda Ash in the Aluminium sector.
15. Their inventory is on sharp rise, even after lower production.

16. The transportation cost forms a very substantial portion in cost to make and sell the subject goods. To compound the problems further, while the Indian Producers of soda ash are located in the State of Gujarat (due to availability of raw material), the sales have to be made throughout India. Further, the subject goods is a comparatively lower price product. Thus, the incidence of transportation cost per MT of the product works out very substantial when compared with the selling price of the product.
17. Their profitability has gone down drastically and the danger of their wipe out is imminent.
18. India is self sufficient in soda ash. There is no demand supply gap and imports are not necessitated on this account.
19. The Chinese exports have previous history of causing injury to the Indian Producers. Anti dumping duties earlier imposed is relied upon.
20. Chinese exporters or importers have not filed any questionnaire response in the form and manner prescribed.
21. Interested parties have not availed opportunity to represent their interests in a timely manner, which is mandatory under the Rules.
22. The petitioner has provided three sources of data – DGCI&S, IBIS and China customs. Further, Directorate of Valuation data is also available to the Director General. The Director General may rely upon best available information after considering imports reported by the three sources.
23. Whereas export price from China to India was lower than global price during 2005-06 and 2006-07, the prices for India were higher than global prices during the period April 07-September 08. However, not only the trend has once again got reversed from Oct.08, but also the price difference was phenomenal in Nov. and Dec.08. Consequently, whereas exports to other global markets have steeply declined from August 08, exports to India have very steeply increased
24. Whereas import price from China was higher than import price from other countries upto Sept. 2008, the trend got reversed during Oct. 2008 and the import price from China are now materially lower than import price from other countries. Consequently, whereas import volumes from third countries were increasing between 1999-00 and 2007-08, the trend has reversed thereafter with Chinese imports rapidly increasing and third country imports significantly declining.
25. All Indian Producers are participating in the present investigations and have provided all relevant information with regard to injury to the domestic industry.
26. Both light & dense soda ash is included in the present scope of the product. Both are being imported from China and both are being supplied by the domestic industry.
27. Soda ash forms anywhere about 12-15% of selling price of detergent for popular low priced brands to 3-5% for premium brands. About 40% of variable cost of glass is soda ash.

28. Imports have increased in absolute terms as also in relation to total imports, domestic production and domestic consumption.
29. With the current onset of global recession, the Chinese producers are faced with the problem of increased capacities on the one hand and reduction in Chinese and global demand on the other hand. Decline in Chinese domestic demand for soda ash, decline in global exports from China, significant decline in prices both in domestic and overseas, addition of fresh capacities in China, enhancement in capacities by existing producers in China without proportionate increase in domestic demand and in spite of existing surpluses clearly constitute unforeseen circumstances leading to increased imports.
30. Alarming increase in volumes to India is solely because of equally alarming and specifically targeted price reductions offered by the Chinese suppliers (in Indian market) due to severe demand pressure on them.
31. During the period Aug 08-Dec 08 China's export prices have declined by 16% to "Rest of the World", whereas decline in case of India is an alarming 37%.
32. Huge price difference between the domestic soda ash and import price is motivating even small volume consumers to look for imported soda ash
33. With regard to serious injury, the domestic industry has made following submissions
34. Chinese imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market.
35. Performance of the domestic industry was improving before the current surge in imports. The performance of the domestic industry, however, deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales volumes, inventories, selling prices, employment, profitability, market share, return on investment, growth, etc.
36. Increased Chinese imports are in addition posing threat of market disruption. This is clearly established by parameters such as rate of increase in imports, price difference between domestic and imported product, freely disposable production capacities with the Chinese producers. Further, the threat has continued even after imposition of interim safeguard duty, given that the Chinese producers continue to suffer from significant freely disposable production capacities.
37. The profitability of the domestic industry slightly improved in Jan.-June, 09 period. Performance has however once again deteriorated steeply in July-Sept., 09 period inspite of 20% safeguard duty imposed.
38. Soda ash industry has some cyclicity in as much as production & sales increase after monsoon and upto March and then decline thereafter till monsoon. This trend can easily be established by the month wise statistics from April, 2005 till most recent period. However, the increase in sales volumes after 2008 monsoon was far less and decline in sales volumes thereafter till 2009 monsoon was far more than previous periods this time, solely because of increased imports.

39. Injury to the domestic industry has been caused by increased imports. Factors other than increased imports such imports from third countries, changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, export performance, etc. have not caused injury to the domestic industry. Further, significant increase in Chinese imports, increase in market share of China & consequent decline in market share of domestic industry, increase in sales less than what the rates experienced in the past after Sept., 08 and decline in sales after March, 09 more than rates experienced earlier clearly establishes that injury to the domestic industry has been caused by increased imports.
40. Imposition of safeguard duty is in public interest.
41. Increase or high volume of imports even after imposition of safeguard duty clearly establishes that the current quantum of safeguard duty is grossly inadequate.

Views of the Government of China and Exporters

42. The Government of China, China Soda Industry Association (CISA), China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCME) through his consultant and others have made following submissions:
43. Before proceeding to initiate an investigation, consultations should have been held in terms of Article 16.1 of CAP. They argued that this is an investigation for imposing Transitional Product-Specific Safeguard Measures (TPSSM) as contemplated under Article 16 of China's Accession Protocol to WTO (CAP). Article 16.1 of CAP requires prior consultation. The Article 16.1 reads as follows:

16. Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism

1. In cases where products of Chinese origin are being imported into the territory of any WTO Member in such increased quantities or under such conditions as to cause or threaten to cause market disruption to the domestic producers of like or directly competitive products, the WTO Member so affected may request consultations with China with a view to seeking a mutually satisfactory solution, including whether the affected WTO Member should pursue application of a measure under the Agreement on Safeguards. Any such request shall be notified immediately to the Committee on Safeguards."

44. However, GOC regrets to note that the Investigating Authority failed to provide such consultation opportunity before the initiation of the investigation. From the time prior to the initiation of investigation till date (even after the approval of preliminary findings), no communication has been received by GOC through proper channels. In the opinion of

- GOC, this runs not only against the basic principles of WTO but also runs counter to the obligations to be assumed by the Investigating Authority. Consequently, this has seriously deprived the rights of GOC.
45. The words '*seeking mutually satisfactory solution, including whether the affected WTO Member should pursue application of a measure under the Agreement on Safeguards*' appearing in Article 16.1 of CAP clearly imply that no investigation should have been initiated without prior consultation.
 46. In this particular case, India did not seek consultations with China under Article 16.1 of CAP. As a WTO Member, the basic WTO principles to be adhered to and the obligations to be assumed shall not be ignored or reduced by any means when conducting an investigation. Since no opportunity of consultation under Article 16.1 of CAP has been provided to GOC, the TPSSM investigation should be terminated immediately.
 47. They also contended that there is no sufficient evidence of increased imports causing market disruption or threat of market disruption.
 48. The Period of investigation has been changed by insertion of new data, which is not correct.
 49. With regard to the Petitioner's allegation of a sharp rise in imports, the source of the data on which the Petitioner is making this allegation is not clear. The Petitioner cites to a number of sources for its subject merchandise import figures, namely IBIS, DGCIS, Chinese customs, and industry estimates. However, none of these sources provide consistent data on imports from China.
 50. The average weekly production in recent months is *higher than* both the average weekly production in the base period as well as the years 2006-07 and 2007-08. The fact that the production listed for the most recent period (i.e., January 1-7, 2009) has declined does not indicate an overall decline in industry production. The domestic sales for 2007-08 were 1,765,322 MT. On a pro rata basis for the next 6 months, it should have been 882,661 MT. However, actual domestic sales during the next 6 months i.e. from April to September 2008 were higher at 892,577 MT. Thus, there was no fall in domestic sales as per petition. The imports from China PR were 45,771 Mt during 2007-08. On a pro-rata basis, it should have been 22,886 MT during the next six months. However, actual imports during April-September 2008 were 22,907 MT – an increase of just about 21 MT. Further, data contained in Annexure 8 of the petition shows that the per-unit selling price for each of the Petitioner companies listed therein has *increased* for the period April-September 2008 vis-à-vis per-unit prices in 2007-08. Furthermore, the total sales quantity for 3 of these companies (i.e., Nirma, GHCL and TCL) is up vis-à-vis a 6-month period for the year 2007-08. With regard to profits, Annexure 8 reveals that three of the five petitioner-companies (i.e., DCW, GHCL and TCL) experienced an improved profit-loss situation in April-September 2008 vis-à-vis the period 2007-08. These three companies together comprise almost 70% of total sales quantity for the petitioner

companies. It is difficult to see how the Petitioner can make such claims of falling profits in good faith when the overwhelming majority of the domestic industry is experiencing increased profits.

51. Other claims made in the petition like a fall in exports to the US and EU; a decline in Chinese demand for soda ash following the Olympic games; PRC government actions which have prevented the closure of soda ash plants in China etc are not supported by any evidence.
52. Petition is grossly deficient and therefore, initiation does not meet the requirements of Rule 5. If the requirements of Rule 5 are not met, the DG does not acquire the jurisdiction to initiate the investigation. Thus, initiation is without jurisdiction and no measures can be imposed pursuant to such an initiation.
53. The preliminary finding issued by DG (SG) was not approved by the Standing Board on Safeguards in its meeting held on 13 February 2009. Standing Board had clearly mentioned that no case had been made out for imposition of duty in the preliminary findings and that the DG (SG) should examine a number of other issues. It is learnt that the DG (SG) did a further examination of the issues pursuant to the minutes of the meeting and filed a subsequent report with the Standing Board. Based on the subsequent report, Standing Board approved imposition of provisional safeguard duty at the rate of 20%. As a public notice of the revised preliminary findings was not issued, no provisional duty could have been imposed.
54. Besides these, import data and production data listed in the preliminary findings does not match the data provided in the petition.
55. There is no market disruption, as the fall in sales is miniscule.
56. There is significant imports from other countries, where the applicant industries own manufacturing facilities. Thus, they are using TPSSM as a measure not to protect their Indian operations but to ensure a free market to export from Kenya or Romania. TPSSM is not intended to serve such purposes.
57. Assuming the market disruption, the market disruption is not on account of imports.
58. Soda ash is used in an array of industries for manufacturing various finished products. Any imposition of safeguard duty is going to adversely affect the end users and consumers of a variety of products.
59. It is not clear what the 31% figure provided in the preliminary findings is based on. For example, it is not clear if this margin was calculated based on a comparison at the ex-factory level, or if it was calculated using a landed value that was based on China customs data. China customs data normally gives FOB prices ex-China.
60. Regarding the letter of DG sent to BOS, the reliance on a decision of European Commission is not correct as it does not support his claim at all. Firstly, this decision is not considered as good law among the scholars of Trade Law. It is an open secret the

European Commission's decision was driven by political reasons and it was retaliation against the restrictive actions of USA on imports of steel.

Views of Importers/users industries

61. The Detergent Manufacturers Association (Delhi Region) Regd. / All India Federation of Detergent Manufacturers (AIFDM) made the following submissions through his counsel:
62. Preliminary Objection: The domestic industry had come out with completely new set of data during the Public Hearing held on Aug. 7, 2009. It is strongly objected as the interested parties are not able to understand what the claim of domestic industry is. A Safeguard Investigation cannot be said to be a continuing investigation. The DG must determine the period of injury so that all interested parties are able to offer their comments thereon. It is submitted that no data relating to the period subsequent to the initiation of the investigation should be considered by DG(SG) in arriving at the final findings. In this regard, the earlier decision of DG(SG) in the safeguard investigation concerning Carbon Black – final findings dated 1st July 1998 is also referred, whereby the DG had not extended the period of investigation.
63. Deficiencies in the petition: With regard to the Petitioner's allegation of a sharp rise in imports, the source of the data on which the Petitioner is making this allegation is not clear. The Petitioner cites to a number of sources for its subject merchandise import figures, namely IBIS, DGCIS, Chinese customs, and industry estimates. However, none of these sources provide consistent data on imports from China. Accordingly, it is respectfully submitted that the DG must rely on one consistent source for the subject merchandise import figures in reaching its final determination. Further, Section 8C(1) of Customs Tariff Act 1975 talks about "increased imports into India" and not "exports from China". When the section says 'imports into India', one cannot take exports from China as the basis for making the determination. Therefore, considering China Customs Data which is nothing but exports from China and 'not' imports into India should not be considered by the DG Safeguards.
64. No evidence regarding market disruption was contained in the petition: The average weekly production in recent months is higher than both the average weekly production in the base period as well as the years 2006-07 and 2007-08. The fact that the production listed for the most recent period (i.e., January 1-7, 2009) has declined does not indicate an overall decline in industry production. The domestic sales for 2007-08 were 1,765,322 MT. On a pro rata basis for the next 6 months, it should have been 882,661 MT. However, actual domestic sales during the next 6 months i.e. from April to September 2008 were higher at 892,577 MT. Thus, there was no fall in domestic sales as per petition. The imports from China PR were 45,771 Mt during 2007-08. On a pro-rata basis, it should have been 22,886 MT during the next six months. However, actual

imports during April-September 2008 were 22,907 MT – an increase of just about 21 MT. Further, data contained in Annexure 8 of the petition shows that the per-unit selling price for each of the Petitioner companies listed therein has increased for the period April-September 2008 vis-à-vis per-unit prices in 2007-08. Furthermore, the total sales quantity for 3 of these companies (i.e., Nirma, GHCL and TCL) is up vis-à-vis a 6-month period for the year 2007-08. With regard to profits, Annexure 8 reveals that three of the five petitioner-companies (i.e., DCW, GHCL and TCL) experienced an improved profit-loss situation in April-September 2008 vis-à-vis the period 2007-08. These three companies together comprise almost 70% of total sales quantity for the petitioner companies. It is difficult to see how the Petitioner can make such claims of falling profits in good faith when the overwhelming majority of the domestic industry is experiencing increased profits.

65. Other claims made in the petition are also not supported by any evidence: The Petitioner has further alleged increasing inventories of soda ash amongst Chinese producers resulting from an economic slowdown in China and a fall in exports to the US and EU; a decline in Chinese demand for soda ash following the Olympic games; PRC government actions which have prevented the closure of soda ash plants in China; Chinese soda ash capacity having been “ramped up” in 2007-08 and Chinese capacities in mid-2008 “reportedly” being 22 million MT; a slowdown in and consequent declining demand for soda ash by the Chinese the float glass, detergent, and aluminum industries, etc. For all these no evidence has been provided to support these blanket claims.
66. Petition is grossly deficient and therefore, initiation does not meet the requirements of Rule 5: In view of the innumerable deficiencies in the petition described above, the petition is grossly deficient and did not meet the requirements of Rule 5(2). Accordingly, DG Safeguards could never have satisfied himself as to the accuracy and adequacy of the evidence presented in the petition to justify initiation of the investigation. Therefore, the initiation itself does not meet the requirements of Rule 5. If the requirements of Rule 5 are not met, the DG does not acquire the jurisdiction to initiate the investigation. Thus, initiation is without jurisdiction and no measures can be imposed pursuant to such an initiation.
67. Procedural lapses in the initiation of the investigation: In spite of the express provision in Article 16.1 of the Accession Protocol and shared understanding among Member countries on the need of consultations, The Government of China has not been informed about the present TPSS investigation through official channels.
68. Further, the preliminary finding issued by DG (SG) was not approved by the Standing Board on Safeguards in its meeting held on 13 February 2009. Standing Board had clearly mentioned that no case had been made out for imposition of duty in the preliminary findings and that the DG (SG) should examine a number of other issues. We understand that the DG (SG) did a further examination of the issues pursuant to the

minutes of the meeting and filed a subsequent report with the Standing Board. Based on the subsequent report, Standing Board approved imposition of provisional safeguard duty at the rate of 20%. As a public notice of the revised preliminary findings was not issued, no provisional duty could have been imposed.

69. Besides these, import data and production data listed in the preliminary findings does not match the data provided in the petition.
70. There is no market disruption, as the fall in sales is miniscule.
71. Two of the domestic producers own manufacturing facilities abroad. TATA Chemicals took over Magadi Soda in Kenya in December 2005. There is only one producer in Kenya. Imports from Kenya are significantly higher than the imports from China. Similarly, GHCL took over S C Bega Upsom S A in Romania in 2005. Imports from Romania were the highest till 2007-08. Even during 2008-09, significant quantities have been imported from Romania. Both these domestic producers (i.e., TATA Chemicals and GHCL) want to protect their ability to export from Kenya/Romania to India. If safeguard measures are imposed against those countries, their imports from Kenya/Romania will be adversely affected. Therefore, they have chosen the TPSSM measure targeting only the imports from China. Once the Chinese imports are blocked, they will have no problem in importing from their related companies in Kenya/Romania. Thus, they are using TPSSM as a measure not to protect their Indian operations but to ensure a free market to export from Kenya or Romania. TPSSM is not intended to serve such purposes.
72. Assuming that there is market disruption, the market disruption is not on account of imports.
73. Public Interest: Soda ash is used in an array of industries for manufacturing various finished products. A non-exhaustive list of the same has been provided below:
 - i. Household Detergents
 - ii. Soaps
 - iii. Cleaning Compounds
 - iv. Float Glass
 - v. Container and specialty Glasses
 - vi. Large variety of heavy & industrial chemicals
 - vii. Extensively used in
 - viii. Textile Industry
 - ix. Paper Industry
 - x. Metallurgical Industries
 - xi. Desalination Plants
 - xii. Water Treatment
 - xiii. Rubber Industry
 - xiv. Leather Industry
 - xv. Aluminium Industry

- xvi. Soda Ash is also a key ingredient in the manufacture of
 - xvii. Bulk Drugs
 - xviii. Saccharin
 - xix. Safolin
74. Given this myriad uses of soda ash, it is obvious that any imposition of safeguard duty is going to adversely affect the end users and consumers of a variety of products. It would further result into undue benefit for integrated producers like Nirma. Once the imports from China are subjected to safeguard duty, the domestic industry would easily import from its affiliates in Kenya and Romania and hike prices at the cost of the interest of the end users and consumers.
75. The cartel-like nature of the domestic industry is evident from its pricing behavior (i.e., the Petitioner companies charge a uniform price). As such, the pricing pattern of the domestic industry should be disregarded by the Authority in reaching a final determination on market disruption or the threat thereof.
76. Calculation of Safeguard Duty: It is not clear what the 31% figure provided in the preliminary findings is based on. For example, it is not clear if this margin was calculated based on a comparison at the ex-factory level, or if it was calculated using a landed value that was based on China customs data. China customs data normally gives FOB prices ex-China.
77. Regarding the letter of DG sent to BOS, the reliance on a decision of European Commission is not correct as it does not support his claim at all. Firstly, this decision is not considered as good law among the scholars of Trade Law. It is an open secret the European Commission's decision was driven by political reasons and it was retaliation against the restrictive actions of USA on imports of steel.

The representatives of M/s Hindustan levers have made following submissions:

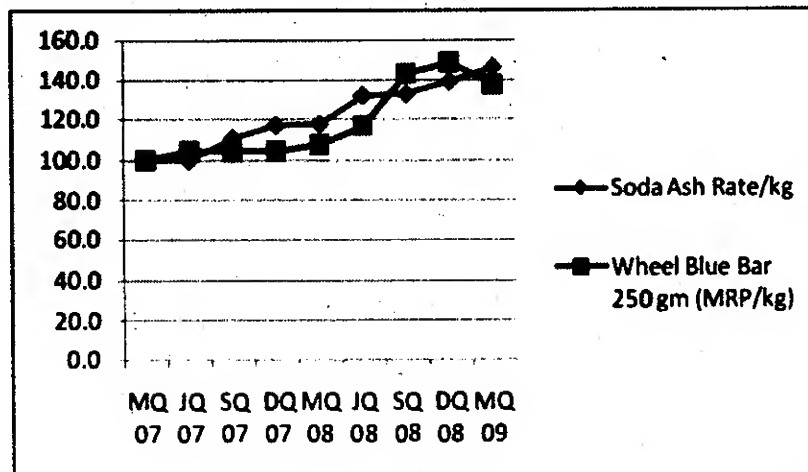
78. A safeguard measure is based on a "no fault principle" and is applied on imports that are made fairly and not with the intention to hurt the domestic industry. As such the bar for proving market disruption, or even considering the application of a safeguards measure is higher than that of other trade remedies. Furthermore, interpretations need to be construed as narrowly as possible so as to minimize the impact on free trade.
79. The applicant has relied upon various sources of data for their own convenience and failed to provide a cogent reason for this switch from one data source to another provided by DGCI&S and IBIS to data provided by China Customs and "industry estimates".
80. Multiple sources of data used in the petition as well as the preliminary findings.
81. There are many discrepancies in the figures provided in the petition. The information provided in the petition and that in the preliminary findings do not match at some places.

82. Confidentiality: The petition has failed to provide critical data available in the public domain under the guise of confidentiality, as also various parts of the petition have been left blank without providing valid reason for keeping it confidential. For example the petition states that Annexure 2 to the petition contains data for country wise imports, including China, of soda ash. This data is sourced by the applicants from DGCI&S and IBIS. Therefore it is hard to contemplate why said data would be confidential. Further the petition fails to provide any reasons for seeking confidentiality.
83. Failure to provide a clear “period of investigation” : The WTO Agreement on Safeguards and the Rules do not provide a definition for the “period of investigation”. In fact the term period of investigation is nowhere to be found in the both the Safeguards Agreement and the Rules. However, the Director General has dealt with the issue of period of investigation in the past. In *Carbon Black case* the investigation had been initiated on February 5, 1998 and the applicants had submitted data up to September 1997. Thus when the applicants tried to introduce new evidence of recent events the Director General refused to accept the data on the ground that it would not be fair to change this reference period as various interested parties respond with reference to the facts available during this period. In the present case the applicants have sought to introduce new data beyond the reference period i.e. starting 2005-2006 to September, 2008, in the petition, initiation, preliminary finding and recently during the public hearing. We therefore, in light of the Director Generals consistent practice, request the Director General to limit the “period of investigation” from April 2005 to September 2008.
84. Problems with the initiation and preliminary findings: The notice of initiation for the investigation of imports of soda ash from China was issued on January 16, 2009. The said notice provided concerned parties to make their representations by the February 16, 2006. However the Director General issued his preliminary findings on January 30, 2009. This preliminary finding was issued in violation of basic principle of administrative law, i.e. audi alteram partem which says that nobody should be condemned unheard. This principle has been repeatedly recognized by the Hon’ble Supreme Court in *State of Haryana v. Rama Kishan & Others* (AIR 1988 SC 1301). Further this is not just a violation of the rules of natural justice, but also a violation of the Rules. Rule 6 contains the principles governing an investigation. Rule 6 sub rule 5 provides that the Director General shall provide an opportunity to the industrial users to be heard.
85. No surge in imports: The applicants have failed to prove that there has been a dramatic increase in imports. A plain perusal of the data provided in the petition shows that there is clearly no surge in imports. A glance at the table on page 6 of the petition shows that there was no dramatic surge in imports from April 2006 to September 2008.
86. No dramatic fall in sales or reduction in market share of the applicants: A safeguard measure may be imposed if there has been a change in level of sales or production. Data presented in the petition as well as the preliminary findings shows otherwise. Annexure

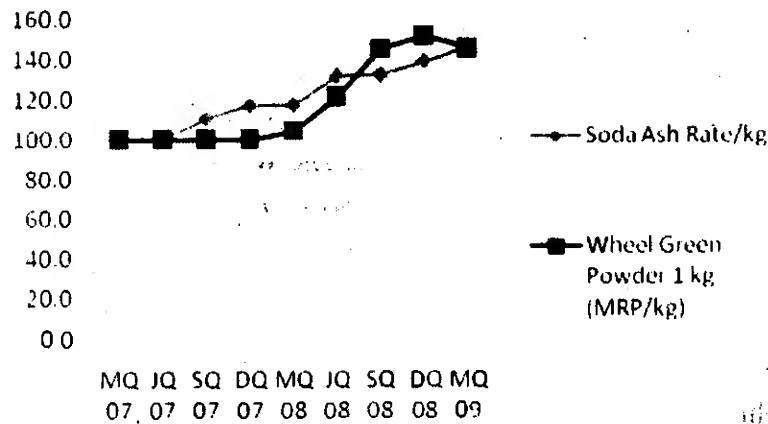
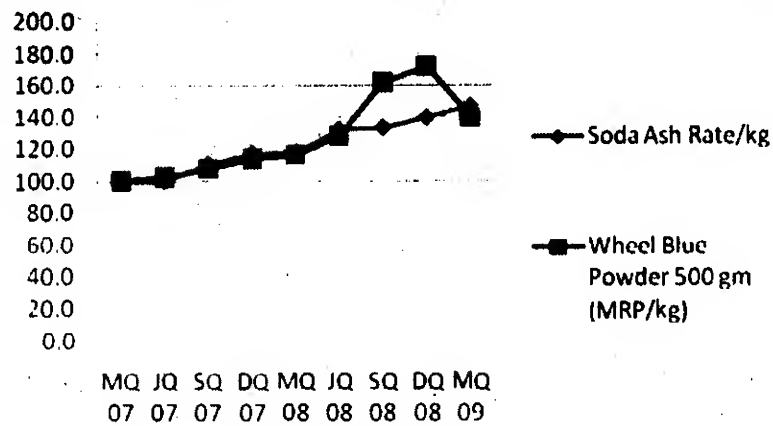
- 10 to the petition shows demand in the Indian market and “market share in demand”. This table shows there has in fact been an approximately 3% rise in the sales of the applicants from 2006-07 to April-September 2008. In fact with the decrease in demand during the reference period, the increase of domestic sales clearly cannot be a factor of market disruption. Data for sales in the preliminary findings shows a modest fall in sales over the same period of time.
87. There has been fall in international prices due to reduction in raw material prices. However the prices of the applicants have not fallen.
88. The WTO Agreement on Safeguards and the Rules do not even mention the word “price”, let alone consider the implications of low prices on the domestic markets. Safeguard duty is only imposed on imports when there is a surge in the imports which result in certain negative consequences for the domestic industry. There is no discussion of price undercutting or price underselling with respect to safeguards. Thus all the information with respect to foreign and domestic prices should be disregarded, as it should not have any bearing on decision to impose a safeguards duty. However, world prices of soda ash have fallen over the last few months. This fall in prices has been mainly due to the fall of the prices in the inputs that go into making soda ash. Thus while there has been a sizeable fall in international prices the domestic industry has failed to reduce its prices. This probably because the applicants have long term contracts for inputs at higher prices than those for the same inputs in the spot market.
89. No fall in Capacity Utilization: The applicants have claimed that there is a fall in their capacity utilization. However a perusal of Annexure 5 of the petition reveals that there has not been any dramatic decline in capacity utilization from April 2006 to September 2008. Also the decline in capacity utilization from 2005-06 to 2006-07 can be explained by the increase in total capacity by the domestic industry without a commensurate expansion in production rather than a dramatic fall in sales or production.
90. Employment and Profit and Losses: The petition provides no data with regard to the employment loss by the applicants, but surprisingly the Director General has in its finding under Table 9 come to a finding on this aspect that there has been a decline in employment. As regards the profitability is concerned, without referring to the half baked information provided in the petition it is our submission that as a matter of fact that the largest producer Tata Chemicals 3rd Quarter profits were up by 106% to Rs. 3495 crores. Similarly GHCL's Quarterly results show that revenue for 9 months was up by 20% whereas profits for 9 months were up by 36%. Thus it can be seen that there is clearly no causal link between the imports and the market disruption claim.
91. No Causal Link: The Applicants do not even qualify to show that there is clearly a causal link between the increased imports and market disruption for the reasons that there is clearly no surge in imports as demonstrated above as well as there is nothing to show on records that either the operations of the Applicants have suffered any market disruption.

- If there were any signs of market disruption during the reference period, there would not be any outbound investments made to increase their international presence.
92. As has been shown above none of the conditions for imposition of safeguard duty is satisfied. The claim for threat has to be real and imminent to justify the critical circumstances under which the said duty can be imposed. Therefore there can be no case for market disruption or threat of market disruption.
93. Calculation of duty: The applicants have asked for the imposition of a 55% safeguard duty on imports of soda ash from China, which is clearly beyond the bound rate of 40% as per India's WTO commitments. However the applicant fails to provide any reasons or calculations or the methodology followed to recommend this duty. Similarly the Director General too has failed to provide reasons for a 31% duty on imports of soda ash from China.
94. Public interest: A safeguard duty on soda ash would be detrimental to public interest. As an industrial user we use soda ash extensively in the manufacture detergents, cakes and saccharine. Soda ash is also important in the float glass industry, in bulk drugs and various industrial chemicals. A duty on soda ash would result in the rise in the prices of several basic commodities and medicines. As such the implications are to the wider Indian citizenry, rather than a limited number of industries.
95. Regarding the impact of provisional safeguard duty the Soda Ash provisional duty was implemented only on 20 April 2009; while the burden of duties would impact the end product i.e. detergents but at this stage considering the short period of time, the industry is unable to quantify the full extent of the impact of the rise in soda ash prices. As results are announced only on quarterly basis for a listed company like the Importer the effect of the revised price is yet to be ascertained. The importer is therefore unable to provide any documentary evidence showing impact of the soda ash prices post provisional duty on detergent prices. Since the impact of higher soda ash prices post provisional duty is yet to be felt industry is unable to produce evidence showing the effects of higher prices on our profit margins. Further, the attention of the Director General is drawn to the fact that during price negotiations with all domestic soda ash players for second half of 2009, the initial offers given by soda ash domestic players were at parity to the IPP (Import parity pricing) benchmarked prices which included the impact of safeguard duty. This can be simply linked to the fact that the domestic suppliers have artificially increased their prices due to the provisional duty in place now. . However, the past data which clearly shows a strong correlation between MRP/kg of Wheel detergent and cost of soda ash is as below.

96.



97.



98. Conclusion: In light of the above the Importer submitted that the period of investigation should be defined as "April-December 2008"; There should be transparent and reliable data which is the basis for any analysis. There has been no surge in imports during the period of investigation; The Petitioners have not suffered from market disruption because

alleged surge in imports; and Imposition of safeguard duty would against Public Interest. For the reasons stated above, the petition for imposition of safeguard duties should be disregarded and these proceedings should be terminated forthwith.

The All India Glass Manufacturer' association (AIGMF) and UP glass Manufacturers. Syndicate (UPGMS) has made following submissions.

99. Safeguard investigation not a dispute between parties: The safeguard investigations under the law are to be done with utmost transparency as PUBLIC at large is going to be affected by the results of investigation. The proceedings are more in the nature of investigation in public interest for the purpose of eliciting information than in the nature of a dispute between the parties. The parties have only a right to offer information and a right to receive information. The doctrine of fair hearing was incorporated in the rules only to take into account the written information and there is no personal hearing as such.
100. Import Increase per se is not bad: Every increase in import or availability of material at lower prices outside India is not bad and should not be discouraged. The supreme court of India in an Anti dumping and Competition Law case in the case of *HARIDAS EXPORTS Versus ALL INDIA FLOAT GLASS MFRS. ASSOCIATION* 2002 (145) E.L.T. 241 (S.C.) has emphasized the benefits of availability of material at lower prices outside the country in following words. "*The availability of goods outside India at prices lower than those which are indigenously produced would encourage competition amongst the Indian industry and would not per se result in eliminating the competitor, as was sought to be submitted by the respondents.*"
101. The imposition of a safeguard measure under the provisions contained in the China's WTO Accession Protocol/WTO Agreement as well as under Section 8C of the Customs Tariff Act 1975 and the Customs Tariff (Transitional Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 (hereinafter the "the Rules") is an extraordinary emergency action/measure which should be invoked in extra ordinary circumstances. The WTO Appellate Body in the case of *United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea*, WT/DS202/AB/R, adopted 8 March 2002, DSR 2002:IV, 1403, in para 80 has held that "*it is useful to recall that safeguard measures are extraordinary remedies to be taken only in emergency situations.*"
102. The domestic soda Ash prices are unreasonably high: The Soda ash prices of Domestic manufacturers which went to 16000 in August 2008 from 9142 per Mt in March 2007 and even today it is around 14900 ex-factory, has not recorded any major decline. The basic raw material lime and salt are abundantly available in domestic market as admitted on page 3 of application. The prices of basic raw material have not changed much. The other input is energy which has become cheaper as a result of crash of petroleum prices. Thus, to say that the domestic industry is imperiled on account of price competition from

- increased imports from China is contradictory. On the contrary, this explains the alleged increase in imports of Soda Ash as consumers are forced to look for cheaper avenues to meet their demand.
103. Chinese prices on the one hand are actually on higher side compared to other countries and on the other hand in volume terms Chinese imports are on lower side as seen from application submitted by domestic Industry. Therefore no material injury can be caused by Chinese import if it cannot be caused by import from other countries.
 104. The cost of production in the case of export sales are lower, by amount of DEPB/Drawback benefits, compared to domestic sales. The current DEPB/drawback benefits are a maximum of 2%. Therefore from a business perspective the difference in ex-factory realization in case of export sales and domestic sales should not be more than 2%. An examination of sale prices of domestic producers will show that domestic producers are selling Soda Ash at USD 160-170 per MT FOB and therefore their factory gate realization is below USD 150 (below Rs 7500 per MT) because in the case of exports they are passing the benefit of reduced input cost to customers. No safeguard duty can be imposed to cross subsidize their exports. They must give us a treatment if not better then at least equal to what they are giving to overseas buyers.
 105. It is not permissible under law to expand the period of investigation by submitting data at the time of public hearing and is also unfair on the part of domestic Industry to surprise everybody by submitting extra data.
 106. Public Interest: Soda ash is like onion, used in a wide range of industries affecting the product costing of a large number of consumer items. In fact in August 2008 Government was contemplating a ban on export of Soda Ash to check rising prices as reported in ET dated 2/8/2008.
 107. Soda Ash is input to a large number of industries. If the raw material cost goes up the prices will also go up and the product shall not be able to compete with imported products. The result will be the import of value added product like glass instead of an intermediate like Soda Ash. If we are not able to sell our products, the Soda Ash manufacturers will lose market in India. Therefore the imposition of safeguard duty on Soda Ash is self defeating and against public interest as
 108. It will lead to closure of glass industry and consequently cause damage to Soda Ash industry itself, unemployment of people and heavy burden on consumers down the line.
 109. It will make India a net importer of value added products like glass instead of importing raw material like Soda Ash.
 110. The domestic producers are already enjoying a basic tariff protection of 7.5% and sea freight protection of another 15% at least when compared to imported Soda Ash. Therefore any extra protection shall give undue advantage to domestic producers.
 111. It may be noted that Nirma Ltd. which is one of the key petitioners and one of the largest producers of Soda Ash goes for captive consumption of soda ash for its detergent

business. Similarly, information available in the public domain also suggests that Tata Chemicals Ltd. is also in the process of foraying into the detergent powder business. The levy of safeguard duty is likely to unfairly benefit these producers at the cost of disadvantaging other producers of detergent powder.

112. The preliminary findings are just interim exparte findings and final findings should not be influenced by preliminary findings. In all the judicial proceedings interims orders do not play any role while arriving at final conclusions. The interim findings are non est for final findings.
113. The preliminary findings have been approved by BOS based on a confidential communication contrary to the legal provisions and a subsequent disclosure of non confidential version of this document shall not make the proceedings legal. The whole idea of making the recommendations public is to give an opportunity to interested party to offer their comments and represent to Government against acceptance of this recommendation. Based on a post acceptance disclosure of the proposal no representation can be made.
114. The imposition of provisional duty vide notification dated 20.4.2009, after conduct of public hearing on 23.3.2009 is also against the provisions of law. Rule 9 provides imposition of duty in critical circumstances that too when investigation is pending. Once the investigation is complete no provisional duty can be imposed. However in the present case the investigation was complete, hearing was over, all parties made their submission, yet duty was imposed based on ex-parte preliminary finding.
115. In view of above submissions, the application filed by Petitioners for imposition of safeguard duty is not maintainable. Therefore the Hon'ble Director General (Safeguards) is requested to terminate the investigation initiated Vide F No. D-22011/02/09 dated 16th January 2009 for imposition of Safeguard Duty on soda ash with a finding that there is no case for imposition of safeguard duty.

The representatives of I-Glass (formerly known as All India Flat Glass Manufacturers' Association - AIFGMA), Saint-Gobain Glass India Ltd. (SGGI) and Asahi India Glass Ltd. (AIG) have made the following submissions:

116. The principles of natural justice have been seriously compromised while issuing the Preliminary Findings as would be apparent from the following:
 - i. DG (Safeguards) had provided time till 16.2.2009 to all the interested parties to make their views known. The preliminary findings have been issued without even waiting for the date which was prescribed by the DG (Safeguards) himself for receiving comments/inputs from the interested parties.

- ii. Copies of the application and notice was not even sent to several users even though the complainant Domestic Industry is fully aware of their existence as the former entities are buyers of the latter.
 - iii. In most cases, where the notices were sent, copies of the application of the Domestic Industry were not enclosed.
 - iv. No effort was made to procure the comments and inputs of the user industry or the other interested parties.
117. The plain reading of the application as well as the initiation notification would reveal that the preconditions of Rule 5 have not been fulfilled at all and thus the initiation of investigation is bad in law.
118. It has been stated in the application as well as the Preliminary Findings that there has been an increase in the imports to such an extent that it has caused disruption of the domestic market in India. With respect, it is submitted that a marginal increase for a short period of two months cannot by any stretch of imagination be considered as increased imports leading to market disruption.
119. It is well-known that prices of Soda ash were increased by the Domestic Industry during May 2007 to November 2008 by a whopping 70-75%. Later, despite substantial reductions in the major inputs, the Domestic Industry reduced the prices by a token Rs 400 per ton, i.e. about 2.4%. The reduction of a meager 2.4% drop in prices was not in line with the level of reduction in the input costs. Obviously, the reluctance of the Domestic Industry to correct its prices and adjust to the new realities must have forced some of the importers to import essentially to remain competitive in their own markets
120. It is apparent that the application by the Domestic Industry as well as the preliminary findings is based on factually incorrect premise and a jugglery of numbers compared over non-comparable periods.
121. While it is true that any investigating authority, be it anti-dumping or safeguard, must take into account the latest period for which credible data is available for examination, it does not imply that the POI can be changed at will. All that such a principle implies is that at the time of initiating the investigation, the Authorities should take into account the period for which figures or data is available. This does not give the DG the authority to change the period as it would lead to chaos and a mockery of the due process of law.
122. Production of Soda Ash for the Domestic Industry has, in fact, increased from an average weekly production of 40,879MT per week to as high as 55971MT if compared over a comparable period. In fact, this appears to be an all time high average as on 31st December, 2008.
123. Average domestic sales have increased significantly and reached a new crest at 39,101 MT which again is the highest average sales recorded during the period when market disruption has been claimed to have been caused.

124. The average weekly capacity utilization has touched almost 100%, an all time highest as on 31st December, 2008. This has risen from 73.84% as on 31.3.2008 to 99.99% during the period of investigation.
125. As regards the claim of drop in profitability, it can be seen that the claimed fall in profitability is also for a period ending September 2008 which is prior to the alleged increased imports and the alleged market disruption. Therefore, the profitability analysis is of no consequence.
126. It can be seen from the above that there is no injury to the Domestic Industry on the above factors if the analysis is done in a fair and scientific manner and the comparison is done for the period ending 31.12.2008.
127. In this context, it is important to note that it is an admitted fact that soda ash is imported as “dense” as well as “light”. It is also an admitted fact that “dense” and “light” soda ash cannot be used interchangeably. Yet the Domestic Industry has mixed up the two products simply to confuse the DG. It may also be mentioned that there is a considerable price difference between the “dense” and “light” soda ash which is apparent from the analysis of the import statistics. Therefore, all the arguments with regard to the price issues would not be ipso facto applicable for both the “dense” and “light” soda ash as has been made out by the Domestic Industry.
128. It was mentioned by the Domestic Industry that the prices from China to India and to other countries are different, the prices to other countries being significantly higher. In this context, it is submitted that there is no legal basis to form price as a basis for seeking imposition of safeguard duties.
129. It was argued at length that the Domestic Industry has been also suffering on account of the fact that their plant is located far away from the consumption centers in Saurashtra region due to proximity of raw material. In this context, we submit that the issue raised by the Domestic Industry has nothing to do with safeguard duties inasmuch as such issues can be addressed separately to the government possibly for freight subsidy. The inherent disadvantage on account of location factors cannot be a basis for imposition of safeguard duties.
130. It was also argued vehemently that China provides export subsidy to the extent of 9%. We submit that this argument is yet again flawed for the reasons explained above. The answer to an export subsidy is contained in the Agreement on Subsidies & Countervailing Measures and not under TPSSM.
131. The Preliminary findings recommend a percentage of 31% as safeguard duty for the product under consideration. The Central Government has, however, decided to impose duty to the extent of 20% which itself is very high considering the fact the Domestic Industry is making huge profits and no valid case of specific safeguard duties has been made out.

132. It is further submitted that imposition of safeguard duties on such flimsy grounds would result into a colossal blow on the entire glass industry which is already reeling under pressure due to overall global slowdown.

M/s Gujarat Guardian Ltd. ("GGL") has made following submissions through his representatives:

133. There are serious deficiencies in the petition filed by AMAI which undermine the very basis of this investigation. The Petitioners have made blatantly misleading, false and incorrect statements in their petition in an attempt to deceive the Hon'ble DG Safeguards and establish market disruption, threat of market disruption as well as causal link as a result of some alleged increase in imports when in fact the Petitioners have only gone from strength to strength and any marginal changes in its position are entirely on account of factors unrelated to volume of imports.
134. The Accession Protocol lays down a scheme whereby the affected Member enters into consultations with China and provides China with an opportunity to remedy the market disruption if any. It is only if the consultations do not yield results that the affected Member is allowed to levy measures. However in this matter, it is apparent that these procedures were completely circumvented not only in violation of India's obligation to China under the Accession Protocol but also in violation of principles of natural justice.
135. Accuracy and Adequacy of evidence was not examined before initiation of investigation. It should be noted that the information provided by the domestic industry should be in the form of evidence and not mere allegations unsupported by any data as in this case. It is submitted that it is necessary that Accuracy and Adequacy of evidence was not examined. The data provided is deficient in the sense that (i) Certain significant information has not been provided in the petition which should have been provided and (ii) An investigation has been initiated despite the serious inconsistencies in data provided by the Petitioner.
136. Data provided by the Domestic Industry is Inaccurate and Misleading
137. Volume of imports from China and Other Countries is inaccurate:
138. There is mismatch in Production figures.
139. Entire data is not submitted and only the selected data is submitted.
140. The cost of production data is misleading.
141. Basis for comparison of import price and of the domestic realization is frivolous and baseless. The comparison of data has been done with reference to Inconsistent periods
142. It can be seen that though the Hon'ble DG Safeguards had allowed a time of 30 days to file responses in the safeguards investigations still the preliminary findings, the Notification was issued within 15 days from the date of issue of the initiation notification. It is submitted that the said conduct of the Hon'ble DG Safeguards is against the well established principles of natural justice.

143. The market disruption is said to occur when the evidence on record establishes the following:
 - i. Imports should increase rapidly
 - ii. Material injury is caused to the domestic industry
 - iii. Such rapidly increasing imports are a major or significant cause of the material injury
 - iv. Factors such as volume of imports, effect of imports on prices and effect of imports on domestic industry should be considered in totality to determine if there is market disruption.
144. Gujarat Guardian has analyzed the threat of injury parameters on the basis of the data provided by the domestic industry. This is without prejudice to the claim that the data itself is not reliable or that the domestic industry should have provided annualized data during POI. At the risk of reiteration it is further stated that the Petitioners should have established that the threat of material injury and thus market disruption was imminent and foreseeable. This is all the more relevant given that the Petitioners were seeking preliminary measures on the basis of "critical circumstances". The Petitioners have failed to establish "threat" or provide any evidence giving rise to such allegedly "critical circumstances" so as to warrant preliminary duties.
145. It should be noted that the requirement is not a mere showing of "increase" in imports but a showing of "rapid increase" in imports. Thus it is incumbent upon the Petitioners to show not only an increase but that such increase has been rapid or in quick succession. However despite this clear legal obligation, the Petitioners have failed to establish that imports from China of soda ash have increased rapidly.
146. The total imports from China have increased marginally, i.e. 0.08% during April-September 2008 when compared to the import data for previous year. Further, if we consider the import data from Chinese Customs then it is evident that imports increased by just 0.03% in comparison to the imports during the previous year
147. In addition to rapidly increasing imports, the domestic industry has to prove "market disruption" by establishing that the domestic industry's share in the market has gone down and such decrease in the share of the domestic market are solely due to rapidly increased imports. However, a look at the figures provided in the petition show that there is no fall in the share of the domestic industry, rather the domestic industry's share has increased during POI and the increase in share of imports is nominal.
148. It has been strenuously argued by the Petitioners that the said fall in production is due to surged imports. It should be noted right at the outset that though there has been a marginal fall in production, there has been an increase in sales during the POI. Thus both sales and market share of the domestic industry have shown a rise in the POI.
149. Without prejudice, assuming the data furnished by the Petitioner in Annexure 9 of the petition is accurate, this data clearly shows that the domestic industry has undertaken a

serious exercise to increase capacity at its plants. Clearly an increase in the installed capacity of the domestic industry shows that the exercise is undertaken only because the company foresees imminent increase in domestic sales of Soda Ash.

150. In the present case the domestic industry has not made any reference to the productivity of the industry.
151. As per the Petitioner the domestic industry has suffered losses due to surge in imports. However, the Petitioners have not shown the basis on which the profit / loss has been calculated by them. It is submitted that the domestic industry should reveal the basis on which the profit / losses have been calculated by them, i.e. whether on a Profit Before Interest and Tax (PBIT) basis or on an Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) basis.
152. The domestic industry has not provided data regarding employment in the petition filed by them for levy of product-specific safeguards duty. Not providing vital information to the interested parties has seriously jeopardized the ability of the interested parties' to contest the veracity of these figures.
153. It is further submitted that as per Annexure 2 of the petition, CIF import price of imports from China are higher than CIF value of imports from other countries except during the period 2007-08 where no threat of market disruption has been claimed.
154. While calculating the cost of production for domestic sales and arriving at the Non-Injurious Price, domestic industry has assumed a fixed Return on Capital Employed (ROCE) @22%. Accordingly, domestic industry has tried to show that since the ROCE was not 22% it is indicative of market disruption to the domestic industry. However, it is submitted that a fixed return of 22% on ROCE is not the position of law as stated in the Safeguard Rules. ROCE is different for different industries and for different products. Therefore, assuming a fixed ROCE of 22% is incorrect in law and should not be a basis for arriving at the conclusion of market disruption. It has also been held in the case of *Indian Spinners' Association vs. DA* that the DGAD should not assume a fixed ROCE of 22% and should always arrive at the correct ROCE figures keeping in mind the type of industry.
155. The Petitioners have also failed to establish a causal link between the alleged "rapid increase" in imports and threat of market disruption as alleged by them. It is submitted that no causal link exists between imports and domestic like products
156. In conclusion Gujarat Guardian again reiterates its request to terminate this investigation on account of serious deficiencies in data, lack of any evidence of market disruption or threat of market disruption and a causal link between the alleged imports and alleged market disruption.

Other Submissions:

157. Various other interested parties have also made detailed submissions through written submissions and also during the two public hearings. Summary of these are as follows:

158. Some of the parties made similar submissions as mentioned above.
159. There is no increase in import as the difference sources of data have been used. Further, it is not appropriate to use China Customs data.
160. The increase in import, if any is on account of inability of domestic producers to reduce their price.
161. There is no injury to the domestic industry. All these companies are very big and are earning good profit.
162. The imposition of safeguard duty is not in the public interest as these are input to various products consumed by a large number of consumers. Imposition of safeguard duty will increase the price of soda ash, which in turn would lead to increase in prices of final products affecting the consumer interests.
163. The domestic industries are adopting monopolistic practices.
164. Therefore, no safeguard duty should be imposed.

EXAMINATION AND FINDINGS

165. The section 8C(1) empowers the Central Government to impose a safeguard duty on the article if the article is being imported into India from the Peoples Republic of China, in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause market disruption to domestic industry.
166. The Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 provides the manner and principles governing investigation. Accordingly, the investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

Reasons of Investigation under Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 for imposition of Safeguard duty on imports from China.

167. The import figures from China and other than China (Table 2, Table 3 and Table 4) shows that imports of Soda Ash from China have increased after October, 2008 while imports from other countries have shown a declining trend. Therefore, the safeguard investigation under Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 for imposition of Safeguard duty on imports from China has been conducted.

What is the product under Investigation?

168. **Product under Investigation:** The product under investigation is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It has been referred as "Soda Ash" in this order. Soda Ash is classifiable under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff

Act, 1975. Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The domestic industry produces both types of Soda Ash and the imports are also of both types. The difference in the two types is bulk density. Chemically both types of Soda Ash are same. There is no significant difference between the imported dense soda ash from China and domestically produced dense soda ash in terms of physical or chemical characteristics. Further, there is also no significant difference between imported light soda ash and domestically produced light soda ash in terms of physical or chemical characteristics. The imported soda ash and domestic soda ash have similar or identical sales channel. The sales of both are done through direct sale to end users, distributors or retail. These products have common uses and are commercially interchangeable. Price information is readily available and the products concerned and the products of the domestic producers compete mainly on price. Therefore, the imported soda ash is 'like or directly competitive' to the domestically produced soda ash.

Which are the domestic producers who constitute 'Domestic Industry' for the purpose of Safeguard Investigation?

169. Section 8C(7)(a) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

- (b) "Domestic industry" means the producers –
- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India;
 - ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

170. The important domestic producers in India who manufacture Soda Ash are following:

- i. Tata Chemicals Ltd,
- ii. Gujarat Heavy Chemicals Limited,
- iii. Saurashtra Chemicals Limited,
- iv. DCW Limited,
- v. Nirma Limited and
- vi. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited.

171. The shares of these producers are as mentioned in the Table I below. The following producers have requested to be considered as 'domestic industry'.

- i. M/s Tata Chemicals Ltd. Andheri (East), Mumbai,
- ii. M/s Gujarat Heavy Chemicals Limited, Noida,
- iii. M/s Saurashtra Chemicals Limited, Birla Sagar, Porbandar, Gujarat,
- iv. M./s DCW Ltd, Nariman Point , Mumbai and
- v. M/s Nirma Ltd., Bhavnagar, Gujarat.

Table-1

Share of individual producers in total production of India					
	Name of unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	DCW Ltd.	3.81%	3.80%	3.90%	3.91%
2	GHCL Ltd.	23.35%	24.70%	28.37%	29.49%
3	Nirma Ltd.	22.95%	21.66%	17.21%	18.31%
4	Saurashtra Chemicals Ltd.	10.64%	6.57%	13.26%	11.51%
5	Tata Chemicals Ltd.	35.37%	39.17%	37.27%	36.78%
6	Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%
	GRAND TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Share of Indian Producers who support the petition	96.11%	95.91%	100.00%	100.00%
	Share of other Indian Producers	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%

172. It is found that their production of Soda Ash accounts for 100% of total Indian domestic production in 2008-09. As the Collective output of the above mentioned producers constitute 100% of the total production of Soda Ash in India and there is no contention by any of the interested parties that these producers do not constitute domestic industry, the above mentioned domestic producers constitute the 'domestic industry' within the meaning of 'domestic industry' defined under Sec 8C (7) of the Customs Tariff Act, 1975.

What is the Period of Investigation?

173. The Customs Tariff Act, 1975, the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, the Agreement on Safeguard or the relevant Article XIX of GATT does not specifically define what the Period of Investigation should be. However, the issue of period of investigation has been dealt extensively in the panel's report on Argentina Footwear as well as Appellate Body Report on Argentina Footwear, which are being produced below;

"Argentina—safeguard measures on imports of Footwear; Report of the Panel

8.216 *Regarding the investigation's almost exclusive reliance on end-point-to-end-point comparisons in its analysis of the changes in the situation of the industry, we have the same concerns as were noted above with regard to the "increased imports" analysis. Here we note in particular that if intervening trends are not systematically considered and factored into the analysis, the competent authorities are not fulfilling Article 4.2(a)'s requirement to analyse "all relevant factors", and in addition, the situation of the domestic industry is not ascertained in full. For example, the situation of an industry whose production drops drastically in one year, but then recovers steadily thereafter, although to a level still somewhat below the starting level, arguably would be quite different from the situation of an industry whose production drops continuously over an extended period. An end-point-to-end-point analysis might be quite similar in the two cases, whereas consideration of the year-to-year changes and trends might lead to entirely opposite conclusions.*

We believe that consideration of changes over the course of the investigation period in the various injury factors is indispensable for determining whether an industry is seriously injured or imminently threatened with serious injury. An end-point-to-end-point comparison, without consideration of intervening trends, is very unlikely to provide a full evaluation of all relevant factors as required

Appellate Body Report

Note 130:

The Panel, in footnote 530 to para. 8.166 of the Panel Report, recognizes that the present tense is being used, which it states "would seem to indicate that, whatever the starting-point of an investigation period, it has to end no later than the very recent past." (emphasis added) Here, we disagree with the Panel. We believe that the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past.

174. From the above it is apparent that neither the Agreement on Safeguard nor the relevant provisions of WTO provide specific definition or interpretation of the period of investigation. The Appellate Body Report has given its finding in unequivocal terms that the relevant investigation period should not only end in the very recent past; the investigation period should be the recent past. Therefore, the period after filing of the application cannot be ignored in safeguard investigation. However, in order to meet the

requirement of natural justice, it is imperative that the information received or collected after initiation of investigation is accessible to the interested parties.

175. In the instant case, the investigation was initiated on 16th January, 2009 and preliminary findings were issued on 30th January, 2009. The provisional safeguard duty was imposed on 20th April, 2009. It has been contended by the applicants that the unprecedented recession has led to increase in import. The increase in imports took place from the month of December, 2008. The imports increased in the Q4 of 2008-09. Therefore, the Q4 of 2008-09 has been considered for determination of market disruption or threat of market disruption. The information relating to the period April, 2006 to December 2008 has also been considered for comparison and trend study. Provisional Safeguard duty was imposed on 20th April 2009. Therefore, the period after March 2009 has also been considered.

Methodology and Source of information

176. For the purpose of import data reliance has been placed on DGCIS figures up to FY 2007-08 and IBIS for the subsequent period. The transaction wise details of the information have been kept in the public file. The other economic parameters relating to all manufacturers of India have been sourced from the Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) and individual units. If any other information is used the source is mentioned with the information.
177. As the initiation of investigation was done in the middle of the year, the annual information may not be a very recent information. Therefore, for the purpose of analysis, quarterly figures as well as monthly figures have been used for analysis. In order to obviate effects of seasonal variation, if any, the comparison has been made with corresponding period of preceding years. In order to conduct trend analysis, actual monthly figures have been considered, so that sample size is reasonably large.
178. Further, while conducting analysis of economic factors for the determination of market disruption or threat of market disruption trend analysis using polynomial of order 2 and order 3 has been conducted.

Is there an increase in import?

179. **Increased Imports:** The table below gives the Quarterly import figures relating to Soda Ash. The month wise imports are placed as Annexure I

Table 2

Soda Ash Imports from China Quantity (In MT)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	17,836	2,256	10,046	1,10,329
Q2	19,112	6,362	10,716	-
Q3	7,929	21,268	20,261	-
Q4	16	7,804	67,624	-

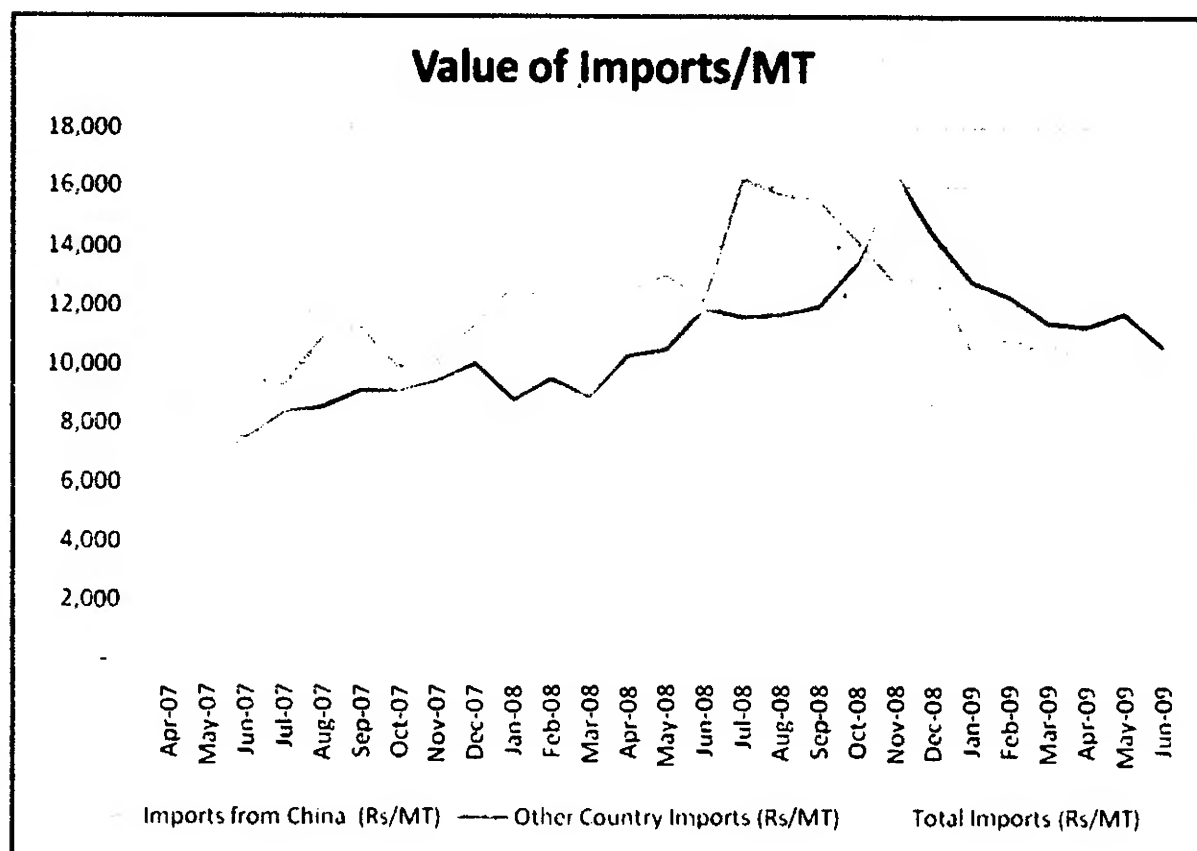
Table 3

Soda Ash Imports from Other Than China Quantity (In MT)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	58,923	49,666	50,333	41,195
Q2	62,139	63,236	55,566	-
Q3	56,241	1,13,356	42,825	-
Q4	35,326	90,233	33,778	-

Table 4

Total Soda Ash Imports into India Quantity (In MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	30,166	76,759	51,922	60,379	1,51,523
Q2	44,637	81,251	69,598	66,282	-
Q3	38,733	64,170	1,34,623	63,086	-
Q4	38,280	35,342	98,037	1,01,402	-

Graph 1



180. The increase in import from China took place in the month of December 2008. The import in December 2008 was 15,946 MT from China against imports of 4004MT in December 2007. The graph above shows month wise imports from China.
181. The import from China in Q4 of 2008-09 was 67624MT against imports of 7804MT in Q4 of 2007-08. The import from China in Q1 of 2009-10 was 110329 MT against imports of 10046MT in Q1 of 2008-09. The total import in India in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 were 101402 MT and 1515123 MT against 98037 MT and 60379 MT in respective quarters of previous year. This shows 8.66 times increase in imports from China in Q4 of 2008-09 and 10.98 times increase in Q1 of 2009-10. This increase in imports from China led to overall increase in imports into India even though imports from countries fell during the same period. The total increase in imports in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 was 3.4% and 151% respectively. This implies the imports from China increased rapidly from December 2008. The increase in imports continued even after imposition of safeguard duty at the rate of 20% w.e.f 20.4.2009.

182. **Relative increase in imports:** The share of imports in the total market size of India has been as follows:

Table 5

Year		Market Share (%)		
		China	Domestic Producers	Others
2005-06	Q1	0.01	94.19	5.81
	Q2	0.91	91.91	7.18
	Q3	0	92.68	7.32
	Q4	0.72	93.11	6.17
2006-07	Q1	3.07	86.80	10.14
	Q2	3.63	84.58	11.79
	Q3	1.46	88.16	10.38
	Q4	0.00	93.76	6.24
2007-08	Q1	0.42	90.30	9.28
	Q2	1.34	85.35	13.31
	Q3	3.36	78.75	17.89
	Q4	1.27	84.01	14.72
2008-09	Q1	1.82	89.07	9.11
	Q2	2.00	87.61	10.39
	Q3	4.05	87.38	8.57
	Q4	11.62	82.57	5.80
2009-10	Q1	17.74	75.63	6.62

183. The market share of China in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 was 11.62% and 17.74% respectively compared to 1.27% and 1.82% in their respective quarters in previous years. Therefore, the imports from China increased in relative terms too.

Under what conditions import from China taking place?

184. The Annexure 1 contains average value of imports/month and the graph 1 above contains graphical representation of value/MT of imports from China and other countries. Further the table below contains the quarterly average value of import.

Table 6

Import Prices – China (Rs./MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	37,817	8,503	9,184	12,559	10,008
Q2	8,765	8,492	10,540	15,721	
Q3	-	8,824	10,300	13,221	
Q4	8,794	44,446	12,393	10,649	

185. The value of imports per MT decreased in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 to 10649 Rs/MT and 10008 respectively from 12393 Rs/MT and 12559 Rs/MT in their respective quarters. Further there is a fall in import value/MT in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 compared to immediately preceding quarter i.e Q3 of 2008-09. Therefore, the increase in imports from China is at lower value.

What are the reasons of increased import from China?

186. The unprecedented and uneven recession, which started in mid 2008 led to slow down in many nations. The effect of recession has been different in different countries. The general slowdown on account of recession caused fall in demand both in domestic as well as export market of China, leading to surplus available capacity in China. In order to deal with such situations, the unconventional market was explored by China. India has not been a conventional market of China as is apparent from the quantity of imports into India from China, which was very small till September, 2008. However, after recession

affected the world economy Indian market became important for China, which is apparent from the increased imports from China at lower value. Traditionally, imports from China to India have been at higher value than value of imports from other country but the situation reversed in the third quarter of 2008-09. As seen from the graph 1, the import prices of China suddenly came down even when price of imports from other countries had the upward trend. This sudden fall in price reversed the trend of imports of soda ash. On account of sudden reduction in price by China, the imports from China grew rapidly and China became the main importer of Soda ash to India. The import from China remains at lower price than other countries.

187. The export trend from China to various other countries (graph 2) also shows that India has become very important market for China. This change in focus of producers of Soda Ash in China has caused increased imports. These factors causing increased imports from China are unexpected.

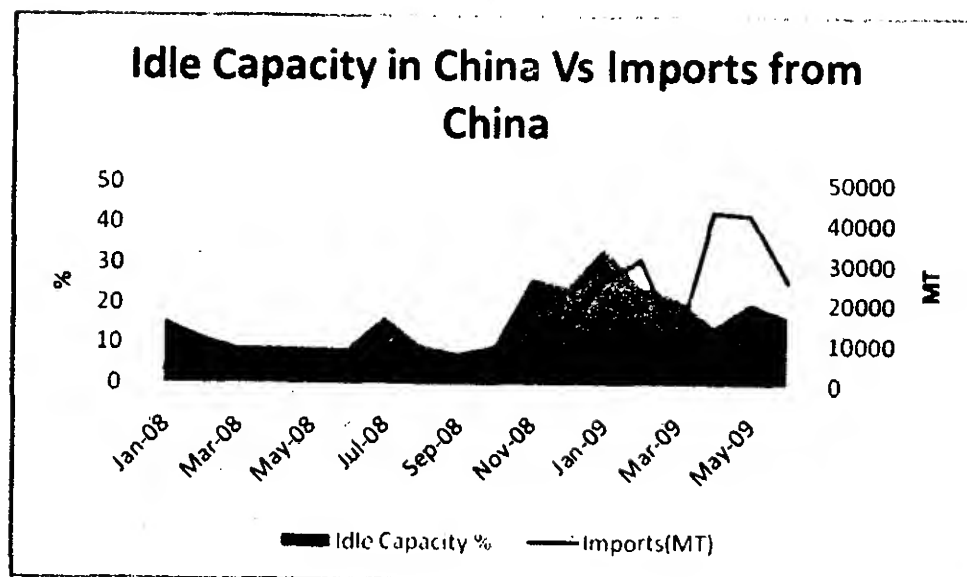
Table : 7
Surplus Capacity in China

Month	Idle Capacity
Jan-08	16.00%
Feb-08	12.00%
Mar-08	9.00%
Apr-08	9.00%
May-08	9.00%
Jun-08	9.00%
Jul-08	17.00%
Aug-08	10.00%
Sep-08	8.00%
Oct-08	10.00%
Nov-08	27.00%
Dec-08	25.00%
Jan-09	35.00%

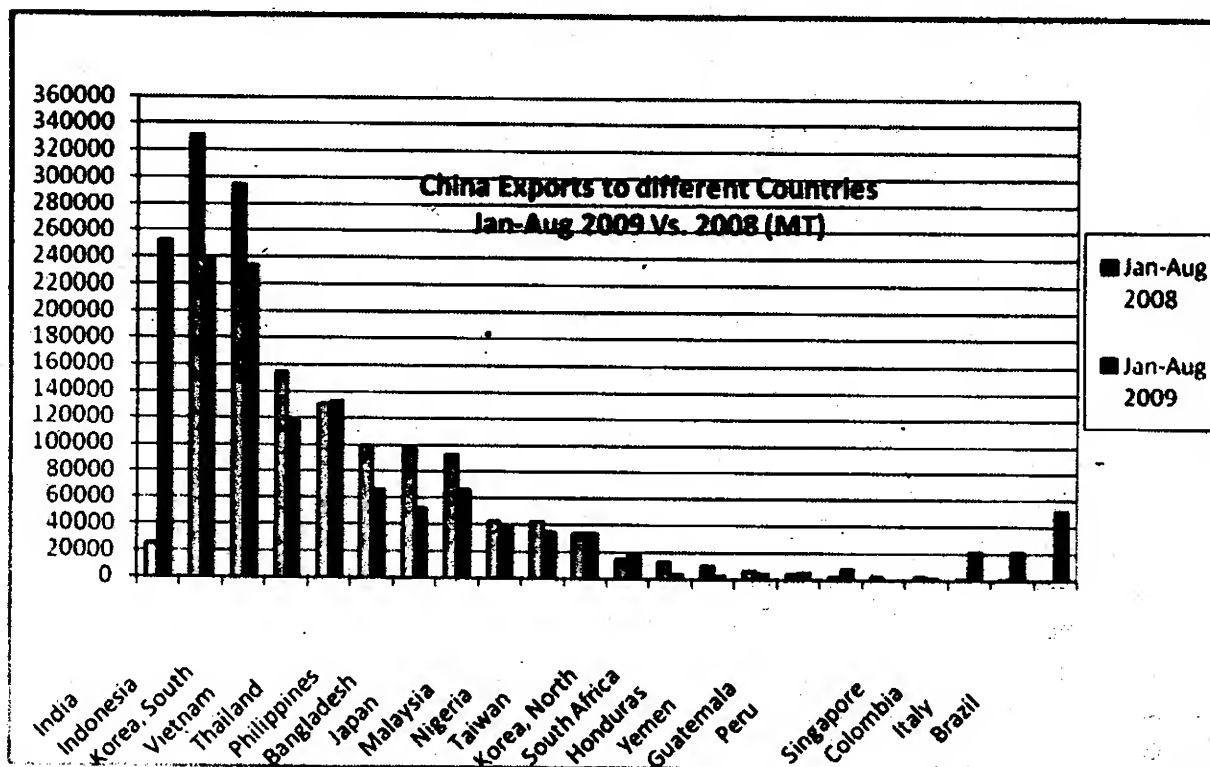
Feb-09	25.00%
Mar-09	22.00%
Apr-09	15.00%
May-09	21.00%
Jun-09	17.00%
Jul-09	21.00%
Aug-09	20.90%

[Source: Harriman Chemsult Ltd. , CMAI Reports,
National Bureau of Statistics China]

Graph 2



Graph 3
Exports by China to India and Other Countries



As seen from the graph above, the export to India by China increased ten times from 25 Thousand MT to 252 Thousand MT during January to August, 2009 compared to the same period in 2008. This increase in export to India has been in the back drop of decrease in export to Indonesia, South Korea, Vietnam and Philippines, which have been the traditional market of producers of Soda Ash in China.

Evaluation of evidences relating to Threat of Market Disruption:

Statutory framework:

188. The Section 8C (7)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 explains that 'market disruption' shall be caused whenever imports of a like or a directly competitive article produced by the domestic industry, increase rapidly, either absolutely or relatively, so as to be a significant cause of material injury, or threat of material injury to the domestic industry. It also defines 'threat of market disruption' to mean a clear and imminent danger of market disruption.
189. However the definition of 'material injury' is not found either in the Act or Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002. Therefore, the practice followed in past investigations by the Directorate and laws and practices of other countries were studied. It was noted that the law of USA relating to safeguard duty

against imports of China provides definition of 'material injury'. The term 'material injury' appears in Section 406 of the Trade Act, 1974 of USA and Title VII of the Tariff Act, 1930 of USA. Title VII of the Tariff Act of 1930 defines 'material injury' to mean "harm which is not inconsequential, immaterial, or unimportant".

190. It is also noted that the market disruption test is intended to be more easily met than the serious injury tests. The term material injury represents a lesser degree of injury than the term 'serious injury'.
191. Accordingly, it is found appropriate, in analyzing market disruption or threat of market disruption to consider all factors as mentioned in the rules and other factors which are relevant for determination of market disruption or threat of market disruption, especially export capacity in the country of origin or export, as it stands or is likely to be in the foreseeable future and the likelihood that the capacity will be used to export to India and to what extent India is focused for exports by China. No single factor has been considered as dispositive and all relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition that are relevant to the affected industry has been considered. The determination of market disruption or threat of market disruption is based on evaluation of overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry.

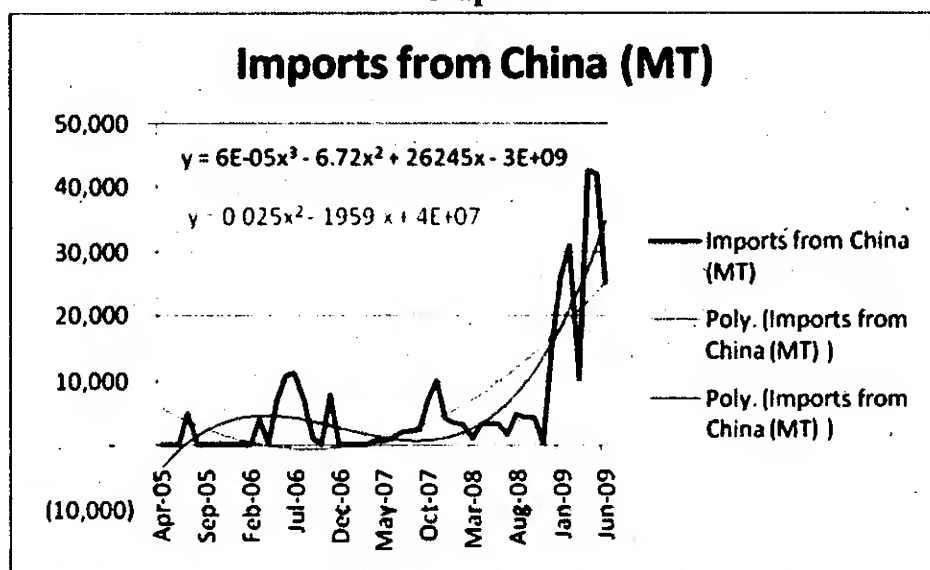
Identification of relevant factors:

192. In order to identify the relevant factors, the practice adopted by various member nations for safeguard investigation and the factors having bearing on the performance of Soda Ash industry was studied. The Annex to Rule 8 mentions following factors for determination of existence of market disruption or threat of market disruption;
 - i. Rate of increase of imports
 - ii. Share of the domestic market taken by increased imports
 - iii. Change in level of sales
 - iv. Production
 - v. productivity
 - vi. Capacity utilization
 - vii. Profits & losses
 - viii. Employment
193. All the factors as mentioned in the rules have been adopted for evaluation. Besides these factors, certain factors were also considered relevant for the instant case. These are
 - i. Export capacity in the country of origin or export, as it stands or is likely to be in the foreseeable future and the likelihood that the capacity will be used to export to India.
 - ii. India as focus to Exports by China

iii. inventory

194. **Rate of increase of imports:** In order to assess the rate of increase of imports trend of imports since April 2005 has been studied by drawing trend lines of polynomials of order 2 and order 3. The trend is as shown in the chart below. The trend lines show that the rate of increase in imports is substantial. It is also noticed that the growth in imports is accelerated one since October 2008. In other words the rate of increase in imports itself is growing.

Graph 4



195. **Share of domestic market taken by increased imports from China:** The table and graph below gives information about market share of domestic industry:

Table 8

Quarter	Market Share (%)		
	China	Domestic Producers	Others
05-06Q1	0.01	94.19	5.81
05-06Q2	0.91	91.91	7.18
05-06Q3	-	92.68	7.32
05-06Q4	0.72	93.11	6.17

06-07Q1	3.07	86.80	10.14
06-07Q2	3.63	84.58	11.79
06-07Q3	1.46	88.16	10.38
06-07Q4	0.00	93.76	6.24
07-08Q1	0.42	90.30	9.28
07-08Q2	1.34	85.35	13.31
07-08Q3	3.36	78.75	17.89
07-08Q4	1.27	84.01	14.72
08-09Q1	1.82	89.07	9.11
08-09Q2	2.00	87.61	10.39
08-09Q3	4.05	87.38	8.57
08-09Q4	11.62	82.57	5.80
09-10Q1	17.74	75.63	6.62

196. The market share of domestic industries is falling from Q3 of 2008-09. The market share of domestic industries fell in Q4 of 2008-09 to 82.57% from 84.01% in Q4 of 2007-08. This fall in market share continued in Q1 of 2009-10 when it fell to 75.63% from 89.07% in corresponding quarter from previous year. The down ward trend in Q3 and Q4 of 08-09 and Q1 of 2009-10 is in contrast with the upward trend in Q3 and Q4 of 07-08 and Q1 of 2008-09. The market share in Q1 of 2009-10 is the minimum in the entire period starting from 2005-06 even after imposition of safeguard duty at the rate of 20% advalorem w.e.f 20th April 2009. It is also noticed that share of imports from other countries has also fallen and thus the share of domestic industry has been taken by imports from China.

197. **Change in level of Sales:** The table below gives quarter wise sales by domestic industry.

Table 9

Quarters	Sales (MT)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	4,88,794	5,04,532	4,83,558	4,92,142	4,70,319
Q2	5,07,359	4,45,663	4,05,514	4,68,751	
Q3	4,90,616	4,77,618	4,98,893	4,36,845	
Q4	5,17,577	5,31,127	5,14,964	4,80,476	

Table 9A

Sales (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
July	1,72,221	1,49,000	1,54,029	1,66,172	1,50,528
August	1,60,070	1,46,524	1,22,933	1,60,381	1,31,586

198. The Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 witnessed fall 6.7% and 4.43% fall compared to Q4 of 2007-08 and Q1 of 2008-09 respectively. The Q4 of 2008-09 was the period when imposition of provisional duty was recommended and Q1 of 2008-09 is the period when provisional safeguard duty was imposed. In spite of imposition of safeguard duty in Q1 of 2009-10, the sales decreased as compared to same quarter of previous year. The falling trend of sales continued in July and August, 2009. The lower sales of soda ash by domestic industry in Q4 2008-09 and Q1 2009-10 when compared to corresponding quarter of previous year is in contrast to higher sales in Q2 and Q1 of 2008-09 compared to Q2 and Q1 of 2007-08. The trend analysis of monthly sales shows negative trend after January 2009.
199. Therefore, it is noted that there is fall in sales even after imposition of safeguard duty at the rate of 20% w.e.f 20th April, 2009. This fall in sales has been in the backdrop of growing market size and decreasing imports from countries other than China. The fall in sales coincide with increase in import from China. Thus, the fall in sales is on account of increased imports from China.
200. **Production:** The tables below gives gross production by domestic industry as well as production reduced by production exported (production net of exports) quarter wise. The

production net of exports has been analyzed to study the effect of exports in production as well as trend of production meant for domestic consumption.

Table: 10

Gross Production (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5,65,853	5,15,924	5,32,360	5,12,342	5,34,576
Q2	5,68,648	4,87,595	4,25,305	5,11,118	
Q3	6,07,843	5,40,916	5,51,124	5,42,399	
Q4	5,49,985	5,79,708	5,76,499	5,28,162	

Table 11

Production Net of Exports (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5,08,720	4,88,405	4,94,992	4,83,482	4,79,999
Q2	5,19,054	4,57,960	4,08,555	4,78,414	
Q3	5,37,702	4,83,958	5,20,302	5,04,626	
Q4	4,80,705	5,24,963	5,23,591	4,68,523	

Table 10A

Gross Production (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
July	1,89,678	1,60,644	1,59,520	1,76,042	1,52,989
Aug	1,90,952	1,61,811	1,26,703	1,74,905	1,62,539

Table 11A

Production Net of Export (Gross production –Exports)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
July	1,75,212	1,55,571	1,56,742	1,68,272	1,29,131
Aug	1,70,147	1,49,967	1,18,056	1,65,386	1,49,329

201. The production in Q4 of 2008-09 is down by 8.38% if compared with corresponding quarter of previous year. The production in Q4 of 2008-09 is the minimum in Q4 of any year starting from 2005-06. The production in Q1 of 2009-10 is higher than that of 2008-09, but in the month of July and August 2009 the production saw decline by 13.09 % and 7.07% compared to same month of previous year. The comparison of production in January-August 2009 shows a decline by 61522MT i.e 4.3%. It is also noted that the safeguard duty was imposed in Q1 of 2009-10. It is also noted that when reduction in production was noticed, the import was found to have increased.
202. The production net of exports shows that decrease in production meant for domestic consumption in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 by 10.52% and 0.72% respectively, even after imposition of safeguard duty in Q1 of 2009-10. The down ward trend continued in the month of July and August 2009. The fall in July and August 2009 is 23.26% and 9.70% respectively compared to same months of previous years. The analysis of production net of exports shows that the production in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 is the least in their respective quarters.
203. Therefore, it is noted that the production meant for domestic consumption has fallen down. The total gross production during January to August has also fallen. This fall in production is in spite of imposition of safeguard duty at the rate of 20% w.e.f 20th April, 2009. During the period when production has fallen the import increased. The fall in production is on account of fall in sales caused by increased imports. Thus, the fall in sales is attributable to increased imports from China.
204. **Capacity utilization:** The table below gives information about capacity and capacity utilization of domestic

Table 12

Installed capacity

Quarter	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	6,75,250	5,94,675	6,57,175	7,19,674	7,19,674
Q2	6,75,250	6,00,758	5,36,505	7,19,674	
Q3	6,75,250	6,80,175	6,35,508	7,19,674	
Q4	6,18,292	6,81,133	7,19,674	7,19,674	

Table 13

Capacity Utilisation					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	84	87	81	71	74
Q2	84	81	79	71	
Q3	90	80	87	75	
Q4	89	85	80	73	

Table 13A

Capacity Utilisation					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
July	84.27	81.04	83.09	73.38	63.77
Aug	84.84	81.63	77.23	72.91	67.76

205. The tables above show that Q4 of 2008-09 has the least capacity utilization in their respective quarters since 2005-06. The capacity utilization improved in Q1 of 2009-10. This improvement in capacity utilization was partly on account of improved exports and partly on account of increase in inventory. Further, the safeguard duty was also imposed on 20th April, 2009, which falls in the same quarter. However, the improvement in capacity utilization was temporary in nature. In the month of July and August 2009, however, there was a fall in capacity utilization below 70% mark, which is the minimum

in the entire period of consideration. As a result, the capacity utilization during January to August 2009 has fallen to 71.8% from 75% during the same period in 2008. The monthly trend analysis of capacity utilization shows negative trend post December 2008, when increased imports were noticed.

206. Hence, it is seen that the capacity utilization has gone down. The fall in capacity utilization is attributable largely to increased imports.
207. **Inventory:** The Tables below give information about inventory available with domestic industry.

Table 14

Inventory					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	37,282	26,465	35,822	33,667	81,115
Q2	42,936	39,955	32,061	37,874	
Q3	77,857	44,459	46,997	99,910	
Q4	40,530	28,576	48,891	75,741	

Table 15

Inventory					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
July	36,961	37,743	36,473	33,263	58,093
Aug	45,264	39,930	29,318	37,201	76,809

208. The analysis of table above shows that inventory in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 are the maximum in their respective quarters. The inventory in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 grew by 51% and 141% compared to the respective quarters of previous years. The stocks per day of sale in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 are also the maximum in their respective quarters. Similar trend is also observed in July and August 2009.

209. Therefore, it is noted that the inventory was higher post December 2008, when imports have been increasing. The increase in inventory is on account of fall in sales even when there is a capability to produce.

210. **Profitability:** The table below gives profit and loss per month.

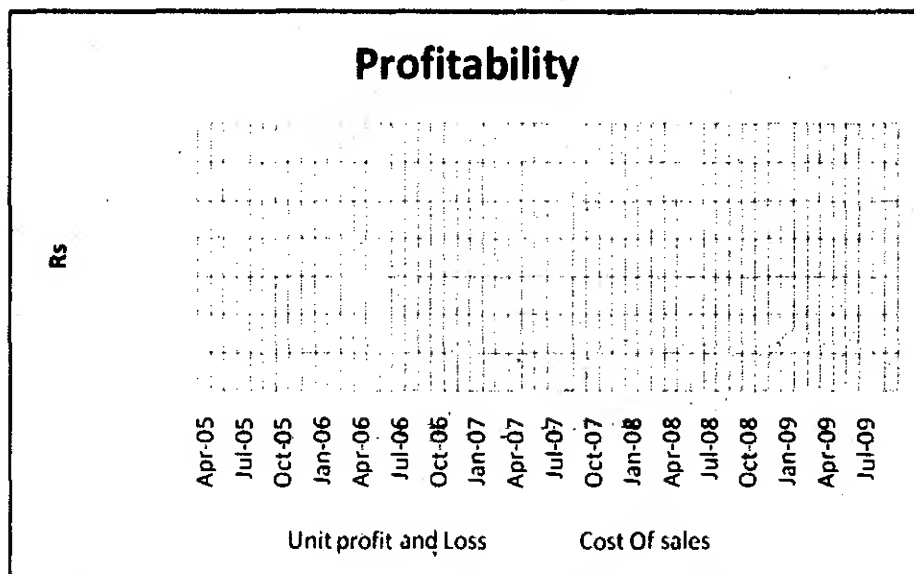
Table 16

Profits and loss (Rs/ MT) (Indexed)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	100	190	127	209	211
Q2	97	163	34	180	
Q3	136	163	191	165	
Q4	178	152	244	264	

Profit and loss (Rs/MT) (Indexed)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
July	93	200	47	201	147
Aug	97	207	15	189	135

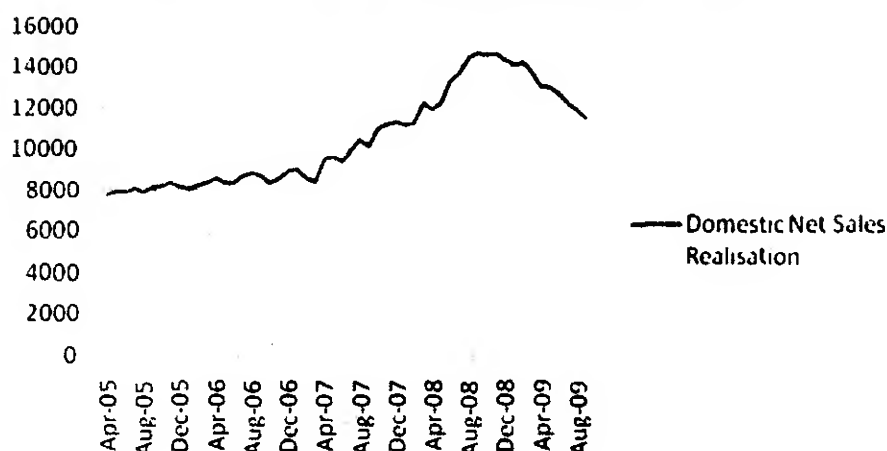
211. The analysis of profits and loss per MT shows that the domestic industry had growth in profit(Rs./MT) from Q3 of 2007-08 to Q2 of 2008-09, but it declined in Q3 of 2008-09. The profit improved in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 by 8.2% and 0.6% respectively (when the recommendation for provisional safeguard duty was made and imposed). However the profitability fell by 26.7% and 28.8% in July and August 2009.

Graph5



212. The analysis of cost of sales and unit profit/loss through their monthly figures plotted as line graph shows that increase in cost of sales led to loss in unit profits and vice versa in general till January 2009. It means that the increase in cost is absorbed to some extent by the industry and the entire decrease in cost is not passed to the consumer. This is the general trend as analyzed from April 2005. However the latest trend shows that there is decrease in unit profit and loss, even when, cost of sales has gone down. It implies that the benefit of cost reduction is being passed on in greater proportion than what has been done in the past. It is also important to note that the demand in India is growing, which has natural effect of improvement in sales realization and consequently better profitability. This effect of growth in demand on profitability has been largely neutralized by increased imports causing increased supply in India. The increased import has been more than the increase in demand, which caused pressure on prices, as shown below in the graph.

Domestic Net Sales Realisation



213. **Employment:** The table below shows number of employees employed by domestic industries. The graph below represents number of employees on monthly basis.

Table: 17

Employment					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	11,629	8,893	10,641	10,996	10,693
Q2	11,436	10,222	10,488	10,897	
Q3	11,721	10,981	10,944	10,979	
Q4	8,999	10,977	10,741	10,867	

214. There is an increase in number of employees by 0.3% in Q3 of 2008-09, 1.1% increase in Q4 of 2008-09 and 2.7% decrease in Q1 of 2009-10. The monthly analysis shows range bound movement in number of employees. Therefore, it is noted that the employment has no bearing on the position of industry more so when retrenchment of employees is normally not possible in short duration.
215. **Productivity:** The productivity in terms of production per employees is as follows:

Table 18

Productivity Per employee (MT/employee)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	49	58	50	47	50
Q2	50	48	41	47	
Q3	52	49	50	49	
Q4	61	58	54	49	

216. The productivity of employee has gone down in Q4 of 2008-09 and gone up in Q1 of 2009-10. However, the productivity remains range bound and there is no bearing of productivity on determination of market disruption or threat of market disruption.
217. **Export capacity in China, as it stands or is likely to be in the foreseeable future, and the likelihood that the capacity will be used to export to India:** The table below gives idle capacity in China.

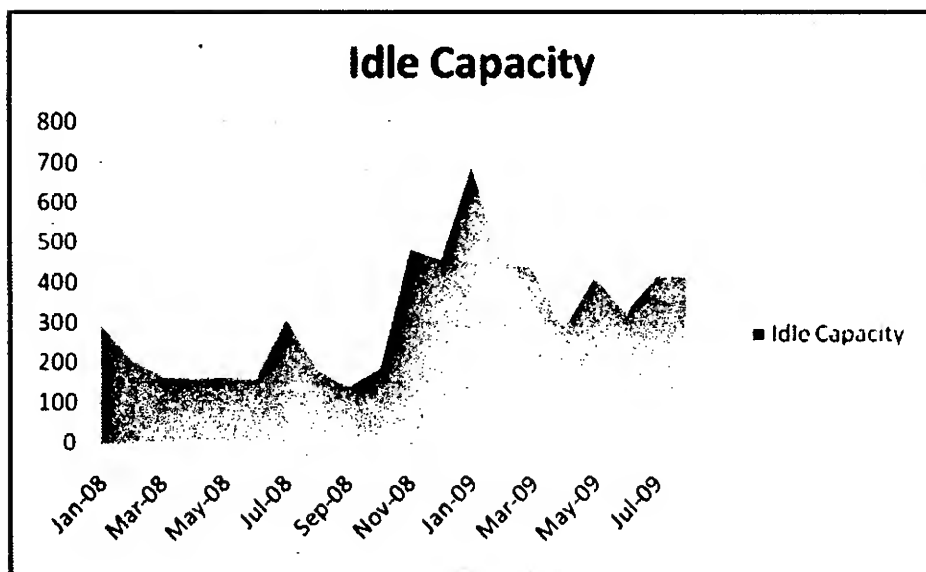
Table 19

Month	Idle Capacity (000MT)
Jan-08	294.82
Feb-08	207.56
Mar-08	166.26
Apr-08	160.85
May-08	165.93
Jun-08	160.2
Jul-08	311.16

Aug-08	183.9
Sep-08	141.64
Oct-08	183.87
Nov-08	482.97
Dec-08	458.67
Jan-09	696.39
Feb-09	448.3
Mar-09	437.91
Apr-09	291.72
May-09	418.33
Jun-09	329.7
Jul-09	418.43
Aug-09	416.53

[Source: Harriman chemsult]

Graph 6



218. The information on surplus capacity shows that surplus capacity in China increased from November 2008. The surplus capacity of China was in the tune of 2 Lac MT/month prior to November 2008, which increased to an average of 4.4 Lac MT/Month from November 2008 to August, 2009. This increase in idle capacity of China by 2.4 Lac MT/month has potential to be used for exports. It may be noted that the market size of India is about 2Lac MT/month. Further the exports to their traditional market viz, South Korea, Indonesia, Philippines, Bangladesh and Japan have reduced. The average monthly fall in export by China to these countries during January to August has been in the tune of 36000 MT per month. On account of reduction in exports to the traditional market and available idle capacity of soda ash in China, the same has already been used to export it to India.
219. **India as focus to Exports by China:** The table and graph below is about exports from China to various countries including India.

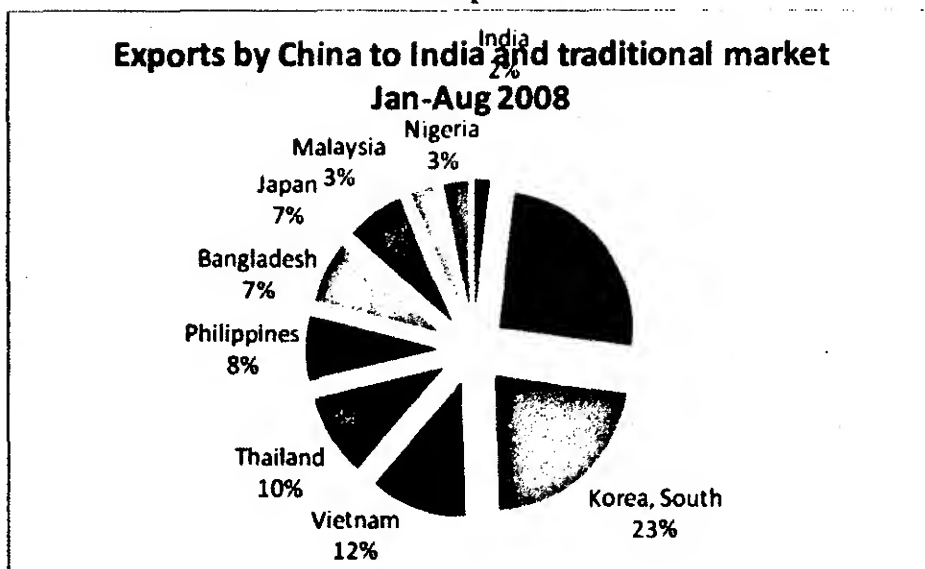
Table 20

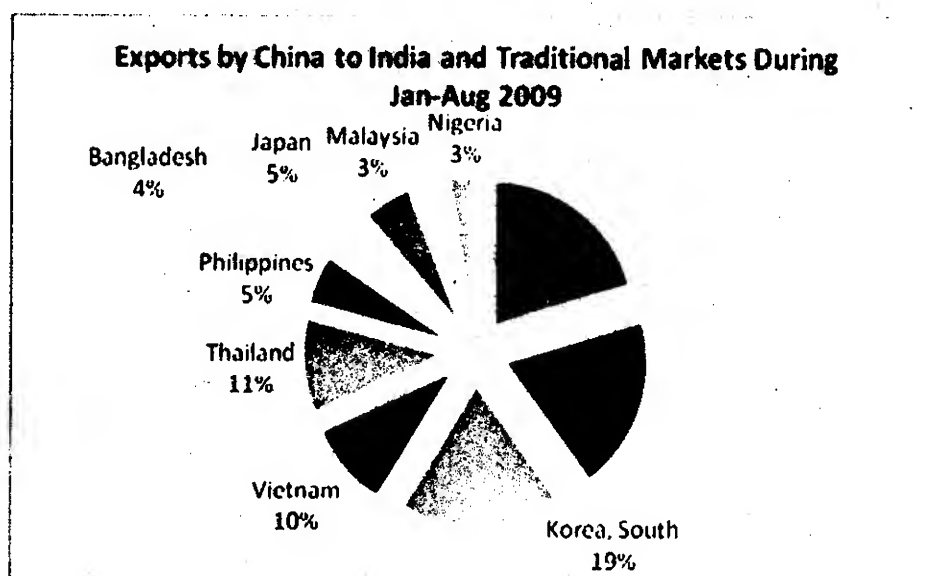
Exports to various countries from China			
Year	World	India	Share of India
2005-06	1,55,318	839	0.54%
2006-07	1,51,788	3,938	2.59%
2007-08	1,43,673	3,814	2.65%
Jan-08	1,47,389	5,282	3.58%
Feb-08	1,43,428	750	0.52%
Mar-08	1,75,850	4,561	2.59%
Apr-08	1,54,902	1,859	1.20%
May-08	2,25,960	2,620	1.16%
Jun-08	1,84,465	1,351	0.73%
Jul-08	2,10,262	3,011	1.43%
Aug-08	2,27,269	5,742	2.53%
Sep-08	1,83,157	7,809	4.26%

Oct-08	1,71,616	5,891	3.43%
Nov-08	1,32,478	1,920	1.45%
Dec-08	1,72,103	41,207	23.94%
Jan-09	1,64,187	28,839	17.56%
Feb-09	2,11,493	31,129	14.72%
Mar-09	2,79,692	47,535	17.00%
Apr-09	2,39,698	45,320	18.91%
May-09	1,70,377	30,402	17.84%
Jun-09	2,15,828	22,889	10.60%
Jul-09	1,81,740	32,475	17.87%

[Source: China Customs]

Graph 7





220. The traditional market of China namely Indonesia, South Korea, Vietnam has seen lower exports from China but exports to India have grown 10 times during January to August 2009. The exports to India during January to August 2009 are more than that to Indonesia, South Korea, and Vietnam who have been their traditional markets. India accounted for 2 to 3% of total exports of Soda Ash from China in 2008 but the scenario changed in 2009 and share of India rose to 16%. This change in focus has made India a focused market for Soda ash manufacturers of China.

Evaluation of overall position:

221. The evaluation of above mentioned parameters shows that there is increase in imports at accelerated rate. The market share of domestic industry has gone down. There is a loss in production, and capacity utilization. There is also increase in idle capacity in China and India has become focused destination of exports by China. Further, the increased imports, reduction in market share, fall in sales, production and capacity utilization continues even after imposition of safeguard duty at the rate of 20th in April 20th, 2009. Therefore, there is a clear and imminent threat of market disruption. The preliminary determination had shown threat of market disruption leading to imposition of safeguard duty. It is also noticed that the threat of market disruption continues to exist.

Other factors:

222. **Exports:** The table below gives quarterly exports by India.

Table 21

Export Sales (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	57,133	27,520	37,368	28,860	54,577
Q2	49,594	29,636	16,750	32,704	
Q3	70,142	56,958	30,821	37,773	
Q4	69,280	54,745	52,908	59,639	

223. The analysis of export figures show that export from India has been increasing during the period Q3 & Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10. Further, the analysis of production figures excluding that for exports above shows decrease in production. Therefore, the export has no bearing on injury.
224. **Demand of Soda Ash in India:** The table below gives the market size in India. The analysis of the demand shows that

Table 22

Market Size [Demand](MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5,18,960	5,81,291	5,35,480	5,52,521	6,21,842
Q2	5,51,996	5,26,914	4,75,112	5,35,033	
Q3	5,29,349	5,41,789	6,33,516	4,99,931	
Q4	5,55,857	5,66,469	6,13,001	5,81,878	

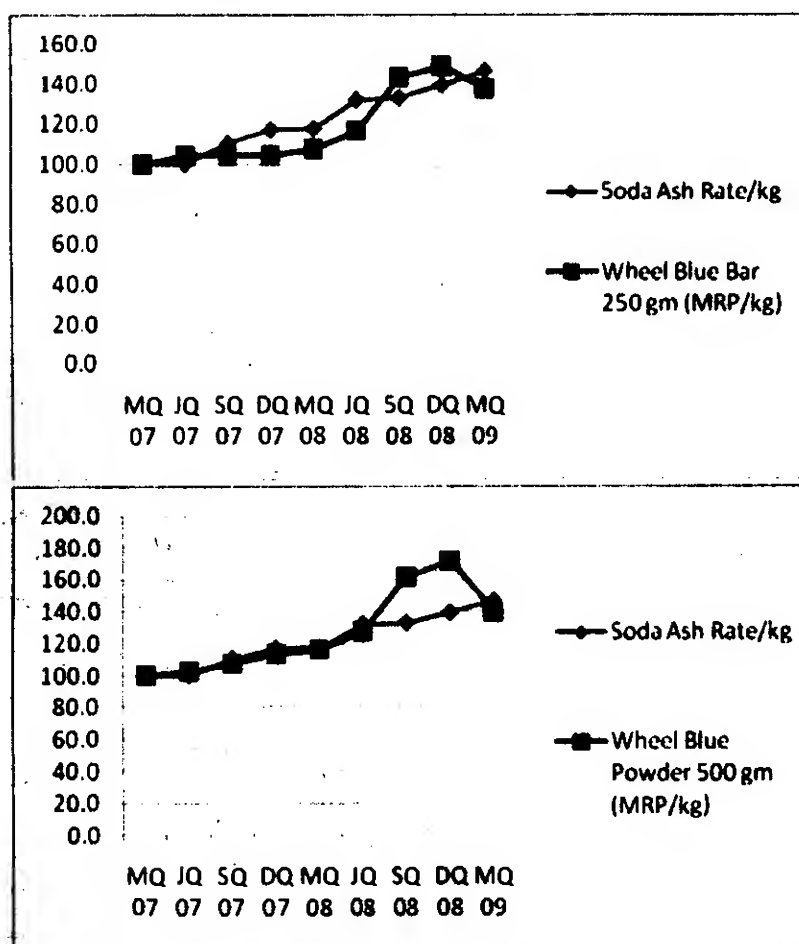
225. The demand in Q1 of 2009-10 increased by 69,321 compared to Q1 of 2008-09 but the domestic sales reduced by 21823 MT. The imports from other countries also reduced by 9138 MT. The increase in imports from China was 100283 MT. This means imports from China not only took away the growth in market size but also took 21823MT of market of domestic industry.
226. **Causal Link:** The analysis of idle capacity in China shows the idle capacity sharply increased in the month of November 2008 and the imports increased from the month of

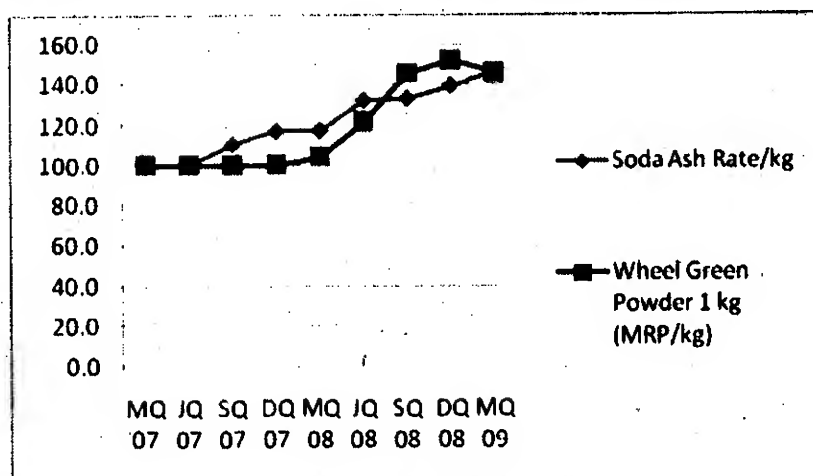
December. Further, the period of slow down of exports by China to their traditional market coincides with the period of increased imports. The market share of domestic industry has gone down significantly on account of increased imports from China, as imports from other countries have not gone up during the same period. The production has gone down and inventories gone up, when imports from China went up. This means it is the import from China, which caused lowering of sales leading to fall in production and rise in inventory. The lowering of production also caused lowered capacity utilization. The analysis of other factors shows that factors other than increased imports did not have noticeable impact on threat of market disruption. Therefore, the increased import is the significant cause of threat of market disruption.

227. **Public Interest:** In an economy there are varying and some time competing interests of different economic players. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impacts may not always be most suitable for all the different economic players when they have competing interests. Therefore interests of various economic player groups have been analyzed based on the available information.
228. The producers of soda ash and importers/end users of soda ash participated in the safeguard investigation. No representative of any consumer association or group participated in the safeguard investigation.
229. In order to analyze the public interest, the economic players have been divided in three categories, viz. producers, importers/end users and ultimate consumer of the final product.
230. In order to conduct impact analysis data relating to price at which goods reach ultimate consumers, information regarding financial impact and views on impact of provisional safeguard duty was called from all interested parties. However, only a very few responded.
231. Detergent industry and glass industry are main users of soda ash who have participated in the safeguard proceedings. Besides these there are large number of industries like Textile Industry, Paper Industry, Metallurgical Industries, Desalination Plants, Water Treatment, Rubber Industry, Leather Industry, Aluminium Industry, Bulk Drugs etc. but there has been no participation of these industries in the safeguard investigation.
232. **Glass Industry:** The float glass industries enjoy anti-dumping protection of US \$133 per MT vide Notification No.4/2009-Customs dated the 6th January, 2009 for the period of five years (i.e up to 5th January, 2014) for imports from Indonesia and China PR. As the float glass industry already enjoys duty protection, the impact of safeguard duty is not likely to have significant impact. Further, no adequate evidence or information has been brought forward by the glass industry showing injurious effect of safeguard duty on soda ash.
233. **Detergent Industry:** The quantum of imports of detergent into India is around four thousand MT at a value more than Rs 100/Kg. The average CIF value of imported

detergent has increased from 54.10Rs/Kg in 2007-08 to Rs. 71.18 per Kg from China and from Rs 96.20 per Kg in 2007-08 to Rs. 104 per Kg in 2008-09. The MRP of most of the detergent brands is well below Rs. 100/Kg. It means the import value, which is well above the prices in the domestic market. The imported detergents do not have price advantage over the domestically produced detergent and thus the domestic producers of detergent do not face significant competition from imports.

234. Impact on consumers of detergent: It is only M/s Hindustan Lever Ltd., who has provided MRPs of their products and their relationship with procurement prices of soda ash. The information has been provided only in respect of one brand as they find the same as representative. In this respect, it is noted that various brands of detergents have different MRPs and they cater to different segment of consumers. The movement of MRP with soda ash procurement price is as follows:





235. The graph above shows that the MRP of detergent has been stagnant in the initial phase of graph even when price of soda ash was rising. In the latter phase when the prices of soda ash fell, the MRP was rising. It shows that price of Soda Ash is not a significant factor which would conclusively determine the MRP of the detergent. Therefore, the imposition of safeguard duty may not have a significant impact on consumers of detergents segment.
236. As discussed above, there are various economic operators in the economy. Their interests are varied and sometimes competing. The impacts of safeguard duty on these economic operators are also different because of their nature. For some, availability of cheaper imported soda ash may be financially rewarding. On the other hand the increased import may disrupt economic operations of others. While determining safeguard duty, interests of various economic operators have been taken into account. The safeguard duty is intended to moderate imports to reduce its injurious effects on the economy. The imposition of provisional safeguard duty at the rate of 20% did not stop the imports. Further, no evidence could be produced by the interested parties, which could show that the safeguard duty has made their industry unviable or that their growth has been unduly scuttled. The provisional safeguard duty might have, at the maximum, neutralized price gains acquired by some through increased imports. However, it is important for public to have a healthy soda ash industry so that there is steady and reliable source of Soda ash in India to feed the downstream user industry. Hence, imposition of safeguard duty is in public interest.

Conclusion and Recommendation

237. On the basis of the above findings it is found that increased imports of Soda Ash from People's Republic of China have threatened to cause market disruption to the domestic industry. In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent

threat of serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of sales at reasonable return on employed capital and average landed cost of import has been considered. Accordingly, safeguard duty at the rate of 20% ad valorem, which is considered to be the minimum required to protect the domestic industry from market disruption, is recommended to be imposed on imports of Soda Ash, falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 for one year from the date of imposition of provisional duty, when imported into India from the People's Republic of China.

238. The preliminary findings recommending provisional safeguard duty on the basis of which a provisional safeguard duty was imposed vide Notification No. 37/ 2009-Customs dated 20th April, 2009 is also confirmed.

[F. No. D-22011/02/09/5423]

PRAVEEN MAHAJAN, Director General (Safeguards)

Annexure 1									
Month wise import data (MT)									
Month	Import Qty (MT)		Total Imports	Import Value			Import Price		
	Imports from China	Other Country Imports		Imports from China	Other Country Imports	Total Imports	Imports from China (Rs/MT)	Other Country Imports (Rs/MT)	Total Imports (Rs/MT)
Apr-05	32	5,169	5,201	12	359	371	37,817	6,945	7,135
May-05	-	12,380	12,380	-	855	855	-	6,907	6,907
Jun-05	-	12,585	12,585	-	866	866	-	6,883	6,883
Jul-05	5,000	14,450	19,450	433	835	1,268	8,664	5,781	6,522
Aug-05	16	13,937	13,953	6	1,067	1,074	40,385	7,658	7,695
Sep-05	-	11,234	11,234	-	826	826	-	7,352	7,352
Oct-05	-	9,433	9,433	-	718	718	-	7,611	7,611
Nov-05	-	17,430	17,430	-	1,422	1,422	-	8,158	8,158
Dec-05	-	11,870	11,870	-	2,612	2,612	-	22,007	22,007
Jan-06	-	18,521	18,521	-	1,403	1,403	-	7,577	7,577
Feb-06	-	7,415	7,415	-	568	568	-	7,660	7,660
Mar-06	4,000	8,345	12,345	352	664	1,016	8,794	7,956	8,228
Apr-06	-	11,482	11,482	-	719	719	-	6,261	6,261
May-06	6,907	20,541	27,448	587	1,595	2,182	8,495	7,766	7,949
Jun-06	10,929	26,901	37,829	930	2,195	3,125	8,508	8,161	8,261
Jul-06	11,304	19,177	30,481	944	1,594	2,538	8,352	8,312	8,327
Aug-06	6,904	20,699	27,603	597	1,770	2,367	8,640	8,552	8,574
Sep-06	904	22,263	23,167	82	1,898	1,981	9,116	8,527	8,550
Oct-06	-	25,260	25,260	-	2,171	2,171	-	8,594	8,594
Nov-06	7,929	20,232	28,161	700	1,702	2,402	8,824	8,412	8,528
Dec-06	-	10,749	10,749	-	853	853	-	7,939	7,939
Jan-07	-	7,984	7,984	-	633	633	-	7,930	7,930
Feb-07	-	13,766	13,766	-	1,090	1,090	-	7,917	7,917
Mar-07	16	13,576	13,592	7	1,079	1,086	44,446	7,947	7,990
Apr-07	632	12,530	13,162	55	1,134	1,188	8,637	9,047	9,027
May-07	600	20,544	21,144	55	1,580	1,635	9,115	7,691	7,731

Jun-07	1,024	16,592	17,618	98	1,250	1,348	9,563	7,532	7,650
Jul-07	1,934	15,894	17,828	181	1,337	1,518	9,336	8,414	8,514
Aug-07	2,174	24,264	26,438	237	2,067	2,304	10,890	8,520	8,715
Sep-07	2,254	23,078	25,332	253	2,101	2,354	11,236	9,103	9,293
Oct-07	7,233	39,286	46,518	717	3,589	4,306	9,915	9,136	9,257
Nov-07	10,032	46,301	56,332	1,017	4,387	5,404	10,139	9,474	9,593
Dec-07	4,004	27,769	31,772	456	2,785	3,241	11,399	10,029	10,202
Jan-08	3,456	40,756	44,212	438	3,575	4,013	12,660	8,772	9,076
Feb-08	3,282	30,772	34,054	398	2,934	3,332	12,119	9,536	9,785
Mar-08	1,066	18,705	19,771	132	1,664	1,796	12,368	8,896	9,083
Apr-08	3,364	23,264	26,647	420	2,398	2,818	12,493	10,298	10,575
May-08	3,373	11,711	15,064	439	1,229	1,669	13,026	10,496	11,062
Jun-08	3,309	15,338	18,648	402	1,825	2,227	12,150	11,899	11,944
Jul-08	1,534	20,548	22,082	250	2,383	2,632	16,269	11,596	11,921
Aug-08	4,864	13,362	18,226	765	1,558	2,323	15,725	11,658	12,744
Sep-08	4,318	21,657	25,975	670	2,587	3,257	15,522	11,947	12,541
Oct-08	4,191	16,126	20,317	595	2,157	2,752	14,196	13,379	13,547
Nov-08	125	6,950	7,075	16	1,144	1,160	12,765	16,459	18,393
Dec-08	15,946	19,748	35,694	2,068	2,646	4,914	12,969	14,410	13,766
Jan-09	26,303	16,811	43,114	2,747	2,153	4,900	10,443	12,809	11,366
Feb-09	31,068	7,141	38,209	3,386	878	4,264	10,898	12,294	11,159
Mar-09	10,253	9,825	20,078	1,069	1,123	2,192	10,424	11,428	10,916
Apr-09	42,780	15,261	58,041	4,459	1,723	6,183	10,423	11,293	10,652
May-09	42,173	10,857	53,030	4,236	1,270	5,506	10,045	11,694	10,382
Jun-09	25,376	15,077	40,452	2,347	1,606	3,952	9,247	10,650	9,770